

माननीय एसपी कुर्दुकर, सीजे और वीके बाली से पहले, जे.
मैसर्स जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड। श्री शाम लाल
गुप्ता और अन्य के माध्यम से, - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, -प्रतिवादी।

1992 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1898।

15 सितंबर 1995.

भारत का संविधान , 1950-अनुच्छेद 226 —हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973— 4 —केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956— एस.एस. 6-ए, 9(2)- केंद्रीय बिक्री कर नियम। 1956- आर.एल. 12(5), फॉर्म 'बी' शाखा स्थानांतरण - माल की बिक्री - मूल्यांकन के खिलाफ याचिका दायर की गई। आरोप लगाने का आदेश

मुख्यमंत्री के खिलाफ दुर्भावना -वैकल्पिक उपाय-कला के तहत याचिका पर रोक लगाने के लिए वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व। 226 सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नहीं है - मामला 3 साल तक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रहा और पार्टियों द्वारा विस्तृत मौखिक और लिखित दलीलें पेश की गईं और इस तथ्य के साथ जोड़ा गया कि कंपनी पर भारी मात्रा में कर लगाया जाना है और इस तरह के कर को जमा करना शर्त है गुण-दोष के आधार पर अपीलों की सुनवाई के बाद, मूल समाधान में परिवर्तन की आपत्ति को -खारिज कर दिया जाता है - सवाल यह है कि क्या शाखा हस्तांतरण अंतरराज्यीय बिक्री है या उसके एजेंटों को माल की बिक्री अंतरराज्यीय बिक्री है, मामला नए निर्णय के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी को भेज दिया गया है - मूल्यांकन आदेश रद्द कर दिया गया है - निष्कर्ष केवल संभावनाओं के आधार पर दुर्भावना को वापस नहीं किया जा सकता।

अभिनिर्धारित, कि जो भी मामला डीबी को स्वीकार करने का कारण रहा होगा, तथ्य यह है कि मामले तीन साल की अवधि के लिए इस न्यायालय के समक्ष लंबित रहे हैं और लगभग छह महीने की अवधि में पक्षों द्वारा

विस्तृत मौखिक और लिखित प्रस्तुतियां दी गई हैं, वास्तविक सुनवाई करीब 15 दिन से हो रही है। इस मामले पर लगातार सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि पक्षकारों के वकील इस मामले पर एक बार में बहस करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, अंतर-राज्यीय बिक्री होने के लिए खेप बिक्री के रूप में शाखा हस्तांतरण को रखने के माध्यम से याचिकाकर्ता कंपनी पर एक बड़ा कर लगाया गया है। हमें बताया जाता है कि लगातार तीन वर्षों की अवधि के लिए लगाया गया कर लगभग बीस करोड़ होगा। यकीनन, कर जमा करना अधिनियम के प्रावधानों के तहत योग्यता के आधार पर अपीलों की सुनवाई के लिए एक शर्त है, चाहे वह राज्य अधिनियम हो या केंद्रीय अधिनियम। हम इस तथ्य के बारे में काफी सचेत हैं कि अपीलीय प्राधिकारी के लिए यह अनुमति है कि वह स्थगन के लिए एक आवेदन का मनोरंजन करे और इसे एनील के लंबित रहने के दौरान प्रदान करे लेकिन हम इस तथ्य के बारे में समान रूप से सचेत हैं कि बहुमत में इस तरह के स्थगन को मंजूरी नहीं दी जाती है और यदि दी जाती है, वही सशर्त है।

(पैरा 27)

इसके अलावा, यह माना गया कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ताओं के लिए एक वैकल्पिक मूल उपाय उपलब्ध है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है।

(पैरा 28)

इसके अलावा, आकलन प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि शाखा हस्तांतरण की अनुमति नहीं थी और माल को देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित याचिकाकर्ताओं की विभिन्न शाखाओं में भेजा गया था। क्या वह हिसार कार्यालय में ओएनएलवी का उपयोग कर सकता है, ऐसा न करने पर इसे अंतरराज्यीय बिक्री के रूप में माना जाएगा, यह कानून की जांच में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। फैसले के पहले भाग में केंद्रीय अधिनियम के काल्पनिक पी?वीडब्ल्यू और नियम 12एफएल) को पुनः प्रस्तुत किया गया है। न तो धारा 8 के नियम, न ही नियम 12 के नियम, न ही फॉर्म 'बी' में भर्ती प्रमाणपत्र के प्रावधान और न ही फॉर्म 'सी' में दी गई घोषणा से पता चलता है कि प्रश्न में आने वाले सामान का उपयोग टाइन विनिर्माण या प्रक्रिया में किया जाना चाहिए। किसी विशेष राज्य में बिक्री के लिए माल की। कानून के अनुसार, कल्पना की दृष्टि से यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता कंपनी ने पंजीकरण प्रमाणपत्र का दुरुपयोग किया है।

(पैरा 36)

इसके अलावा, धारा 3 का खंड (ख) लागू नहीं है क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में उनके स्थानांतरण के दौरान स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से कोई बिक्री नहीं हुई थी।

(पैरा 37)

इसके अलावा, यह माना जाता है कि जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में चला गया है, तो केंद्रीय अधिनियम की धारा 3 (क) के तहत एक सवाल उठता है कि क्या माल की ऐसी आवाजाही अंतर-राज्य व्यापार के दौरान बिक्री के कारण हुई थी। या वाणिज्य और यदि ऐसा हुआ है, तो केंद्रीय अधिनियम के तहत एक दायित्व उत्पन्न होगा। यदि नहीं, तो ऐसी देनदारी संभवतः उत्पन्न हो सकती है। हम विद्वान वकील के इस तर्क से भी सहमत हैं कि जहां माल के हस्तांतरण का दावा बिक्री के अलावा किसी अन्य तरीके से किया जाता है, तो सबूत का बोझ डीलर द्वारा उन्मोचित किया जाएगा यदि उसने निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन प्राधिकारी को

प्रस्तुत कर दिया है। या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जब वह प्राधिकारी, पर्याप्त कारण के लिए, व्यवसाय के अन्य कार्यालय के प्रमुख अधिकारी या उसके एजेंट या प्रिंसिपल द्वारा विधिवत भरी और हस्ताक्षरित एक घोषणा की अनुमति दे, जैसा भी मामला हो, जिसमें निर्धारित विवरण शामिल हों, निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में, ऐसे माल के प्रेषण के साक्ष्य के साथ, लेकिन इस तरह के बोझ को, टीकेएस न्यायालय के विचार में, मूल्यांकन प्राधिकारी को, उप-धारा के तहत परिकल्पित की गई जांच पर छुट्टी दे दी जाती है। धारा 6-ए की उप-धारा (2) के तहत की गई जांच में इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया है कि डीलर व्यापारी उप-धारा (1) द्वारा प्रस्तुत विवरण केंद्रीय अधिनियम के तहत कोई कर देयता उत्पन्न नहीं होने की तुलना में सही हैं।

(पैरा 38)

इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि केंद्रीय अधिनियम की धारा आर-ए के प्रावधानों के तहत जांच करने के लिए आकलन प्राधिकरण अपने अधिकारों के भीतर अच्छी तरह से होता। यह अच्छी तरह से अपने अधिकारों के भीतर फिर से मूल्यांकनकर्ता को सभी घोषणा पत्र प्रस्तुत करने और उसमें की गई प्रविष्टियों की जांच करने के लिए कहने के लिए होता और अगर यह गलत या असंगत

पाया गया या कुछ ओवर-लैपरिव था। मूल्यांकनकर्ता को यह साबित करने का और मौका दिया जाना चाहिए था कि घोषणा प्रपत्रों के माध्यम से भेजे गए सामान वास्तव में एजेंटों को खेप थे, न कि अंतर-राज्यीय बिक्री। ऐसा कुछ भी नहीं था। तथापि, किया गया और उन आधारों पर आदेश पारित किए गए जो टीबी के प्रावधानों के तहत विचारित जांच के लिए स्थायी नहीं थे? केंद्रीय अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम।

(पैरा 38)

याचिकाकर्ता के लिए शांति भूषण, अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश बिंदल, जायनी और अधिवक्ता ए. के. मित्तल के साथ.

एच. एल. सिब्बल, एजी हरियाणा और अरुण नेहरा, एडीशनल एजी हरियाणा ने प्रतिवादियों के लिए।

निर्णय

वी. के. बाली, जे.

(1) मेसर्स जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, जो भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, 1992 की अलग-अलग तीन रिट याचिकाओं संख्या 1898 और 5864 और 1993 की 5404 के माध्यम से, केंद्रीय बिक्री कर के तहत किए गए मूल्यांकन आदेशों पर कड़ी आपत्ति जताती है। निर्धारण वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लिए अधिनियम, 1956 (इसके बाद इसे केंद्रीय अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। जबकि, 1992 के सीडब्ल्यूपी नंबर 1898 में प्रार्थना कारण बताओ नोटिस, अनुलग्नक पी-101 (दिनांक 10 दिसंबर, 1991) और पी-194, दिनांक 17 दिसंबर, 1991 को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट जारी करने की है। उत्तरदाताओं 2 और 4 द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश, अनुलग्नक पी-194, दिनांक 18 दिसंबर, 1991, रिट याचिकाओं 1992 की 5864 और 1993 की 5404 में प्रार्थना, कारण बताओ नोटिस को रद्द करने के लिए है, अनुलग्नक पी-690, दिनांक 22 अप्रैल, 1992 और मूल्यांकन आदेश, अनुलग्नक पी-715, दिनांक 1 मई, 1992, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित किया गया। उत्पाद एवं करायान आयुक्त-ईम-आकलन प्राधिकरण और आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी-29, दिनांक 18 फरवरी, 1993 और मांग नोटिस, अनुलग्नक पी-30, दिनांक 18 फरवरी 1993, क्रमशः अवैध और मनमाना है। हम इस सामान्य निर्णय द्वारा तीनों रिट याचिकाओं का निपटारा करने का प्रस्ताव करते हैं क्योंकि सभी मामलों में कानून और तथ्य के समान प्रश्न शामिल हैं। हालाँकि, अनावश्यक शब्दाडंबर से दूर, तथ्यों को 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 1898 से कुछ अतिरिक्त तथ्यों के साथ निकाला गया है जो अन्य दो रिट याचिकाओं से आवश्यक हो सकते हैं। पक्षों के विद्वान वकीलों ने सभी रिट याचिकाओं के संबंध में सामान्य प्रश्न भी उठाए हैं। 1992 की सिविल रिट याचिका 5864 और 1993 की 5404 से संबंधित कुछ अतिरिक्त विवाद भी उठाए गए हैं। अतिरिक्त विवादों को अलग से निपटाया जाएगा।

(2) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता नंबर 1 जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विधिवत पंजीकृत है और इसका पंजीकृत प्रधान कार्यालय दिल्ली रोड पर है। हिसार. याचिकाकर्ता नंबर 2 कंपनी का एक शेयरधारक है, जिसका याचिकाकर्ता कंपनी-जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड में वित्तीय हित है

और कहा गया है कि वह प्रतिवादी 2/4 द्वारा पारित किए गए विवादित आदेशों से भौतिक रूप से प्रभावित है, जिससे अतिरिक्त मांग पैदा हो रही है। आर.जे.एस. 2.04,1/3,895,1 - दिसंबर 1/8, 1991 के आदेशों के अनुसार। याचिकाकर्ता संख्या 1 को सादे कार्बन, मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्स, स्लैब, ब्लूम्स, प्लेट्स, ऑक्सीजन और आर्गन के निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ बताया गया है। पिछले दो दशकों से अधिक समय से गैसों आदि। इसका व्यवसाय टर्न-ओवर कई गुना बढ़ गया और वर्ष 1990-91 के लिए वर्तमान टर्न-ओवर लगभग रु. जबकि इसका टर्न ओवर 1,88,60,30,533.81 है

वर्ष 1971-72 रु. 24,05,097.00. टर्न-ओवर में पर्याप्त वृद्धि का कारण यह बताया गया है कि कंपनी उन उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है जो आयात विकल्प हैं और याचिकाकर्ता कंपनी देश में कई अन्य इकाइयों के लिए मातृ उद्योग है। यह हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (इसके बाद 'राज्य अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और केंद्रीय अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत है। कंपनी राज्य अधिनियम और केंद्रीय अधिनियम दोनों के तहत नियमित रूप से अपने बिक्री कर रिटर्न दाखिल कर रही है और राज्य अधिनियम और/या केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो भी कर की राशि देय है, उसे जमा कर रही है। याचिकाकर्ता कंपनी का यह भी मामला है कि राज्य अधिनियम के साथ-साथ केंद्रीय अधिनियम के तहत इसका मूल्यांकन 31 मार्च, 1988 तक पहले ही पूरा हो चुका था, जब वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजन लाल ने हरियाणा राज्य के मामलों को संभाला था। उपरोक्त अवधि तक कंपनी का मूल्यांकन हमेशा संबंधित अधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार किया गया था। कंपनी का दावा है कि उसका ट्रेक रिकॉर्ड बहुत साफ-सुथरा है क्योंकि प्रबंधन ईमानदारी से और समय पर करों का भुगतान करके बिक्री कर कानून सहित सभी कानूनों के अनुपालन के प्रति बहुत सचेत था। पिछले नौ वर्षों के मूल्यांकन आदेशों से, यह स्पष्ट होगा कि अंतिम मूल्यांकन आदेशों के समय दांव बहुत सीमित थे और यदि कुछ वर्षों में कुछ हजार रुपये की अतिरिक्त मांग पैदा हुई है, तो रिफंड कुछ वर्षों में ऑर्डर भी दिए गए। कंपनी खुद को हजारों श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए रोजगार का एक स्रोत होने के साथ-साथ न केवल राज्य के लिए बल्कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर और अन्य करों के रूप में भारत संघ के लिए निरंतर राजस्व का स्रोत होने का भी दावा करती है। जो रुपये में होता है। 60 करोड़ और जो पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ रहे हैं। कंपनी को राज्य के साथ-साथ भारत संघ को भी रुपये की राशि के योगदान की उम्मीद थी। राजस्व के रूप में 80 करोड़ रु. इसके स्वच्छ ट्रेक रिकॉर्ड को उजागर करने के लिए यह अनुरोध किया जाता है कि वर्ष 1970-71 में कंपनी की स्थापना के बाद से यह राज्य या राज्य को किसी भी राजस्व या कर के भुगतान के मामले में हमेशा अपने मूल रूप से ईमानदार रही है। केंद्र को और यही कारण है कि कंपनी कभी भी किसी राजस्व की चोरी से संबंधित किसी मुकदमे में शामिल नहीं हुई। इसी प्रकार, कंपनी का प्रबंधन हमेशा अपने कर्मचारियों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने और रोजगार, बोनस और अन्य सुविधाओं के सभी संभावित लाभ प्रदान करने के मामले में न केवल अपने उच्च प्रबंधन अधिकारियों को बल्कि यहां तक कि अग्रणी रहा है। सबसे निचले स्तर पर लगे कार्यकर्ताओं के लिए, कंपनी की विकास दर हर साल बढ़ रही थी, लेकिन अनुरोध है कि कुछ अत्याचारों पर काबू पाया जाए।

इसका विवरण आगे दिया जाएगा, यदि वर्तमान शासन द्वारा प्रतिबद्धता नहीं की गई होती, तो विकास दर वहीं अधिक होती। जून, 1991 से, यह याचिकाकर्ता कंपनी का मामला है, वर्तमान शासन द्वारा किए गए अत्याचारों ने याचिकाकर्ता कंपनी के सामान्य और सुचारू संचालन को गंभीर झटका दिया है, जो श्री के नेतृत्व में वर्तमान शासन द्वारा किए गए राजनीतिक प्रतिशोध के कारण है। भजन लाई ने याचिकाकर्ता कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री ओपी जिंदल के खिलाफ, हिसार से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के मामले में श्री ओपी जिंदल द्वारा हिसार निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की लोकप्रिय मांगों को स्वीकार करने के कारणों के लिए वर्ष 1991 में विधानसभा क्षेत्र जिसमें श्री ओपी जिंदल ने श्री भजन लाई के एक शिष्य को सफलतापूर्वक हराया था। जब तक वर्तमान रिट दायर की गई, याचिकाकर्ता कंपनी का मामला यह है कि उस पर लगभग 200 मामले दर्ज किए गए थे, जिनका प्रबंधन किसी न किसी न्यायालय में विरोध कर रहा है और वास्तव में इसका अधिकांश कर्मचारी काम पर है। श्री भजन लाई द्वारा याचिकाकर्ता कंपनी के प्रबंधन पर थोपे गए राजनीतिक प्रतिशोध के कारणों से अस्तित्व में आने वाले किसी न किसी मुकदमे को लड़ने या बचाव करने के लिए पूरे दिन और वह भी हर दिन दौड़ें। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि श्री भजन लाई ने राजनीतिक क्षेत्र में श्री ओपी जिंदल को झुकाने की कोशिश में राज्य मशीनरी के प्रत्येक अंग का न केवल उपयोग किया है, बल्कि उनके औद्योगिक ढांचे को परेशान करके यह देखने के लिए कि चूक के कृत्यों का दुरुपयोग किया है। और मुख्यमंत्री की ओर से कमीशन अंततः याचिकाकर्ता कंपनी के इक्विटी शेयरधारक, जो लगभग 40,000 हैं, के भाग्य पर भारी पड़ेगा।

(3) जब प्रस्तुतकर्ता: मुख्यमंत्री ने जून, 1991 के महीने में सत्ता संभाली, मूल्यांकन वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लिए मूल्यांकन कार्यवाही तीनों मूल्यांकनों में लंबित थी, राज्य अधिनियम के तहत कटौती का दावा साथ ही केंद्रीय अधिनियम में एक ही संरक्षक शामिल था, जैसा कि पहले के मूल्यांकन वर्षों में भी शामिल था, जिसके लिए मूल्यांकन पहले ही तैयार किया जा चुका था और मुद्दे में मामले, वास्तव में प्रकृति में समान थे, मूल्यांकन वर्ष के अंतर को छोड़कर और बिक्री कारोबार की मात्रा में अंतर जो सभी मूल्यांकन वर्षों में बढ़ रहा था। कुल मिलाकर, मामले तथ्यों के साथ-साथ कानून की दृष्टि से भी समान थे। ऐसा कहा जाता है कि कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री ओपी जिंदल को अप्रैल से जून, 1991 के बीच शुरू और संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में श्री भजन लाई के क्रोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने हिसार विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। श्री बंस के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खंड चुनाव! लाई, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, श्री भजन लाई की इच्छाओं और इच्छाओं के विरुद्ध। ऐसा कहा जाता है कि उत्तरार्द्ध ने यह घोषणा करके सभी को अपनी नाराजगी से अवगत कराया कि वह प्रॉक्सी द्वारा हिसार चुनाव लड़ेंगे और अपने शिष्य श्री ओपी महाजन को टिकट आवंटित कर दिया, जिन्हें उन्होंने अपने ही पराजित होने के बाद एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुना था। वर्ष 1987 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार श्री मुन्ना माई। अपने रुख को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कि भजन लाई ने हिसार चुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया था, यह कहा गया है कि उन्होंने इसे हर निकाय को बता दिया था। यह चुनाव प्रचार के दौरान उनके द्वारा दिए गए सार्वजनिक भाषणों से स्पष्ट है क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश समय हिसार में बिताया। कुछ सार्वजनिक भाषण, जो चुनाव अभियान के दौरान दिए गए थे और जो प्रेस में छपे थे, चुनाव प्रक्रिया के दौरान अनुलग्नक पी-196-ए से पी-196-सी के रूप में रिट के साथ संलग्न किए गए

हैं, यह आगे का मामला है याचिकाकर्ता कंपनी, श्री भजन लाई ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि वह हिसार चुनाव हार गए, तो इसका मतलब उनकी नाक काटना होगा। हालाँकि, श्री ओपी जिंदल उक्त चुनाव में श्री ओपी महाजन को बड़े अंतर से हराकर निर्वाचित हुए थे। यही कारण है कि श्री भजन लाई ने सत्ता में आने के तुरंत बाद अपनी धमकियों पर अमल करना शुरू कर दिया और सबसे पहले पुलिस तंत्र को यह देखने के लिए लगाया कि याचिकाकर्ता कंपनी के कारखाने के परिसर में निर्मित सामान इधर-उधर न हो, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न नागरिक मुकदमे दायर किए गए। जिस पर स्टे दे दिया गया। पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त सहित स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा स्थगन आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए। हिसार, 7 अगस्त, 1991 को न्यायालय द्वारा इन अधिकारियों के वेतन की कुर्की का आदेश दिया गया था। इसके बाद, श्री ओपी जिंदल, उनके बेटे, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा उनके राजनीतिक समर्थकों को न केवल के तहत दर्ज झूठे आपराधिक मामलों में शामिल किया गया था। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान लेकिन शस्त्र अधिनियम के तहत आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के भयानक प्रावधान भी। हालाँकि, याचिकाकर्ता का मामला यह है कि श्री ओपी जिंदल ने उपरोक्त अत्याचारों के बाद भी मुख्यमंत्री श्री भजन लाई के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उसका सामना किया। इस प्रकार, श्री 0 की चिंताओं को बिजली की आपूर्ति। श्री भजन लाई ने याचिकाकर्ता कंपनी सहित पी. जिंदल की कंपनी का कनेक्शन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड पर दबाव डालकर काट दिया, जहां मेरी कंपनी द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से स्थापित कैप्टिव पावर प्लांटों से उत्पन्न बिजली का भी उपभोग नहीं करने दिया गया। . हालाँकि, जब न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण श्री ओपी जिंदल की बिजली आपूर्ति कटवाने के बाद भी मुख्यमंत्री वांछित परिणाम नहीं दे सके , तो श्री भजन

लाई ने उद्योग और प्रदूषण नियंत्रण विभागों को सेवा में लगाया, जिन्होंने कई नोटिस जारी करके कारखानों को बंद कराने की कोशिश की। जब, इससे भी वांछित परिणाम नहीं मिले, तो मुख्यमंत्री को यह पता चला कि याचिकाकर्ता कंपनी के तीन कर निर्धारण हिसार में उक्त विभाग में लंबित थे, पहले बड़े पुलिस बल के साथ छापेमारी करके बिक्री कर विभाग को आगे लाया। याचिकाकर्ता कंपनी का कारखाना परिसर, लेकिन यहां तक कि श्री ओपी जिंदल का आवासीय घर और वह भी उनकी अनुपस्थिति में पूरी तरह से अवैध तरीके से। श्री आर.एस. शर्मा-प्रतिवादी नंबर 4, यह याचिकाकर्ता का मामला है, विशेष रूप से उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त के रूप में हिसार में उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लाया गया था जब पहले के पदधारी ने अवैध उद्देश्यों को पूरा करने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री। इसके बाद, ट्रक यूनिजन विवाद का सहारा लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता कंपनी के लिए और उसकी ओर से माल ले जाने वाले ट्रकों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया। इस बार भी अदालतें कंपनी के बचाव में आईं। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि अत्याचार यहीं समाप्त नहीं हुए और उसके बाद वांछित परिणामों के लिए मुख्यमंत्री ने असामाजिक तत्वों को सेवा में लगाया, जिन्होंने याचिकाकर्ता के कर्मचारियों के कारखानों और आवासीय क्षेत्रों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी और वे थे। यहां तक कि आतंकित भी किया।

(4) द'ससेसमेंट? वर्ष 1988-89 के लिए कार्यवाही राज्य अधिनियम के तहत 26 सितंबर, 1989 को पहली बार उत्तरदाताओं 2 और 4 द्वारा की गई थी। केंद्रीय अधिनियम के तहत मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के लिए उत्तरदाताओं 2 और 4 द्वारा कंपनी को कभी भी कोई

अलग वैधानिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। 25 सितंबर, 1991 तक प्रतिवादी 2 और 4 ने माल रसीद एसटी 38 फॉर्म आदि को सत्यापित करने का केवल प्रारंभिक कार्य किया था। जैसा कि विभिन्न बिक्री कर जांच बाधाओं से प्राप्त हुआ है जो मूल्यांकन फ़ाइल पर पारित विभिन्न अंतरिम आदेशों से स्पष्ट होगा। इस पूरे समय के दौरान याचिकाकर्ता कंपनी को 26 सितंबर, 1991 को नोटिस जारी करने से पहले कभी भी कोई कागजात जमा करने के लिए नहीं कहा गया था। 10 दिसंबर, 1991 को नोटिस जारी करने के साथ ही मूल्यांकन की कार्यवाही पूरी ताकत से शुरू की गई थी, जिसे नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता कंपनी ने 16 दिसंबर, 1991 को उत्तरदाताओं 2 और 4 को मुख्यमंत्री द्वारा मूल्यांकन कार्यवाही पूरी करने में अनावश्यक देरी न करने के लिए एक ताजा फ़ीडबैक दिया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता कंपनी ने मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान हमेशा सहयोग किया और उत्तरदाताओं 2 और 4 द्वारा जो भी जानकारी या दस्तावेज़ मांगे गए, उन्हें बिना किसी देरी के हमेशा प्रदान किया। उप उत्पाद शुल्क एवं

कराधान आयुक्त-प्रतिवादी संख्या 2, - 31 अक्टूबर 1991 के नोटिस के तहत, 11 नवंबर 1991 को कंपनी को दिए गए नोटिस में उसे 13 नवंबर 1991 को कुछ दस्तावेज़ जमा करने के लिए कहा गया। याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ थे प्रोफार्मा ए और बी, कंपनी की तीन शाखाओं के प्रमुख/अधिकृत व्यक्तियों के शपथ पत्र, "एफ" फॉर्म, बैलेंस शीट इत्यादि। प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज़ों को पैरा के उप पैरा (i) से (iv) में संक्षेपित किया गया है। रिट याचिका के 12.

याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शांति भूषण ने इतनी दलील दी और तर्क दिया कि नियम 12 (5) के साथ पढ़ी गई धारा 6 (ए) का अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह साबित करने के लिए कि माल भेजा गया है एक पंजीकृत डीलर (वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता कंपनी) द्वारा अपनी शाखाओं और अपने कंसाइनमेंट एजेंटों को कंसाइनमेंट बिक्री के आधार पर क्षेत्र की बिक्री करने के लिए, अंतर-राज्यीय बिक्री नहीं, फॉर्म "एफ" की विधिवत घोषणा निर्धारित प्राधिकारी यानी संबंधित बिक्री कर प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जहां शाखाएं पंजीकृत हैं, पंजीकृत डीलर के रूप में और जहां कंसाइनमेंट एजेंट पंजीकृत डीलरों के रूप में पंजीकृत हैं, और शाखाओं और कंसाइनमेंट एजेंटों द्वारा निष्पादित किया जाता है, कंसाइनर को सौंप दिया जाता है।, मूल्यांकन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उक्त फॉर्म "एफ" जमा करना, प्रोफार्मा ए और बी के साथ, स्पष्ट रूप से संबंधित शाखाओं के प्रमुख अधिकारियों के हलफनामे के साथ, संख्या में 191 (शाखा हस्तांतरण से संबंधित 44 और खेप प्रेषण से संबंधित 147) याचिकाकर्ता कंपनी पर यह साबित करने का बोझ डाला गया कि रुपये का माल। 51,66,179.26 रुपये का माल इसके उपभोग और/या बिक्री के लिए इसकी उपरोक्त तीन शाखाओं को भेजा गया था। कंसाइनमेंट बिक्री के आधार पर उक्त माल की बिक्री को प्रभावित करने के लिए इसके द्वारा अपने विभिन्न कंसाइनमेंट एजेंटों को 55.45.92,345.00 भेजे गए थे। मेसर्स जिंदल स्टील एजेंसी, मद्रास द्वारा भेजे गए फॉर्म "एफ" की सच्ची प्रतियां रिट याचिका के साथ संलग्न की गई हैं, जिसका विवरण अनुबंध पी-295 में दिया गया है। इसी प्रकार, मेसर्स ऑर्बिट स्टील इंडिया, बॉम्बे द्वारा भेजे गए फॉर्म "एफ" की सच्ची प्रतियां अनुलग्नक पी-77 से पी-97 के रूप में रिट के साथ संलग्न की गई हैं। यह तर्क दिया गया है कि अन्य दस्तावेज़ों और खातों के अलावा इन दस्तावेज़ों और माल प्राप्तियों के आधार पर, मूल्यांकन प्राधिकारी को 13

नवंबर 1991 को ही कंपनी के मूल्यांकन को अंतिम रूप देना चाहिए था, जिसमें यह माना गया था कि शाखा हस्तांतरण वास्तविक थे और कानून के तहत स्वीकार्य थे। याचिकाकर्ता द्वारा अपने विभिन्न कंसाइनमेंट एजेंटों को किए गए प्रेषण वास्तविक और कानून के तहत स्वीकार्य थे। हालाँकि, प्रतिवादी 2/4 ने कार्यवाही स्थगित कर दी

20 नवंबर, 1991 अप्रासंगिक विचारों के लिए। दस्तावेजों का एक समूह, जैसे कि जी.आर., कंसाइनमेंट डिस्पैच सलाह इत्यादि, जो दर्शाता है कि सामग्री सीधे कंपनी के ठेकेदारों द्वारा दिल्ली से कंसाइनमेंट एजेंटों को भेजी गई थी, रिट याचिका के साथ भी संलग्न की गई है। जो सामग्री दिल्ली में काम करने वाले ठेकेदारों को भेजी गई थी, उसके लिए दिल्ली में उपलब्ध परिवहन कंपनियों की सेवाओं की आवश्यकता थी। आगे दलील दी गई है कि शाखा हस्तांतरण के संबंध में पूरा साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया था जिसे प्रतिवादी संख्या 2/4 द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था। चूंकि कंपनी द्वारा हरियाणा राज्य के भीतर आरसी के आधार पर या कर के भुगतान के बिना कोई खरीदारी नहीं की गई थी, इसलिए इन सामानों को अपनी शाखाओं में स्थानांतरित करना उसके अधिकार में था और राज्य या केंद्रीय अधिनियम के तहत कोई अतिरिक्त कर देनदारी नहीं थी। ऐसे स्थानान्तरण पर अर्जित होगा। शाखाओं में स्थानांतरण का तथ्य उत्तरदाता संख्या 2/4 द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है, प्रधान कार्यालय और एक ही इकाई के शाखा कार्यालय के बीच अंतरराज्यीय बिक्री के अलावा कोई बिक्री नहीं हो सकती है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है, प्रतिवादी संख्या 2/4 उस कानून को इंगित करने में बुरी तरह विफल रही जिसके तहत याचिकाकर्ता कंपनी स्टोर के सामान को राज्य के बाहर अपनी शाखाओं में उसी आकार में स्थानांतरित करने की हकदार नहीं थी, जब कोई भी इसके बल पर नहीं खरीदा गया था। हरवाना में आरसी या बिना टैक्स चुकाए। 20 नवंबर 1991 को भी नेफिशनर कंपनी ने, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2/4 की सिफारिश की थी, 23 हलफनामे प्रस्तुत किए, जिनमें से एक कंपनी और 19 कंसाइनमेंट एजेंटों द्वारा वर्ष 1988-89 और तीन के लिए कंसाइनमेंट बिक्री के संबंध में था। शाखा स्थानान्तरण के संबंध में। ये हलफनामे, यह नेफिशनर का मामला है, 21 कंसाइनमेंट एजेंटों के प्रमुख अधिकारियों/अधिकृत व्यक्तियों द्वारा शपथ ली गई और घोषित की गई कि उन्होंने नेफिशनर कंपनी से मूल्यांकन वर्ष 1988-89 में उक्त सामान प्राप्त किया था और उक्त माल का हिसाब-किताब कर लिया गया है और उनकी पुस्तकों में दर्ज कर दिया गया है और उक्त माल वास्तव में हरवाना की सीमा से बाहर चला गया था और उक्त माल का कोई भी हिस्सा हरियाणा राज्य में बेचा या उपभोग नहीं किया गया था और उन्होंने उसी की बिक्री को प्रभावित किया था। खेप के आधार पर. उपरोक्त दस्तावेजों की प्राप्ति पर, प्रतिवादी संख्या 2/4। यह निवेदन किया गया है कि, शाखा हस्तांतरण को वास्तविक माना जाना चाहिए और व्यवसाय के सामान्य क्रम में किया जाना चाहिए, सबूत का बोझ याचिकाकर्ता कॉमननव द्वारा निर्णायक रूप से निर्वहन किया गया है। प्रतिवादी 'नहीं' 2/4 को याचिकाकर्ता कॉमननव के दस्तावेजों यानी फॉर्म "एफ", हलफनामों के आधार पर यह भी मानना चाहिए था कि खेप की बिक्री रु। 55.45 92.345 वास्तविक खेप की बिक्री थी जो कानून के तहत स्वीकार्य थी। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 2/4 ने उपरोक्त के अनुसार मूल्यांकन होल्डिंग को अंतिम रूप देने के बजाय, मूल्यांकन कार्यवाही को लंबित रखा।

(51 टीटी से अनुरोध है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 2/4 का इरादा तब सामने आया जब उन्होंने 10 दिसंबर को नोटिस जारी किया।

1991 ने याचिकाकर्ता कंपनी को 16 दिसंबर 1991 को उसके उत्तर और 17 दिसंबर 1991 को उपस्थिति के लिए भेजा। इस नोटिस में, उत्तरदाता संख्या 2/4 ने रुपये की खेप बिक्री की वास्तविकता पर संदेह किया। याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा हरियाणा राज्य के बाहर अपने विभिन्न एजेंटों को भेजे गए माल में से 55,45,92,345 रुपये और कंपनी द्वारा अपनी शाखाओं में स्थानांतरित किए गए माल में से रु। 51,66,179.26 हरियाणा राज्य के बाहर और कंपनी से

कारण बताने को कहा कि क्यों न उक्त संपूर्ण खेप बिक्री और शाखा हस्तांतरण को अस्वीकार कर दिया जाए और खेप बिक्री और शाखा हस्तांतरण को अंतर-राज्यीय बिक्री मानते हुए केंद्रीय अधिनियम के तहत कर लगाया जाए। यह कहा गया है कि नोटिस की सामग्री से यह स्पष्ट होगा कि 'प्रतिवादी संख्या 2/4 ने वह जानकारी मांगी थी जो अन्यथा 1988-89 की संबंधित मूल्यांकन फाइलों पर उनके पास उपलब्ध थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की। फ़ाइल की गई और यहां तक कि जानबूझकर ध्यान में लाए गए प्रासंगिक दस्तावेजों को भी नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि वे कानूनी तरीके से मूल्यांकन तैयार करने के लिए नहीं थे, बल्कि रुपये की अवैध मांग पैदा करने की दृष्टि से अवैध तरीके से थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 करोड़ रु . जैसा कि ऊपर कहा गया है, कंपनी को आक्षेपित नोटिस, अनुलग्नक पी-101, 16 दिसंबर, 1991 को दिया गया था। इस नोटिस द्वारा, याचिकाकर्ता को नोटिस जारी होने के केवल एक दिन बाद, 17 दिसंबर, 1991 को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। परोसा गया, जो पूरी तरह से अनुचित और मनमाना था क्योंकि उसे अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 2/4 द्वारा दिए गए सबसे कम संभव समय के बावजूद, कंपनी ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 2/4 के आरोप इस आशय के थे कि उसके द्वारा की गई खेप की बिक्री/शाखा हस्तांतरण वास्तविक नहीं थे। इनकार कर दिया गया और यह प्रस्तुत किया गया कि कंपनी ने पहले ही यह साबित करने के लिए फाइल पर सभी आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड रख दिए थे कि रुपये का माल। 55,45.92.345 रुपये इसके द्वारा हरियाणा राज्य के बाहर अपने विभिन्न कंसाइनमेंट एजेंटों को कंसाइनमेंट बिक्री के आधार पर बिक्री के लिए भेजे गए थे और उन एजेंटों ने कंसाइनमेंट बिक्री के आधार पर उसी की बिक्री को प्रभावित किया था। रुपये का सामान 51,66.179.26 वास्तव में याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा हरियाणा राज्य के बाहर अपनी शाखाओं में उपभोग/बिक्री के लिए भेजे गए थे। जवाब में आगे कहा गया कि माल की संपत्ति हमेशा याचिकाकर्ता कंपनी में निहित होती है, जिसके पास हिसार से राज्य के बाहर अन्य स्थानों पर परिवहन के दौरान माल के डायवर्जन के सभी अधिकार होते हैं। भले ही माल के प्रेषण और अंतिम निपटान में कुछ समानताएं हों, फिर भी यह किसी विशेष कंसाइनमेंट एजेंट की संपूर्ण कंसाइनमेंट बिक्री को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। हालाँकि, कंपनी की तमाम दलीलों और दस्तावेजों के बावजूद, जैसे

18 दिसंबर, 1991 को सुबह 9.00 बजे अपना जवाब देने के लिए कहा गया। उपरोक्त नोटिस में निहित निर्देशों के अनुपालन में, कंपनी के पास बहुत कम समय उपलब्ध होने के बावजूद, उसने अपना उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 2/4 द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को अस्वीकार कर दिया गया। उत्तर के साथ, कंपनी अपने तर्क के समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए कि शाखा हस्तांतरण वास्तविक थे और अंतर-राज्यीय बिक्री नहीं थी और उक्त दो कंपनियां, अर्थात् मेसर्स जिंदल स्टील एजेंसी, मद्रास और मेसर्स ऑर्बिट स्टील (इंडिया), बॉम्बे थीं। प्रासंगिक वर्ष 1988-89 और आज तक अस्तित्व में है और रुपये का माल। 18,89,37,392 और रु. याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा कंसाइनमेंट बिक्री के आधार पर उक्त माल की बिक्री को प्रभावित करने के लिए इन कंपनियों को 6,45,38,342 रुपये भेजे गए थे। इसके बावजूद, यह दलील दी गई है कि प्रतिवादी 2/4 ने, रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों और अन्य सबूतों का अवलोकन किए बिना, याचिकाकर्ता कंपनी को गवाहों की जिरह का अवसर दिए बिना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, पारित कर दिया। आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी-194, - जिसके तहत रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है। 2,04,13,895 इस आधार पर बनाया गया था कि शाखा रुपये का हस्तांतरण करती है। 17,30,756 वास्तविक नहीं थे और कर के लिए उत्तरदायी थे और बिक्री (खेप बिक्री) के अलावा अन्य हस्तांतरणों की राशि रु। मेसर्स जिंदल स्टील एजेंसी, मद्रास को 18,89,37,392 रु. मेसर्स ऑर्बिट स्टील (इंडिया), बॉम्बे को दिए गए 6,45,38,342 असली नहीं थे और अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान थे। यह कारण बताओ नोटिस है, अनुलग्नक पी-101। पी-103, मूल्यांकन आदेश, अनुलग्नक पी-194 और मांग नोटिस, अनुलग्नक पी-195, जिन्हें इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है, जैसा कि फैसले के पहले भाग में उल्लिखित है।

(6) प्रासंगिक तथ्यों के साथ-साथ आक्षेपित आदेशों के निष्कर्षों 31 पर, जैसा कि ऊपर विस्तृत किया गया है, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कंपनी पर अतिरिक्त कर देयता दो आधारों पर बनाई गई है, (1) हरियाणा से शाखाओं में स्टोर माल का स्थानांतरण याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा अन्य राज्यों में 'सी' फॉर्म का दुरुपयोग किया गया, जिसके आधार पर कंपनी द्वारा माल का पीछा किया गया था क्योंकि कंपनी को उन सामानों का उपयोग करना था, जिन्हें 'ओ' फॉर्म के आधार पर खरीदा गया था।, केवल अकेले हरियाणा राज्य में अपनी विनिर्माण इकाई में और अन्य राज्यों में अपनी विनिर्माण इकाइयों में उनका उपयोग करने का हकदार नहीं था और (2) बिक्री के अलावा याचिकाकर्ता कंपनी के कुछ एजेंटों को माल की खेप भेज दी गई है। इसे अंतरराज्यीय बिक्री माना गया और *अन्य बातों के साथ-साथ* इस आधार पर केंद्रीय बिक्री कर के अधीन किया गया

मूल्यांकन प्राधिकारी को यह नहीं दिखाया गया कि एजेंटों के पास उनके व्यवसाय के स्थानों पर गोदाम की सुविधाएं थीं। 1992 के सीडब्ल्यूपी संख्या 5864 और 1993 के 5404 में विवादित आदेशों के संबंध में यह सच है, बाद के आदेशों में कुछ अतिरिक्त आधार लिए गए हैं, अन्य दो रिट (सीडब्ल्यूपी संख्या 1992 की 5864 और 1993 की 5404) में चुनौती का विषय है।) और इसका उल्लेख आगामी चर्चा में किया जाएगा। शाखा हस्तांतरण से निपटने के दौरान, मूल्यांकन प्राधिकारी ने निम्नलिखित पाया:

" सीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर खरीदे गए स्टोर सामान की उपभोग्य वस्तुओं को निर्धारिती द्वारा अन्य राज्यों में उनकी इकाई में स्थानांतरित करना डीलर द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र का दुरुपयोग है, जबकि उन सामानों का होना चाहिए था याचिकाकर्ता कंपनी की हिसार स्थित फैक्ट्री में ही उपभोग किया गया, राज्य के बाहर नहीं।" '

हरियाणा राज्य के बाहर बिक्री के माध्यम से स्थानांतरण यानी खेप बिक्री से निपटने के दौरान, संबंधित प्राधिकारी ने निम्नानुसार देखा:

"जिरह के दौरान डीलर वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेनदेन के समर्थन में कानून के अनुरूप कोई ठोस सबूत या दस्तावेजी सबूत देने में विफल रहा क्योंकि इन कंपनियों को अस्तित्व में नहीं बताया गया था।

(i) मैसर्स जिंदल स्टील एजेंसी, मद्रास

Rs. 18,89,37,892

(ii) मेसर्स ऑर्बिट स्टील (इंडियाजे), लिमिटेड- बॉम्बे
कुल

Rs. 6,45,38,342

मद्रास और बॉम्बे में उपरोक्त दो फर्मों के अस्तित्व के संबंध में Rs. 25,34,75,734" याचिकाकर्ता कंपनी के बचाव से निपटने के बाद, संबंधित प्राधिकारी ने पाया कि "उपरोक्त दो फर्मों की वास्तविकता की जांच करते समय उनके साथ भंडारण सुविधा के पहलुओं की भी जांच की गई थी।" किसी की ओर से एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए यह आवश्यक है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्राप्त माल के भंडारण के लिए भंडारण सुविधाओं के अभाव में कंसाइनी फर्म थोक में माल प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होगी।

बिक्री (खेप बिक्री) के अलावा हस्तांतरण के रूप में बिक्री। डीलर मद्रास और बंबई में व्यवसाय के स्थानों पर कंसाइनी फर्मों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए गोदामों आदि के संबंध में कोई सबूत देने में विफल रहा। जैसा कि किताबों में दिखाया गया है, खेपों का प्रेषण बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए भंडारण सुविधाओं के अभाव में भविष्य में बिक्री को प्रभावित करने के लिए इस स्टॉक को रखना और रखना संभव नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में, कोई भी आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि ये लेनदेन बिक्री (खेप बिक्री) के अलावा अन्य हस्तांतरण नहीं हैं, बल्कि अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान बिक्री हैं। संबंधित प्राधिकारी द्वारा आगे यह देखा गया कि "बॉम्बे फर्म के मामले में फर्म के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 9 जून, 1990 के शपथ पत्र और 20 जनवरी, 1991 के शपथ पत्र में माल को हिसार से प्राप्त करने और बॉम्बे भेजने की पुष्टि की गई है क्रमशः हिसार से, लेकिन फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र "एफ" की सूची में नई दिल्ली से

माल का प्रेषण दिखाया गया था। इस प्रकार, माल की आवाजाही के स्थान के संबंध में इन हलफनामों में की गई पुष्टि में विरोधाभास है।” प्राधिकरण द्वारा कंपनी की याचिका को खारिज करते हुए तीसरा कारण यह है कि “जब पूरे भारत के लिए स्थानांतरण सुविधाएं हिसार (फर्म का व्यवसाय स्थान) पर उपलब्ध हैं, लेकिन इस मामले में माल को बॉम्बे से परिवहन किया गया दिखाया गया है परिवहन कंपनियाँ हिसार में अस्तित्व में नहीं हैं। इसी प्रकार, मेसर्स जिंदल स्टील एजेंसी, मैड्रस को बिक्री (कंसाइनमेंट बिक्री) के अलावा अन्य हस्तांतरण में प्रेषण के स्टेशन का खुलासा न करके और हिसार के बाहर एजेंसी की परिवहन सुविधाओं का लाभ उठाकर हेरफेर किया गया है।

(7) अतिरिक्त आधार, जेएलपरिणाम.:(बेशक, विषयों के निष्कर्षों और उसी परिणाम के लिए, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अन्य दो रिट याचिकाओं में, जिनकी संख्या 1992 की 5864 और 1993 की 5404 है, इस स्तर पर ध्यान दिया जा सकता है। कर निर्धारण प्राधिकारी ने शाखा हस्तांतरण से निपटने के दौरान आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी-715 (1992 के सीडब्ल्यूपी 5864 में) में, जैसा कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा दावा किया गया था, 6,90,47,200 रुपये का था जहां तक उससे संबंधित था तैयार माल के लिए, पूरी तरह से अनुमति दी गई। 3,40,71.200 रुपये मूल्य का स्टोर सामान ज्यादातर हरियाणा राज्य के बाहर से खरीदा गया था और शाखा हस्तांतरण के रूप में दिखाया गया था और इसे अंतर-राज्य बिक्री माना गया था, न कि शाखा स्थानान्तरण। मूल्यांकन प्राधिकारी ने इस प्रकार देखा: -

“यह समझ में नहीं आता है कि मेसर्स जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड, हिसार जैसी कंपनी, जिसका प्रबंधन अत्यधिक कुशल और योग्य कर्मियों द्वारा किया जाता है, भारी गैर-आवश्यक खर्च वहन करेगी।

हरियाणा राज्य के बाहर से सीधे माल लाकर परिवहन करना, फिर हरियाणा राज्य के बाहर अपनी शाखाओं में माल भेजने के दौरान चुंगी, उतराई, भंडारण, रखरखाव और फिर लोडिंग, परिवहन और चुंगी आदि पर खर्च करना। यह लाभोन्मुख व्यापार के सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। यदि ये सामान वास्तव में उनकी शाखाओं के लिए होता तो ये सामान सीधे शाखाओं द्वारा ही खरीदा जा सकता था, इस प्रकार, हिसार कार्यालय द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक खर्चों को बचाया जा सकता था। शाखाओं का प्रबंधन भी योग्य स्वतंत्र कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और वे उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं। वास्तव में इन सामानों को शाखाओं में स्थानांतरित नहीं किया गया था, बल्कि अंतरराज्यीय बिक्री के रूप में विभिन्न गंतव्यों तक ले जाया गया था, न कि शाखाओं में।”

रुपये के शाखा हस्तांतरण को अस्वीकार करते समय दिया गया दूसरा कारण। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 3,47,71.200 का तर्क दिया गया था कि दी गई जानकारी और पेश किए गए खातों में विसंगतियां और हेरफेर थे जो सत्यापन और जांच के परीक्षण का सामना नहीं कर सके, इसलिए मूल्यांकन उपरोक्त चर्चा के अनुसार नोट किए गए और सत्यापित तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है, नहीं डीलर द्वारा उत्पादित खातों पर भरोसा करना। अंतिम विश्लेषण में, मूल्यांकन प्राधिकारी ने रुपये के तैयार माल हस्तांतरण के कारण कटौती की अनुमति दी।

3,42,76,000 जबकि शेष रुपये की अंतर-राज्यीय बिक्री की अनुमति नहीं दी गई।
3,47,71,000.

(8) जबकि!आइडियलिंगटी विदसिंसाइनमेंट!सेल्स, एसेसिंगएजेसी ने रुपये की वास्तविक कंसाइनमेंट बिक्री के कारण कटौती की अनुमति दी। 38,69,23,402 जबकि शेष बिक्री को अंतरराज्यीय बिक्री माना गया। मूल्यांकन प्राधिकारी ने पाया कि "सत्यापन पर यह पाया गया कि अनुबंध के परिणामस्वरूप माल का पूरा टुक लोड हिसार से चला गया और उसी वाहन द्वारा अंतिम खरीदारों तक पहुंचाया गया।" अपने उपर्युक्त निष्कर्ष के लिए, प्राधिकारी ने कंसाइनमेंट एजेंट द्वारा जारी किए गए बिलों पर भरोसा किया, जिसमें उनके बिल में दिए गए कॉलम के बावजूद आरआर/जीआर नंबर, वाहन नंबर, परिवहन कंपनी का नाम या परिवहन से बना नहीं था। आरआर और प्रेषण का तरीका आदि। यह देखा गया कि यह जानकारी जानबूझकर बिलों पर नहीं दी गई थी क्योंकि यह जानकारी देने से *मोडस ऑपरेंड!* अंतर-राज्य-बिक्री को कंसाइनमेंट बिक्री के रूप में छिपाना बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। यह भी देखा गया कि लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और अन्य शुल्कों का कोई उल्लेख नहीं था

कंसाइनमेंट एजेंट द्वारा बनाए गए बिलों पर किए गए खर्च से पता चलता है कि ऐसा कोई खर्च नहीं था क्योंकि माल जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड, हिसार से सीधे अंतिम खरीदारों को वितरित किया गया था। खेप एजेंटों द्वारा बिल जारी करना तारीखों और वजन का समायोजन करके किसी को यह विश्वास दिलाने के लिए हेरफेर था कि ये खेप की बिक्री थी और अंतर-राज्यीय बिक्री नहीं थी। राय के लिए कुछ उदाहरण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आदेश में दिए गए थे। कर निर्धारण प्राधिकारी ने आगे देखा कि अन्य कंसाइनमेंट एजेंटों द्वारा दिखाई गई बिक्री के समान मामले थे और वास्तव में सामान उसी वाहन द्वारा और उसी मात्रा में खरीदारों को वितरित किया गया था, जिसने जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड से डिलीवरी ली थी। ..हिसार लेकिन अंतरराज्यीय बिक्री को कंसाइनमेंट सेल का रूप देने के लिए सिर्फ दो बिल बढ़ाकर हेराफेरी की गई। यह भी देखा गया कि सभी प्रकार की हेराफेरी करने के बाद, मेसर्स जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड, हिसार द्वारा भेजे गए माल में संख्यात्मक समानताएं थीं और माल को कंसाइनमेंट एजेंटों द्वारा अंतिम खरीदारों को बेचा गया दिखाया गया था, जिसकी सूची इस प्रकार संलग्न की गई थी अनुलग्नक-ए. एक एजेंट द्वारा अपने खरीदार को अनुबंध की शर्तों के साथ व्यवहार करते समय, "आपूर्ति की गई सभी सामग्री हमारी संपत्ति बनी रहती है जब तक कि पूरा भुगतान नहीं किया जाता है", प्राधिकरण ने देखा कि जब किसी को माल में संपत्ति के साथ निहित किया गया था और यदि माल पर संपत्ति का अधिकार था तथाकथित कंसाइनमेंट एजेंट, फिर मेसर्स जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड, हिसार ने कैसे दावा किया कि माल में संपत्ति उसके पास निहित है। यह भी देखा गया कि तथाकथित कंसाइनमेंट एजेंटों ने स्थानीय बिक्री के लिए अपने बिलों पर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत कर लगाया था जो एक स्पष्ट संकेत था कि मेसर्स जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड, हिसार की अंतर-राज्य बिक्री थी। यह भी देखा गया कि कुछ कंसाइनमेंट एजेंट स्वयं माल के खरीदार थे और इस संबंध में मरुधर इंडस्ट्रीज, बैंगलोर का उदाहरण दिया गया था। यह भी देखा गया कि किसी भी कंसाइनमेंट एजेंट ने अपनी फर्म के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति प्रदान नहीं की थी, जो यह साबित कर सकती है कि कंसाइनमेंट एजेंटों के पास माल भंडारण के लिए अनुमोदित गोदाम थे। उस सम्बन्ध में भी कुछ उदाहरण दिये गये। अंतिम विश्लेषण में, यह माना गया कि रुपये की बिक्री हुई। कुल दावा की गई खेप बिक्री में से 86,64,86,832 अंतर-राज्य बिक्री थीं और उक्त बिक्री पर तदनुसार कर लगाया गया था।

(9) जहां तक 18 फरवरी 1993 के मूल्यांकन आदेश, 1993 की सिविल रिट याचिका संख्या 5404 को जन्म देने का संबंध है, शाखा हस्तांतरण के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पार्टियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा कोई अतिरिक्त आधार नहीं बताया गया है। माल की बिक्री।

(10) 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 1898 को डीबी में स्वीकार कर लिया गया था, आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। सिविल रिट याचिका

1992 की संख्या 5864 को 10 अगस्त 1992 को स्वीकार किया गया था। हालाँकि, जब यह याचिका 19 मई 1992 को डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई और 17 जुलाई 1992 तक के लिए स्थगित कर दी गई, तो प्रार्थना के अनुसार रोक को अस्वीकार कर दिया गया। स्वीकार करते हुए, रोक लगाने से इनकार करने वाले आदेशों के खिलाफ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई जिसे अनुमति दे दी गई। तीसरी रिट याचिका यानी 1993 की सिविल रिट याचिका संख्या 5404 इस न्यायालय द्वारा 22 जुलाई 1993 को स्वीकार की गई जिसमें भी पहले दिए गए स्थगन के अंतरिम आदेश को जारी रखने का आदेश दिया गया था। तथ्यों पर, जैसा कि ऊपर पूरी तरह से विस्तृत किया गया है, याचिकाकर्ताओं की स्पष्ट प्रार्थना 18 दिसंबर, 1991 के आक्षेपित आदेश, अनुबंध पी-194 (1992 के सीडब्ल्यूपी 1898 में) के साथ-साथ मई के परिशिष्ट पी-715 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने की है। 1, 1992 (1992 के सीडब्ल्यूपी 5864 में) और आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी-29, दिनांक 18 फरवरी 1993 (1993 के सीडब्ल्यूपी संख्या 5404 में)।

(11) याचिकाकर्ताओं ने गंभीरता से दो अलग-अलग लिखित बयान दायर किए हैं, एक उत्तरदाताओं 1, 2 और 4 की ओर से और दूसरा श्री भजन लाई, मुख्यमंत्री प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से, दायर किया गया है। लिखित बयान में उत्तरदाताओं 1, 2 और 4 ने याचिकाकर्ता कंपनी की पृष्ठभूमि बताते हुए दलील दी कि कंपनी ने मूल्यांकन वर्ष 1988-89 के दौरान बिक्री (कंसाइनमेंट बिक्री) के अलावा अन्य हस्तांतरणों के कारण कटौती का दावा किया है। रु. 55,45,92,354. खेप की बिक्री में से रु. 55,45,92,345, रुपये की सीमा तक खेप बिक्री। 25,34,75,734 को इस तथ्य के कारण अस्वीकार कर दिया गया था कि कंसाइनमेंट बिक्री के संबंध में याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा प्रस्तुत 'एफ' फॉर्म वास्तविक नहीं पाए गए थे। कटौती का दावा करने के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत 'एफ' फॉर्म में, जिस स्टेशन से माल वास्तव में खेप के आधार पर भेजा गया था, उसे नई दिल्ली के रूप में दिखाया गया था जहां कंपनी का शाखा कार्यालय है। मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान कंपनी का तर्क था कि माल केवल आईओबी कार्य के लिए दिल्ली भेजा गया था। सत्यापन करने पर, यह पाया गया कि 'कार्य पूरा होने के बाद सामान हिसार में वापस नहीं मिला।' इसके कारण मूल्यांकन प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता कंपनी को रुपये की सीमा तक खेप बिक्री के दावे को अस्वीकार कर दिया। 25,34,75,734 मेसर्स जिंदल स्टील एजेंसी, मद्रास और मेसर्स ऑर्बिट स्टील (इंडिया), बॉम्बे से संबंधित। खेप बिक्री के बिंदु पर याचिकाकर्ता कंपनी ने रुपये की कटौती का दावा करने के लिए 'एफ' फॉर्म भी जमा किया। 25,34,75,734 और अपने दावे के समर्थन में, कंपनी ने कहा कि माल कंसाइनमेंट एजेंटों मैसर्स टीएमडीएल आरटील एजेंसी के माध्यम से कंसाइनमेंट के आधार पर था। मद्रास। कंपनी ने दस्तावेज पेश किए जिससे पता चला कि सामान मूल्यवान था रु. 18,89,37,392 और रु. 6,45,38,342 रुपये क्रमशः मेसर्स जिंदल स्टील एजेंसी, मद्रास और मेसर्स ऑर्बिट स्टील (इंडिया) बॉम्बे को भेजे गए। फॉर्म 'एफ' में मेसर्स जिंदल स्टील एजेंसी, मद्रास

को भेजे गए माल के संबंध में उस स्टेशन का नाम नहीं था जहां से माल भेजा गया था, जबकि मेसर्स जिंदल स्टील एजेंसी, मद्रास को भेजे गए माल के संबंध में डेस पैच स्टेशन का नाम नहीं था। < ऑर्बिट स्टील (भारत), बॉम्बे, माल के प्रेषण का स्टेशन नई दिल्ली के रूप में दर्शाया गया था। इस प्रकार, कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाए गए क्योंकि ऊपर नामित फॉर्म अस्तित्व में ही नहीं थीं। आगे यह दलील दी गई है कि कंपनी ने रुपये की सीमा तक शाखा हस्तांतरण किया। 53,90,500 और इन शाखा हस्तांतरणों के कारण कटौती का दावा किया। उक्त शाखा हस्तांतरण को शाखाओं के बीच रायगढ़ (एमपी) और वासिंद, जिला थाना (महाराष्ट्र) की शाखाओं में स्थानांतरण के रूप में दिखाया गया था। कुल शाखा हस्तांतरण में से रु. कंपनी ने 53,90,599 रुपये का स्टोर सामान खरीदा। हिसार में तैयार माल के निर्माण में उपयोग के लिए 21,20,10,907। दुकान से लाखों रुपये का सामान बाहर 21,20,10,907. रुपये का सामान स्टोर करें। 17,30,356 को रायगढ़ (एमपी) और वासिंद की शाखाओं में स्थानांतरण के रूप में दिखाया गया था। जिला थाना. चूंकि दुकान का माल रु. याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा 17,30,356 रुपये हिसार में निर्माण में उपयोग के लिए खरीदे गए थे, यह इसे हरियाणा राज्य के बाहर अन्य शाखाओं में स्थानांतरित करने का हकदार नहीं था। चूंकि उपभोज्य वस्तुओं का उपभोग केवल हिसार में तैयार माल के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान किया गया था, इसलिए कंपनी रुपये की सीमा तक शाखा हस्तांतरण के कारण किसी भी कटौती की हकदार नहीं थी। 17,30,356 जो वास्तव में केंद्रीय अधिनियम की धारा 3एफए के अर्थ के तहत व्यापार और वाणिज्य की अंतर-राज्य बिक्री के दौरान था। प्रारंभिक आपत्ति यह है कि याचिकाकर्ताओं के लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है! राज्य अधिनियम के तहत धारा 39 के तहत अपील की गई है। गुण-दोष के आधार पर, जबकि विवादित आदेशों को पारित करने के लिए बुनियादी तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया है, याचिकाकर्ताओं के आरोप हैं कि आदेश अवैध हैं, क्षेत्राधिकार के बिना या यहां तक कि उस मामले के लिए पारंपरिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हैं और *दुर्भावना* के कारण कार्यान्वित किए गए हैं। सख्ती से इनकार किया गया है। यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा एनआरएमसीआईएन अधिकारियों के प्रोफार्मा एम'आर हलफनामे के साथ फॉर्म 'एफ' जमा करने से वास्तव में यह साबित नहीं होगा कि रुपये का सामान। 17 30 256 ने इसे अपनी शाखाओं में उपभोग/या बिक्री के लिए भेजा और रुपये का माल। इसके द्वारा कंसाइनमेंट के आधार पर 55,45 92,345 भेजे गए। कंपनी ने रुपये का स्टोर सामान खरीदा था। 21.70 10 907 से 21.70 10 907 हरियाणा राज्य और रारायौआ राज्य के बाहर यूई के लिए तैयार माल के निर्माण में केवल हिसार में और स्टोर माल के बाहर, रुपये का माल। 17,30, 356 को रायगढ़ (एमपी) में इसकी शाखाओं में स्थानांतरण के रूप में दिखाया गया था और वासिंद, जिला थाना (महाराष्ट्र) हरियाणा राज्य के बाहर स्थित है। कंपनी नहीं थी। इस प्रकार, वह स्टोर के सामान को उसी आकार में राज्य के बाहर अपनी शाखाओं में स्थानांतरित करने का हकदार है। इसी प्रकार, दिखाए गए माल में से अन्यथा हरियाणा राज्य के बाहर अपने एजेंटों को बिक्री के माध्यम से, माल का बड़ा हिस्सा मैसर्स जिंदल स्टील एजेंसी, मद्रास और मैसर्स के कंसाइनमेंट के आधार पर बिक्री के लिए भेजा गया है। एस ऑर्बिट स्टील (भारत), बॉम्बे। कंसाइनर और कंसाइनी ने कार्यालय में प्रस्तुत अपने शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि माल हिसार से भेजा गया है, लेकिन मैसर्स ऑर्बिट स्टील (इंडिया) लिमिटेड, बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत 'एफ' फॉर्म से पता चलता है कि माल भेजा गया था। नई दिल्ली से और मैसर्स जिंदल स्ट्रिप्स एजेंसी, मद्रास द्वारा जारी किए गए 'एफ' फॉर्म के संबंध में उचित कॉलम खाली में यानी उस स्टेशन का नाम जहां से माल भेजा गया था, का उल्लेख नहीं किया गया था। पूरे भारत में माल की ढुलाई के

लिए परिवहन सुविधाएं हिसार में उपलब्ध थीं। हालाँकि, कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से पता चला कि माल हिसार की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा मैसर्स जिंदल स्टील एजेंसी, मद्रास को भेजा गया था, जो वास्तव में हिसार में मौजूद नहीं थी। कंपनी ने दो कंसाइनमेंट एजेंटों यानी जिंदल स्टील एजेंसी, मद्रास और ऑर्बिट स्टील (इंडिया), बॉम्बे के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया था, जहां उन्होंने याचिकाकर्ता कंपनी, हिसार द्वारा हस्तांतरित माल रखा था। इस प्रकार, माल की बिक्री की राशि रु. ऑर्बिट स्टील (इंडिया), बॉम्बे के संबंध में 18.89 करोड़ रुपये। मैसर्स जिंदल स्ट्रिप्स एजेंसी, मद्रास को 6.45 करोड़ रुपये और स्टोर के सामान का शाखा हस्तांतरण, जिसकी कीमत रु। 17,30.356 वास्तविक और उचित नहीं पाए गए और उन्हें केंद्रीय अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत अंतर-राज्य बिक्री व्यापार और वाणिज्य के दौरान बिक्री के रूप में मानते हुए कानून के अनुसार कर के अधीन किया गया। आगे दलील दी गई है कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन पर, यह पाया गया कि उसने विनिर्माण के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर हरियाणा राज्य के भीतर और हरियाणा राज्य के बाहर से कच्चा माल और उपभोज्य भंडार खरीदा था। हिसार में माल का, लेकिन उपभोज्य स्टोर माल का उपयोग हिसार में माल के निर्माण के लिए नहीं किया गया था और वास्तव में उसी रूप में निपटाया गया था जिसमें उन्हें अंतर-राज्य व्यापार के दौरान बिक्री के पूर्व-मौजूदा अनुबंध के अनुसरण में खरीदा गया था या व्यापार। इन सामानों को अन्य राज्यों में इसकी शाखाओं में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसलिए, कंपनी उन सामानों को उनके तरीके से निपटाने की हकदार नहीं थी और इस तरह उसके दावे को अस्वीकार कर दिया गया था और केंद्रीय अधिनियम के तहत उन पर अंतर-कर लगाया गया था। बिक्री को केंद्रीय अधिनियम की धारा 3(ए) के अंतर्गत बताएं। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता कंपनी ने प्रोफार्मा ए और बी में अपेक्षित जानकारी प्रदान की है शाखा हस्तांतरण के संबंध में और खेप बिक्री और शाखा हस्तांतरण के संबंध में फॉर्म 'एफ' के साथ-साथ फॉर्म एसटी 1.7 में सूची जिसमें ऐसे प्रेषणों को कंसाइनर और कंसाइनी के शपथ पत्र के साथ दर्शाया गया है। जांच में पता चला कि शाखा में रुपये ट्रांसफर हुए हैं। स्टोर के सामान के लिए 17,30, 356 रुपये कानून के तहत स्वीकार्य नहीं थे। दूसरे, रुपये की खेप बिक्री। 25,34,74,734 को उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि डीलर ने सही साक्ष्य नहीं दिया था जो फॉर्म 'एफ' में घोषणा से स्पष्ट था। याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उठाए गए सवाल पर कि उसे उचित अवसर नहीं दिया गया था, जवाब दिया गया है मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान नोटिस भेजना एक सामान्य प्रक्रिया है और निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए। निर्धारिती द्वारा दिए गए उत्तर की जांच की जानी है और मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान निर्धारिती को सुनवाई का मौका दिया जाना है। कंपनी को 17 दिसंबर 1991 के लिए 10 दिसंबर 1991 को एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें यह कारण बताया गया था कि संपूर्ण शाखा हस्तांतरण/कंसाइनमेंट बिक्री को अस्वीकार क्यों न किया जाए और केंद्रीय अधिनियम के तहत अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर क्यों लगाया जाए। कंपनी ने 17 दिसंबर, 1991 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया। श्री एमएल गुप्ता, लेखा कार्यकारी भी लेखा विवरण आदि के साथ प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष उपस्थित हुए और मामले को 18 दिसंबर, 1991 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 17 दिसंबर, 1991 को एक और नोटिस दिया गया क्योंकि खाता पुस्तकों के साथ-साथ शाखा कार्यालयों को हस्तांतरित माल और खेप के आधार पर भेजे गए माल की जांच से पता चला कि स्टोर का माल रु। वर्ष 1988-89 के दौरान हरियाणा राज्य के भीतर समान खरीदने के बाद 17.30,356.26 को हरियाणा राज्य के बाहर विभिन्न शाखाओं में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं था और साथ ही मैसर्स जिंदल स्टील एजेंसी,

मद्रास को खेप की बिक्री भी थी। रुपये के लायक 18,89.37.392 और रु. मेसर्स ऑर्बिट स्टील (इंडिया) लिमिटेड बॉम्बे को 6,45,38,342, जांच के दौरान यह पाया गया कि दोनों एफ/आरएम अस्तित्व में नहीं थे। इस प्रकार, कंपनी को 18 दिसंबर, 1991 को प्रतिवादी संख्या 2/4 के समक्ष उपस्थित होकर यह बताना था कि शाखा हस्तांतरण/कॉन्गमेंट बिक्री से संबंधित लेनदेन को अंतर-राज्य बिक्री के रूप में क्यों नहीं माना जाना चाहिए। कंपनी के प्रतिनिधि की सुनवाई 18 दिसंबर, 1991 को हुई और उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की भी जांच की गई। चूंकि कंपनी मेसर्स जिंदल स्टील एजेंसी, मद्रास और मेसर्स ऑर्बिट स्टील (इंडिया) लिमिटेड बॉम्बे को माल की बिक्री के संबंध में लेनदेन के समर्थन में कानून के अनुरूप कोई ठोस सबूत या दस्तावेजी साक्ष्य देने में विफल रही। उपभोग्य वस्तुएं रायगढ़ (मध्य प्रदेश) और वासिंद की शाखाओं को भेजी गईं। जिला थाना में इन्हें अंतरराज्यीय बिक्री मानकर केंद्रीय अधिनियम के तहत टैक्स लगाया गया। टीटी ने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ता ने ऐसी जानकारी प्रस्तुत नहीं की जो भंडारण क्षमता की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए आवश्यक थी।

गोदाम के संबंध में किराया प्रमाण पत्र। वास्तव में, इसने यह दिखाने के लिए चतुराई से जानकारी दी कि माल को शाखा हस्तांतरण/खेप बिक्री के रूप में भेजा गया था, जो वास्तव में कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच में नहीं पाया गया था। 26 अक्टूबर, 1989 से 18 दिसंबर, 1991 तक कई अवसरों पर पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी कंपनी शाखा हस्तांतरण और खेप बिक्री की वास्तविकता साबित करने में बुरी तरह विफल रही। *दुर्भविना* के आरोपों का भी दृढ़ता से खंडन किया गया है। यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 का मूल्यांकन आदेश से कोई लेना-देना नहीं है और यह आरोप केवल प्रतिवादी 2/4 को कानून के अनुसार कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से लगाया गया है। विभिन्न प्रकरणों के संबंध में, जैसा कि याचिका में विस्तृत किया गया है, जिसके द्वारा कंपनी को सिविल न्यायालयों और अन्य मामलों में मामले दायर करने पड़े, यह कहा गया है, अकेले प्रतिवादी संख्या 3 से संबंधित है, उत्तरदाताओं 1, 2 और 4 ने कहा है कि वे इनमें से किसी से चिंतित नहीं थे और, विशेष रूप से, पैरा (ए) से (जी) में विस्तृत हैं।

(12) श्री श्री भंजन लाल-प्रतिवादी संख्या 3, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, ने अलग लिखित बयान दाखिल किया। इसमें दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ झूठे और *दुर्भविनापूर्ण आरोप लगाए हैं*। याचिकाकर्ता का पूरा हमला यह है कि उक्त प्रतिवादी ने मूल्यांकन प्राधिकारी पर उसके खिलाफ भारी मात्रा में बिक्री कर लगाने का निर्देश दिया था। यह दलील दी गई है कि कानून के अनुसार मूल्यांकन करना मूल्यांकन प्राधिकारी का कर्तव्य है और प्रतिवादी ने श्री जिंदल या उनकी कंपनी के खिलाफ अवैध कार्रवाई करने के लिए किसी को निर्देशित/दबाव नहीं दिया है। मूल्यांकन, जो उप-उत्पाद एवं कराराधान आयुक्त (संक्षेप में डीईटीसी) द्वारा किया गया था, उनके द्वारा हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत किया गया है और उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने मूल्यांकन प्राधिकारी को कोई मूल्यांकन करने का निर्देश नहीं दिया था। याचिकाकर्ताओं के पास न्यायाधिकरण तक अपील और उच्च न्यायालय और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय में संदर्भ के माध्यम से आदेश के खिलाफ उपाय था। स्थगन आवेदन और रिट याचिका में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित हैं। यह दलील दी गई है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप *दुर्भविनापूर्ण* और *दुर्भविनापूर्ण* थे क्योंकि वह श्री टिडल के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थे, जो कर के दायित्व से बचने के लिए झूठे आरोप लगा रहे थे। यदि श्री जिंदल ने किसी कानून के तहत कोई अपराध किया है या किसी कानून का उल्लंघन किया है, तो राज्य

के अधिकारी इससे निपटने के लिए सक्षम हैं और कानून के अनुसार उपाय व्यक्ति के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। उन्होंने कभी भी किसी प्राधिकारी से कोई कार्यवाही शुरू करने के लिए नहीं कहा। श्री भजन लाई का मामला यह भी है कि यह गलत है कि डीईटीसी उनके निर्देशों के तहत काम कर रहा था। उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला था;

याचिकाकर्ता कंपनी के व्यवसाय को पंगु बनाना। डीईटीसी एक वैधानिक प्राधिकरण था और राज्य अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर सकता था। यदि उसने बिक्री कर के निर्धारण के संबंध में याचिकाकर्ता कंपनी को कोई नोटिस दिया था, तो यह एक ऐसा मामला था जिसे प्राधिकरण को समझाया जा सकता था, जो कानून के अनुसार मामले का फैसला करेगा और यदि कोई शिकायत थी, तो वह ले सकता था। मामला अपील में आगे दलील दी गई है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता कंपनी के अध्यक्ष श्री ओपी जिंदल पर हिसार से विधायक के रूप में हरियाणा विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद उनके साथ हाथ मिलाने के लिए कोई दबाव नहीं डाला था। हालाँकि, यह स्वीकार किया गया है कि श्री ओपी जिंदल ने हरियाणा विकास पार्टी द्वारा दिए गए टिकट पर चुनाव लड़ा था। आगे दलील दी गई है कि लोकतांत्रिक चुनावों में कोई भी पार्टी किसी को भी टिकट देगी और यहां तक कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बिना टिकट के भी चुनाव लड़ सकता है। यह स्वीकार किया गया कि श्री ओपी महाजन हार गए, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन यह अप्रासंगिक था। यह आरोप कि प्रतिवादी ने घोषणा की थी कि वह श्री ओपी जिंदल को सबक सिखाएगा या उनकी कंपनी के खिलाफ *दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करेगा, का खंडन* किया गया है। डीईटीसी *अर्ध न्यायिक प्राधिकारी* होने के नाते, मूल्यांकन के संबंध में वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ऐसा करना उसका कर्तव्य था। यह पता लगाना भी उसका कर्तव्य था कि कंपनी उचित बिक्री कर का भुगतान कर रही है या नहीं। कर राजस्व है जो राज्य को उपलब्ध होता है और उस संबंध में राज्य अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना वैधानिक प्राधिकरण का कर्तव्य था। लिखित बयान में दिए गए *दुर्भावनापूर्ण* विशेष आरोपों के उत्तर को आगामी चर्चा में निपटाया जाएगा।

(13) इससे पहले कि मामला गुण-दोषों पर आगे बढ़े और संबंधित आदेशों की अवैधता या अन्यथा के संबंध में पक्षों की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील की दलीलों पर ध्यान दिया जाए, श्री एचएल सिब्बल द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति से निपटना उचित होगा, उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता ने कहा। उत्तरदाताओं के लिए वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के संबंध में। यह ज़ोर देकर तर्क दिया जा रहा है कि बिक्री कर अधिनियम, चाहे वह स्थानीय हो या केंद्रीय, एक संपूर्ण मशीनरी प्रदान करता है और अधिनियम के अंतर्गत गठित प्राधिकारियों को तथ्य के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए अंततः एकमात्र मध्यस्थ होने के नाते मामले का निर्णय करना होता है और जहाँ तक अधिनियमों का संबंध है अपील, पुनरीक्षण और संदर्भ का वैधानिक उपाय प्रदान करते हैं, याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिकाओं द्वारा मूल्यांकन प्राधिकारी के आदेशों को सीधे चुनौती देकर अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अपने पूर्वोक्त तर्क के लिए, विद्वान वकील *टिटासुर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड पर निर्भर हैं। उड़ीसा राज्य और अन्य*(1), *सहायक कलेक्टर*

(1) एआईआर 1983 एससी 603।

सेंट्रल एक्साइज, चंदन नगर, पश्चिम बंगाल बनाम *उनलप इंडिया लिमिटेड और अन्य*(2), *मेसर्स केबी हैंडीक्राफ्ट्स एम्पोरियम* बनाम *हरियाणा राज्य और अन्य*(3)।

(14) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शांति भूषण,

हालांकि, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के तर्क का खंडन करते हैं और इसके अलावा एल हृदय नारायण बनाम आयकर अधिकारी, बरेली (4), राम चंद्र सिंह पर भरोसा करते हैं। बनाम पंजाब राज्य और अन्य (5), राम एंड शाम कंपनी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (6), एम. जी. अबरोल, अतिरिक्त कलेक्टर सीमा शुल्क, बॉम्बे बनाम मैसर्स शांति छोटेलाल एंड कंपनी (7), मेसर्स जोहरमल मुरलीधर एंड कंपनी बनाम कृषि आयकर अधिकारी, असम और अन्य (8), मेसर्स फिल्टरको और अन्य बनाम सेल्स टैक्स कमिश्नर, एमपी और अन्य (9) और सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम टीजेल्हासनगर नगरपालिका वकील और अन्य (10) ने भी उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णयों को अलग करने का प्रयास किया है।

(15) टीटाघुर पेपर मिल्स कंपनी बनाम स्टेल ऑफ उड़ीसा और अन्य (11) मामले में, शीर्ष अदालत ने माना कि एक नागरिक को निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष अपील करने और आगे ट्रिब्यूनल में अपील करने और उसके बाद मामले को निपटाने के लिए कहने का अधिकार है। उच्च न्यायालय की राय के लिए कानून के एक प्रश्न पर कहा गया। इस प्रकार, अधिनियम, मूल्यांकन के आदेश को चुनौती देने के लिए एक पूरी मशीनरी प्रदान करता है, और मूल्यांकन के विवादित आदेशों को केवल अधिनियम द्वारा निर्धारित तरीके से चुनौती दी जा सकती है, न कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका द्वारा। आगे यह माना गया कि "यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त थी कि जहां एक अधिकार या दायित्व एक कानून द्वारा बनाया गया था जो इसे लागू करने के लिए एक विशेष उपाय देता है, उस कानून द्वारा प्रदान किए गए उपाय का ही लाभ उठाया जाना चाहिए"। उपरोक्त मामले के तथ्यों से पता चलता है कि दो विशेष अनुमति याचिकाएँ निर्देशित की गई थीं

- (2) एआईआर 1985 एससी 330।
- (3) जेटी 1993 (4) एससी 545।
- (4) एआईआर 1971 एससी 33.
- (5) एआईआर 1968 पंजाब 178।
- (6) एआईआर 1985 एससी 1147।
- (7) एआईआर 1966 एससी 197।
- (8) एआईआर 1970 एससी 1980।
- (9) एआईआर 1986 एससी 626।
- (10) वायु। 1971 एससी 1021.
- (11) वायु। 1983 एससी 603.

उड़ीसा उच्च न्यायालय के 18 मार्च, 1983 के एक आदेश के खिलाफ सहायक बिक्री कर अधिकारी कटक द्वारा 16 फरवरी, 198-3 को पारित मूल्यांकन के दो आदेशों को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। रिट याचिकाओं के माध्यम से, उक्त मामले में, याचिकाकर्ताओं ने सहायक बिक्री कर अधिकारी कटक द्वारा 16 फरवरी को पारित मूल्यांकन वर्ष 1980-81 के लिए केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत मूल्यांकन के आदेश की वैधता को चुनौती दी थी।, 1983. उच्च न्यायालय में उठाया गया तर्क

यह था कि मूल्यांकन के विवादित आदेश अमान्य होने के कारण, याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार को लागू करने के हकदार थे, लेकिन उच्च न्यायालय संतुष्ट नहीं था। यह अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी का मामला था। उच्च न्यायालय ने रिट को खारिज करते हुए इस प्रकार कहा: -

“पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, हम अपने असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत लागू आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि इसके खिलाफ अपील का अधिकार है। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि विवादित आदेश अमान्य होने के कारण हमारे असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करता है। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि यह अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी का मामला है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं है।”

-एसएलपी के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलें पूरी तरह से प्रक्रियात्मक अनियमितताओं या मूल्यांकन के गुणों पर आधारित थीं। मोटे तौर पर, विवाद यह था कि: (1) विद्वान बिक्री कर अधिकारी के पास याचिकाकर्ताओं द्वारा लौटाए गए सकल टर्नओवर को उनकी कर योग्य आय ए टर्नओवर मानने के लिए केंद्रीय बिक्री कर (उड़ीसा) नियम, 1957 के आर. 15 के तहत मूल्यांकन करते समय कोई अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं था। (2) रुपये की कटौती के दावे को अस्वीकार करना उचित नहीं था। 6,74,99,084.65 पंजीकृत डीलरों और सरकार के विभागों को बिक्री के साथ-साथ रु। 28,24,224.42 पी. अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान बिक्री के सकल कारोबार से खरीददारों से एकत्र किए गए कर के कारण रु। 7,13,94,903.63 पी., (3) उन्होंने याचिकाकर्ताओं को 4 प्रतिशत कर की रियायती दर का लाभ देने से केवल इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वे धारा 12 के फॉर्म 'सी', (4) में **अपेक्षित घोषणाएँ प्रस्तुत करने में विफल रहे।** उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 आंतरिक बिक्री के सकल कारोबार को रु. मानता है। 2,02,07,852.65 पी. जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने अपने कर योग्य टर्नओवर के रूप में लौटाया और न ही रुपये की कटौती के लिए उनके दावे को अस्वीकार करने को उचित ठहराया। 1,80,65,167.65 पी.

पंजीकृत डीलरों को बिक्री का प्रतिनिधित्व केवल इसलिए करना क्योंकि वे पंजीकृत डीलरों से निर्धारित घोषणाएँ प्रस्तुत करने में विफल रहे, (5) और विद्वान बिक्री कर अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के नियमों का घोर उल्लंघन किया क्योंकि याचिकाकर्ताओं को अपनी बात रखने के अवसर से वंचित कर दिया गया था। प्रश्न में मूल्यांकन वर्ष के लिए मामला।

(16) ऊपर दिए गए अनुसार याचिकाकर्ताओं के विवादों पर ध्यान देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार कहा: -

"यह कहना हमारे लिए नहीं है कि केंद्रीय बिक्री कर (उड़ीसा) के आर. 15 के तहत सर्वोत्तम निर्णय के लिए आगे बढ़ना विद्वान बिक्री कर अधिकारी के लिए उचित था या नहीं। नियम। 1957 और उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) के तहत। 1947 या क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा लौटाए गए सकल टर्नओवर को उनका कर योग्य टर्नओवर मानने में वह उचित थे या क्या वह प्रश्न में मूल्यांकन वर्ष के लिए दावा की गई कटौतियों को अस्वीकार करने में गलत थे। चीजों की प्रकृति में, ये वे प्रश्न हैं जिन्हें याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील में उठाना चाहिए।

इस प्रकार, उपरोक्त मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं को तुरंत खारिज कर दिया गया था, जिसके आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था और आक्षेपित आदेश को चुनौती, जैसा कि ऊपर बताया गया है, विवादों पर आधारित थी। , जो मुख्य रूप से निर्धारित करने के लिए अधिनियम के तहत गठित अधिकारियों के एकमात्र डोमेन में थे। यह इस संदर्भ में है कि सुप्रीम कोर्ट ने *रैले इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम गवर्नर जनरल इन काउंसिल* (1947) 74 इंडस्ट्रीज़ ऐप पर भरोसा करते हुए। 50 (एआईआर 1947 पीसी 78) में देखा गया कि जहां अधिनियम पूरी मशीनरी प्रदान करता है जो निर्धारिती को अदालतों में प्रभावी ढंग से उठाने में सक्षम बनाता है, मूल्यांकन की वैधता के सवाल को हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय के वैकल्पिक क्षेत्राधिकार से वंचित किया जाना चाहिए। हालाँकि, पैराग्राफ 7 में, *केएस वेंकटरमन एंड कंपनी बनाम मद्रास राज्य* (12) में अपने फैसले पर भरोसा करते हुए , एक वैकल्पिक उपाय को छोड़कर, यानी मूल्यांकन आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करना, जब चुनौती कानूनी अधिकार को दी गई थी। अधिनियम का, सनरेमे कोर्ट द्वारा ध्यान दिया गया था। हालाँकि, यह माना गया कि उक्त मामले के तथ्यों में अधिकार का कोई सवाल ही नहीं है

(121 एआईआर 1966 एससी 1989।

इसमें शामिल था और दूसरी ओर चुनौती केवल बिक्री कर अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की नियमितता के साथ-साथ सकल टर्नओवर को कर योग्य टर्नओवर मानने के अधिकार को लेकर थी। पैरा ग्राफ 10 में , *यूपी राज्य बनाम मोहम्मद नूह* (13) में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले से निपटने के दौरान , यह देखा गया कि उक्त निर्णय स्पष्ट रूप से अलग था क्योंकि उस मामले में अधिकार क्षेत्र की पूरी कमी थी और वर्तमान में मामले में ऐसा कोई सुझाव नहीं था कि बिक्री कर अधिकारी के पास मूल्यांकन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह भी देखा गया कि मामले

के मौजूदा तथ्यों के अनुसार यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया है क्योंकि उसे कार्यवाही की सूचना दी गई थी और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। मामला।

(17) ए इन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ टी सेंट्रल आई एक्साइज बनाम 'एमएलडनलोपकेआई लिमिटेड और अन्य (14) में, शीर्ष न्यायालय ने कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि "अनुच्छेद 226 शॉर्ट सर्किट या वैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए नहीं है। यह केवल वही है जहां वैधानिक नियम असाधारण स्थितियों की मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हैं, उदाहरण के लिए जहां कानून की मूल बातें प्रश्न में हैं या जहां निजी या सार्वजनिक गलतियाँ इतनी बुरी तरह से मिश्रित हैं और सार्वजनिक न्याय का उल्लंघन है यह पुनः सुनिश्चित करें कि संविधान के अनुच्छेद 226 का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन फिर न्यायालय के पास कानून द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय को पारित करने के लिए अच्छे और पर्याप्त कारण होने चाहिए। निश्चित रूप से, राजस्व से जुड़े मामले जहां वैधानिक उपचार उपलब्ध हैं, ऐसे मामले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकांश याचिकाएं 'केवल अंतरिम आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से झूठ बोलती हैं और उसके बाद किसी न किसी उपकरण द्वारा कार्यवाही को लम्बा खींचती हैं। इस प्रथा को दृढ़ता से हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।" सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के संबंध में वर्तमान में हम केवल इतना उल्लेख कर सकते हैं कि शीर्ष अदालत विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेशों के साथ-साथ याचिकाकर्ता कंपनी को अंतरिम रोक देने वाली डिवीजन बेंच के आदेशों के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी। कंपनी रुपये की छूट के लाभ का दावा कर रही थी। 6.05 करोड़ रुपये और कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रह करने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश की मांग की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि प्रथम दृष्टया मामला कंपनी के पक्ष में बनाया गया है और एक अंतरिम आदेश द्वारा रुपये की छूट का लाभ दिया गया। दो

(13) एआईआर 1958 एससी 86।

(14) एआईआर 1985 एससी 330।

करोड़ तिरानबे लाख और पचासी हजार किस राशि के लिए कंपनी को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, यानी, बैंक गारंटी प्रस्तुत किए जाने पर माल जारी करने का निर्देश दिया गया था। लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर द्वारा एक अपील दायर की गई थी और कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की थी, लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन किया गया था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर को दिया गया था। बैंक गारंटी का 30 प्रतिशत भुनाने की स्वतंत्रता।

(18) में . आईएनएस एम/एसईके. 11 बी. 2 हस्तशिल्पपीएमोरियम > वी. टीटीस्टेट ऑफ थ हर और अन्य (15), यह माना गया कि "न्यायालय तथ्य के सवाल और इस सवाल पर नहीं जा सकता कि क्या कोई विशेष बिक्री एक अंतर-राज्य बिक्री थी, एक अंतरराज्यीय बिक्री, धारा 5(1) के अर्थ के भीतर एक निर्यात बिक्री या धारा 5(3) के अर्थ के भीतर अंतिम बिक्री या

अन्यथा, हमेशा तथ्य का एक प्रश्न था जिसका निर्णय उचित प्राधिकारी द्वारा किया जाना था। न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का प्रकाश। उपरोक्त मामले के तथ्यों से पता चलता है कि प्रश्न में मूल्यांकन वर्ष के लिए हरियाणा के बिक्री कर अधिकारियों ने *मैसर्स मनोहर एंड* में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के बाद याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कच्चे माल की खरीद पर खरीद कर लगाया। *कंपनी, पानीपत और अन्य* बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 के तहत। 1973. हालाँकि, निर्धारण प्राधिकारी ने फॉर्म एच के विरुद्ध निर्यात किए गए माल के खरीद मूल्य के संदर्भ में कर की गणना की। याचिकाकर्ताओं ने अपील दायर करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि इस आधार पर रिट याचिका के माध्यम से सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुरली मनोहर मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, उस राज्य में अधिनियम के तहत उपायों को अपनाने का कोई मतलब नहीं था। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। मुरली मनोहर के मामले का निपटारा 25 अक्टूबर, 1990 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था और जिसे उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, यह मामला *मुरली मनोहर के मामले (सुप्रा) में दिए गए निर्णय में शामिल नहीं था, जिस मामले का निर्णय न्यायालय द्वारा गुडइयर इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (16) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर किया गया था।*). हालाँकि, *गुडइयर के मामले (सुप्रा)* में दिया गया निर्णय आया

(15) जेटी 1993 एससी 545।

(16) जेटी 1989 (4) एससी 229।

होटल बालाजी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (17) मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार किया गया और उसमें यह माना गया कि गुडइयर का मामला सही कानून नहीं बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 6 में कहा कि "मुरली मनोहर के तथ्य काफी हद तक मौजूदा मामले के तथ्यों के समान थे"। ऊपर उल्लिखित तथ्यों की पृष्ठभूमि में, सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका में, तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। यह प्रश्न कि क्या कोई विशेष बिक्री एक अंतर-राज्य बिक्री थी, एक अंतर-राज्य बिक्री, धारा 5(1) के अर्थ में एक निर्यात बिक्री या धारा 5(3) के अर्थ में अंतिम बिक्री या अन्यथा, हमेशा एक था तथ्य का प्रश्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में उचित प्राधिकारी द्वारा तय किया जाना है.. फिलहाल, केवल यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त मामले में याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में सीधे संविधान ने मूल रूप से तर्क दिया कि उसका मामला पूरी तरह से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले द्वारा कवर किया गया था, जो बदले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित था।

(19) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री शांति भूषण कला के तहत इस याचिका की विचारणीयता पर उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के साथ गंभीर मुद्दे में शामिल हो गए हैं। हालाँकि, संविधान का 226 यह स्वीकार करता है कि कानून अपील, संशोधन और संदर्भ प्रदान करता है। हालाँकि, उनका तर्क यह है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, कला के तहत निहित अपने असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 . उनका तर्क है कि इस मामले को 1992 में यानी लगभग तीन साल पहले इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा तय किया गया माना गया था। पहली याचिका (सं. 1898 सन् 1992) 1 फरवरी 1992 को स्थापित की गई थी। इसके बाद, इस न्यायालय में दो बाद की याचिकाएँ दायर की गईं जिन्हें पहले की रिट (19921 की सीडब्ल्यूपी 1898) के साथ सुनने का आदेश दिया गया था। तीसरी याचिका में मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अतिरिक्त देनदारी पर रोक लगा दी गई थी, जबकि दूसरी याचिका में उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक हटाने के आदेश को रद्द कर दिया गया था, इस प्रकार, इस पूरे समय के लिए, के पक्ष में एक पूर्ण और व्यापक रोक लगाई गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं को वैकल्पिक उपाय के लिए बाध्य करना पूरी तरह से अनुचित होगा, खासकर जब उनके खिलाफ *दुर्भावना के गंभीर आरोप हों*।

(17) जेटी 1992 (2) एससी 182।

वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजन लार्ड, जो उक्त पद पर बने हुए हैं और मुख्य आरोप यह है कि न केवल विवादित आदेश बल्कि याचिकाकर्ताओं और श्री ओपी जिंदल पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कई अन्य आदेश अधिकारियों द्वारा प्रमुख के आदेश और आदेश पर पारित किए गए थे। मंत्री. आगे यह तर्क दिया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान की गई विभिन्न न्यायिक घोषणाओं द्वारा वैधानिक प्रावधानों और तय किए गए कानून के आधार पर, अधिकारियों ने शाखा हस्तांतरण और खेप बिक्री को अंतरराज्यीय बिक्री के रूप में रखने में स्पष्ट रूप से गलती की है। कानून की स्थिति स्पष्ट होने के कारण, याचिकाकर्ताओं को अपीलीय मंच पर भेजना सही नहीं होगा, क्योंकि इस मामले की चीजों और तथ्यों और परिस्थितियों की प्रकृति में, यह एक से दूसरे प्रतिबंध का उपाय होगा। (इस प्रकार; सीज़र से सीज़र की पत्नी) यह भी तर्क दिया जा रहा है कि यदि कानून ऐसा उपचार प्रदान करता है तो किसी पक्ष को वैकल्पिक उपचार के लिए पदावनत करने का कोई/असाधारण और एक समान फार्मूला नहीं हो सकता है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय अच्छा होगा। किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने की उसकी शक्तियों के अंतर्गत। उनके तर्कों के लिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान वकील ने एल *हृदय नारायण* बनाम *आयकर अधिकारी, बरेली* (19) का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "जब उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर विचार किया और गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की, तो याचिका खारिज कर दी गई।" इसके बाद इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि वैधानिक उपाय का लाभ नहीं उठाया गया।" उक्त मामले के तथ्यों से पता चलता है कि हृदय नारायण और उनके पांच बेटे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य थे। निर्धारण वर्ष 1950-51 तक हृदय नारायण द्वारा प्राप्त आय पर हिंदू अविभाजित परिवार की आय के रूप में कर निर्धारण किया जाता था। 19 नवंबर, 1949 को हृदय नारायण और उनके बेटों के बीच संयुक्त परिवार की संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया। निर्धारण वर्ष 1951-52 के लिए आय का आकलन करते समय आयकर अधिकारी ने आदेश पर दर्ज किया कि संपत्ति का विभाजन किया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हृदय नारायण द्वारा प्राप्त आय का मूल्यांकन एक हिंदू अविभाजित परिवार की आय के रूप में किया। अपील में, अपीलीय सहायक आयुक्त ने रु. पूर्व हिंदू की आय के रूप में 1 अक्टूबर, 1949 और 18 नवंबर, 1949 के बीच 18,520 रुपये की कमाई हुई! अविभाजित परिवार और निर्देश दिया कि इसे मूल्यांकन से बाहर रखा जाए। इसके अनुसरण में, आयकर अधिकारी ने मूल्यांकन के दो आदेश दिए- (1) रुपये का आकलन करना। हिरदे नारायण और उनके पांच बेटों के हिंदू अविभाजित परिवार की आय के रूप में 18,520; और (2) रुपये का आकलन करना. 1,06,156 भी एक हिंदू अविभाजित परिवार की आय के रूप में और आवेदन द्वारा हृदय नारायण के हाथों कर के लिए उत्तरदायी है

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 16(3)(ए)(ii) के तहत। हृदय नारायण ने तब मूल्यांकन के क्रम में एक गलती के सुधार के लिए आवेदन किया था, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि यह रिकॉर्ड से स्पष्ट है, लेकिन आयकर अधिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यह कहते हुए राहत दें कि 19 नवंबर, 1949 से 30 सितंबर, 1960 की अवधि के लिए हृदय नारायण का मूल्यांकन एक व्यक्ति के रूप में किया जाना चाहिए था। हृदय नारायण ने आयकर अधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की। उक्त उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मूल मूल्यांकन के चरण में, यह प्रश्न कि आय आयकर अधिनियम की धारा 16(3)(ए)(ii) के तहत मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी नहीं थी, थी। नहीं उठाया गया और निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 33-ए के तहत आयुक्त को संशोधन में आवेदन नहीं किया था। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अपील में उस आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 35 के तहत सुधार विवेकाधीन था और यदि आयकर अधिकारी को लगता है कि कार्यवाही काफी हद तक निष्पक्ष थी, तो वह तकनीकी आधार पर मूल्यांकन को सुधारने के लिए बाध्य नहीं था। इसके बाद हृदय नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। वैकल्पिक उपाय की आपत्ति से निपटते समय, सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 12 में कहा कि “आयकर अधिनियम की धारा 35 के तहत एक आदेश अपील योग्य नहीं है। यह सच है कि आदेश को संशोधित करने के लिए आयकर आयुक्त के समक्ष याचिका दायर की जा सकती है। लेकिन हृदय नारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर विचार किया। यदि उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर विचार नहीं किया होता, तो हृदय नारायण आयुक्त के पास पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते थे क्योंकि जिस तारीख को याचिका दायर की गई थी, उस समय अधिनियम की धारा 33-ए द्वारा निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हुई थी। हम यह मानने में असमर्थ हैं क्योंकि धारा 35 के तहत आयकर अधिकारी के आदेश को सही करने के आदेश के लिए एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया जा सकता था, लेकिन दायर नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज करना उचित होगा क्योंकि यह याचिका थी मनोरंजन किया गया और गुण-दोष के आधार पर सुना गया।”

(20) *राम चंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य* (20) में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने माना कि वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता की दलील रिट याचिका की स्थिरता के लिए पूर्ण बाधा नहीं थी और याचिका पर तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाना था। प्रत्येक मामले में, "उपरोक्त मामले के तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र, उस मामले में, अध्यक्ष पद के लिए

(21) एआईआर 1968 पंजाब 178।

सोसायटी के सदस्यों को अस्वीकार कर दिया गया। सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के खिलाफ *दुर्भावना और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रियों के अनुचित प्रभाव* के आरोप थे और याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय से निर्णय चाहता था। उक्त मामले में उत्तरदाताओं की दलील कि रिट को खारिज

कर दिया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने अधिनियम के तहत उपलब्ध वैधानिक उपाय का लाभ नहीं उठाया था, यह देखते हुए खारिज कर दिया गया कि "इस मामले की परिस्थितियों में, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है" इस विवाद में कोई भी ताकत. यह आधिकारिक रूप से माना गया है कि वैकल्पिक मूल उपचार की उपलब्धता की दलील रिट याचिका की स्थिरता के लिए पूर्ण बाधा नहीं है और उक्त याचिका का निर्णय तथ्यों और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जहां इसे उठाया गया है। इस मामले की परिस्थितियों में जब याचिकाकर्ता चाहता था कि यह न्यायालय रजिस्ट्रार और स्वयं मंत्री के खिलाफ *दुर्भावनापूर्ण* आरोप पर सुनवाई करे और निर्णय दे, तो उसके लिए धारा 55 द्वारा प्रदान किए गए उपाय का सहारा लेना पूरी तरह से भ्रामक होता। रिटर्निंग अधिकारी के आक्षेपित आदेश के खिलाफ अपील में रजिस्ट्रार के पास जाकर अधिनियम का उल्लंघन। न ही राज्य सरकार के लिए संशोधन के माध्यम से उपाय एक दिखावा के अलावा कुछ भी होगा यदि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए जाने वाले मुख्य आरोपों में से एक यह था कि याचिकाकर्ता के हितों के खिलाफ मंत्री द्वारा स्वयं अनुचित प्रभाव डाला गया था। आगे यह देखा गया कि "अधिनियम की धारा 55(2) के तहत अपील करने का समय समाप्त हो गया है, हम तकनीकी आधार पर मामले में याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करना उचित नहीं समझते हैं।" यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि डिवीजन *दुर्भावना* के आरोपों से निपटते समय। बेंच ने कहा कि कोर्ट के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने *दुर्भावना* या हस्तक्षेप के कारण याचिकाकर्ता को सोसायटी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने से बाहर कर दिया। मंत्री. इस तरह निपटाया गया मामला:-

“रिटर्निंग ऑफिसर न केवल अपनी *दुर्भावना* से इनकार कर रहा है, बल्कि यह भी आरोप लगा रहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा उसके खिलाफ लगाया गया आरोप *दुर्भावनापूर्ण* है। हमारे सामने रखी गई सामग्री पर मैं ऐसा नहीं सोचता। यह मानना संभव है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी *दुर्भावना* या मंत्री के हस्तक्षेप के कारण याचिकाकर्ता को अध्यक्ष के पद की दौड़ से बाहर कर दिया। याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र के समर्थन की वैधता के सवाल पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय से याचिकाकर्ता द्वारा किए गए इस आशय के दावे को कुछ समर्थन मिलता प्रतीत होता है कि कुछ लोगों के लिए

किसी न किसी कारण से रिटर्निंग अधिकारी याचिकाकर्ता को प्रतियोगिता से बाहर करने के इच्छुक थे। इस मामले पर अंतिम फैसला देना जरूरी नहीं है।'

(22) *राम और श्याम कंपनी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य* (21) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "आमतौर पर यह सच है कि न्यायालय ने कला के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर अपने विवेक से प्रतिबंध लगाया है। 226 जहां अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाले पक्ष के पास वैकल्पिक, प्रभावी पर्याप्त उपाय है। अक्सर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस नियम के लिए वैकल्पिक उपचारों की आवश्यकता होती है वह कानून के शासन के बजाय सुविधा और विवेक का नियम है। किसी भी कीमत पर यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को खत्म नहीं करता है। जहां शिकायत किए गए आदेश को कानून के विपरीत होने के कारण अवैध या अमान्य माना जाता है, तो इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति के अनुरोध पर एक याचिका कला के तहत उच्च न्यायालय में दायर की जाएगी। 226 और ऐसी याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि अपील उच्च अधिकारी या राज्य सरकार के पास है। यह नहीं कहा जा सकता कि सभी मामलों में अपील क्षेत्राधिकार और योग्यता के बीच अच्छे अंतर को अलग रखते हुए सभी स्थितियों में एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय प्रदान करती है। उपरोक्त मामले के तथ्यों से पता चलता है कि लघु खनिजों को जीतने के लिए पट्टा देने की शक्ति का प्रयोग औपचारिक रूप से नियमों के तहत स्थापित प्राधिकरण द्वारा किया गया था, लेकिन प्रभावी ढंग से और सभी उद्देश्यों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। उपरोक्त परिस्थितियों में यह माना गया कि राज्य सरकार के लिए अपील अप्रभावी होगी और ऐसे मामले में एक रिट सुनवाई योग्य होगी।

(23) *अतिरिक्त सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम मैसर्स शांति लाई छोटे लाल एंड कंपनी* (22) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने, जहां समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जल्दी और बड़ा जुर्माना लगाने का मामला शामिल था, माना कि "उपाय के माध्यम से" ऐसे आदेश के खिलाफ अपील एक प्रभावी उपाय नहीं है क्योंकि कोई भी अपील तब तक दायर नहीं की जा सकती जब तक कि याचिकाकर्ता पर लगाया गया बड़ा जुर्माना पहले जमा नहीं किया जाता है।" उक्त मामले में फर्म ने आयरन एंड स्टील कंट्रोलर से एक निर्यात लाइसेंस प्राप्त किया था, जिसमें उन्हें बॉम्बे के बंदरगाह से 900 टन लंबे स्टील स्कल स्क्रेप के निर्यात की अनुमति दी गई थी। फर्म ने विभिन्न स्रोतों से रुपये से भिन्न दरों पर स्क्रेप लोहा खरीदा था। 95 से रु. 207 प्रति टन. सामान को गोदी में लाने के बाद, आयरन एंड स्टील नियंत्रक द्वारा अधिकृत अधिकारी और

(21) एआईआर 1985 एससी 1147।

(22) एआईआर 1966 एससी 197।

क्षेत्रीय संयुक्त स्क्रेप समिति के प्रतिनिधि ने माल को उक्त निर्यात लाइसेंस के तहत निर्यात के लिए उपयुक्त स्टील स्कल स्क्रेप के रूप में प्रमाणित किया और उक्त माल के संबंध में शिपिंग बिलों पर इस आशय के आवश्यक समर्थन किए गए। इसके बाद माल को निर्यात करने के उद्देश्य से सीमा शुल्क अधिकारियों के पास ले जाया गया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने यह विचार किया कि माल का हिस्सा स्टील स्कल स्क्रेप नहीं था और मामला आयरन एंड स्टील नियंत्रक को भेजा गया था। 18 मार्च, 1957 के आदेश के द्वारा, नियंत्रक ने सीमा शुल्क

अधिकारियों को सूचित किया कि अस्वीकृत बफ़र्स, प्लंजर और केसिंग भट्टी के अस्वीकृत थे और खोपड़ी के स्क्रेप आदि का हिस्सा थे। 26 मार्च, 1957 के आदेश के अनुसार सीमा शुल्क अधिकारियों ने बोर्ड पर मौजूद पूरा माल जब्त कर लिया। समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 178 के तहत जहाज, लेकिन उक्त अधिकारियों ने माल को शिपर्स की अस्थायी हिरासत में रहने की अनुमति दी। उन्होंने माल से संबंधित दस्तावेज़ भी अपने पास रख लिए, लेकिन बाद में 25 अप्रैल, 1957 को फर्म द्वारा रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर उन्हें रिहा कर दिया। 49,995.75 27 मई 1957 को सीमा शुल्क अधिकारियों ने फर्म को यह बताने के लिए नोटिस दिया कि क्यों न उक्त सामान को जब्त कर लिया जाए और अधिनियम की धारा 167(8) और (37) के तहत उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सीमा शुल्क के अतिरिक्त कलेक्टर ने 21 दिसंबर, 1957 के आदेश द्वारा माना कि भेजी गई कुल मात्रा में से 320 टन अनधिकृत थी और उसे जब्त करने का निर्देश दिया गया, लेकिन रुपये का जुर्माना लगाया गया। जब्त की एवज में 49,995.95 रुपये और व्यक्तिगत जुर्माना लगाया गया। 35,000. उपरोक्त आदेशों को रद्द करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट दायर की गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने, भले ही याचिकाकर्ता के खिलाफ फैसला सुनाया, लेकिन रुपये के व्यक्तिगत दंड को कम करके सीमित राहत की अनुमति दी। 35,000 से रु. 1,000. डिवीजन बेंच में की गई अपील में मामला याचिकाकर्ता के पक्ष में तय किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश निरस्त कर दिया गया। डिवीजन बेंच के उक्त आदेश के खिलाफ ही कस्टम कलेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। सीमा शुल्क कलेक्टर द्वारा उठाए गए वैकल्पिक उपाय की दलील पर, एओएक्स कोर्ट ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

“अंत में, यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। चूंकि उत्तरदाताओं के पास उच्च सीमा शुल्क अधिकारियों के पास अपील के माध्यम से एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय था, लेकिन उच्च न्यायालय ने ठीक ही बताया कि उत्तरदाताओं के पास कोई प्रभावी उपाय नहीं था, क्योंकि तब एक शर्त के रूप में जमा किए बिना अपील दायर नहीं कर सकता था।

उन पर बड़ी मात्रा में जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, एक प्रभावी उपाय का अस्तित्व उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करता है, लेकिन यह केवल उन परिस्थितियों में से एक है जिसे अदालत को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए। इस सहजता में उच्च न्यायालय ने कला के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना उचित समझा। संविधान की धारा 226 और हमें इसके विवेक में हस्तक्षेप करने वाली कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दिखती है।”

(23) मेसर्स *जोहरमल मुरलीधर एंड कंपनी बनाम कृषि आयकर अधिकारी और अन्य* (23) में, वैकल्पिक उपाय की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "यह निश्चित रूप से निर्धारिती को राहत देने से इनकार करने का एक अच्छा आधार है लेकिन फिर भी, इसमें शामिल रकम और निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सबूत की सरल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नानुसार निर्देशित करते हैं: -

“आकलन अधिकारी करदाता को एक नया नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों के लिए अपने आयकर मूल्यांकन आदेश प्रस्तुत करने के लिए कहा

जाएगा। निर्धारिती को नोटिस प्राप्त होने के एक महीने के भीतर उन आदेशों को प्रस्तुत करना होगा। यदि वह उन आदेशों को प्रस्तुत करता है, तो विवादित मूल्यांकन आदेश रद्द कर दिए जाएंगे और मूल्यांकन अधिकारी नए सिरे से निर्धारिती का मूल्यांकन करेगा। यदि निर्धारिती उन आदेशों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो लगाए गए मूल्यांकन आदेश मान्य रहेंगे और उन आदेशों के आधार पर आगे कदम उठाए जा सकते हैं।

(24) मेसर्स *फ़िल्टरको और अन्य* बनाम *बिक्री कर आयुक्त और अन्य* (24) में, जहां उच्च न्यायालय ने याचिका को प्रारंभिक रूप से खारिज कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा था कि "हमारी राय है कि उच्च न्यायालय को ऐसा करना चाहिए था रिट याचिका को उसी तरीके से खारिज करने के बजाय मामले की खूबियों की जांच की, जिस तरह से उसने किया है। बिक्री कर आयुक्त द्वारा पारित आदेश धारा 42बीएफ01 के तहत कर निर्धारण प्राधिकारी पर स्पष्ट रूप से बाध्यकारी था और तकनीकी होते हुए भी यह अपीलकर्ताओं के लिए अपीलिय प्राधिकारी अर्थात् अपीलिय सहायक आयुक्त के समक्ष अपनी दलीलें पेश करने के लिए खुला होता, जो कि एक मात्र आदेश होता। यह निरर्थक है जब एक वरिष्ठ अधिकारी, अर्थात् आयुक्त, ने पहले ही अपने वैधानिक अभ्यास में एक तर्कसंगत आदेश पारित कर दिया है

(231 एआईआर 1970 एससी 1080।

(24) एआईआर 1986 एससी 626,

अधिनियम की धारा 42-बी की उप-धारा (1) के तहत क्षेत्राधिकार यह मानता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित संपीडित ऊनी कपड़े की 21 किस्में अधिनियम की अनुसूची I की प्रविष्टि 6 के तहत टूट के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा अधिनियम की धारा 38(3) के अनुसार अपील या पुनरीक्षण दायर करने से पहले कर का एक बड़ा हिस्सा जमा करना होगा। ऐसी परिस्थितियों में हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय को पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों के गुण-दोष पर विचार करना चाहिए था और फैसला सुनाना चाहिए था और रिट याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करना उचित नहीं था। ऐसी स्थिति में, हालांकि हम आमतौर पर उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर देते और मामले को नए सिरे से निपटान के लिए उस न्यायालय में भेज देते, हम मानते हैं कि वर्तमान मामले में यह दोनों पक्षों के हित में होगा वर्तमान चरण में इस न्यायालय द्वारा अंततः मामले का निर्णय लिया गया, विशेषकर तब जब हमें दोनों पक्षों के वकील द्वारा संबोधित विस्तृत और विद्वतापूर्ण तर्कों का लाभ मिला है।

(25) *सेंचुरी ' स्पिनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी बनाम द ल्लशासनगर म्युनिसिपल काउंसिल और अन्य* (25) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "उच्च न्यायालय, अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। यदि याचिकाकर्ता ऐसा दावा करता है जो तुच्छ, कष्टप्रद, या *प्रथम दृष्टया* अन्यायपूर्ण है, या असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करने वाली याचिका में उचित रूप से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, तो न्यायालय याचिका पर विचार करने से इनकार कर सकता है। लेकिन एक पक्ष जो किसी सार्वजनिक निकाय या प्राधिकरण की कार्रवाई से व्यथित होने का दावा करता है और कहता है कि कार्रवाई गैरकानूनी, मनमानी, मनमानी या अन्यायपूर्ण है, वह योग्यता के आधार पर अपनी याचिका पर सुनवाई का हकदार है।" उक्त मामले में मामला चुंगी शुल्क से संबंधित था और बिना कोई कारण बताए रिट याचिका को

खारिज करना शीर्ष न्यायालय द्वारा अनुचित माना गया था।

(26) ऊपर बताए गए विभिन्न न्यायिक उदाहरणों के आधार पर, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी याचिका पर विचार न करने के लिए वैकल्पिक देशी उपचार की क्षमता का लाभ उठाना सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं हो सकता है। यह सच है कि आम तौर पर जब क़ानून एक वैकल्पिक उपाय प्रदान करता है, और विशेष रूप से जब पार्टियों के अधिकारों पर निर्णय लेने के लिए पूरी मशीनरी होती है, जो बड़े पैमाने पर तथ्यों पर निर्भर करती है, तो उच्च न्यायालय को अधिकारों पर निर्णय लेने से बचना चाहिए पक्ष लेकिन इस सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं और एक नागरिक, जो इनमें से किसी एक में भी अपना मामला सफलतापूर्वक कवर कर सकता है

(25) एआईआर, 1971 एससी 10211

अपवाद स्वरूप, उसे उच्च न्यायालय में प्रवेश का निकास द्वार नहीं दिखाया जा सकता और संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कुछ अपवाद जिनके तहत कोई याचिका वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाए बिना उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत झूठ बोल सकती है, जब क़ानून के प्रावधानों को संविधान के दायरे से बाहर या अधिनियम के प्रतिकूल होने पर चुनौती दी जाती है। जाहिर है, अपील या पुनरीक्षण पर विचार करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले अधिनियम के तहत गठित प्राधिकारी, चाहे वे विभाग के पदानुक्रम में कितने भी ऊंचे क्यों न हों, अधिनियम/क़ानून के प्रावधानों को अधिकारातीत होने के कारण रद्द नहीं कर सकते हैं / वे अधिनियम और उसमें निहित प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। दूसरा अपवाद तब होता है जब अधिनियम के तहत सर्वोच्च प्राधिकारी ने कानून के प्रश्न पर एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया हो और उक्त दृष्टिकोण सभी अधीनस्थ अधिकारियों को ज्ञात हो, साथ ही जब उच्च न्यायालय या न्यायालय द्वारा कोई भिन्न या विपरीत दृष्टिकोण व्यक्त नहीं किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट. ऐसी स्थिति में, अपील या पुनरीक्षण का उपाय एक ऐसा उपाय होगा जिसे लोकप्रिय रूप से सेज़र टू सेज़र या पोल से पोल के रूप में जाना जाता है। अधीनस्थ प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, अपील या पुनरीक्षण से निपटने के लिए अधिनियम के तहत गठित विभाग में सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण का पालन करने के लिए बाध्य हैं। तीसरा अपवाद तब हो सकता है जब जिस आदेश की शिकायत की गई हो। पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना है। ऐसा आदेश आम तौर पर तब होता है जब यह क़ानून के प्रावधानों के पूरी तरह से विपरीत होता है या जब अधिनियम के तहत गठित अधिकारियों के पास आदेश पारित करने की कोई शक्ति नहीं होती है। फिर भी एक और अपवाद तब हो सकता है जब आदेश राज्य के सर्वोच्च गणमान्य व्यक्तियों के बाहरी विचारों या दुर्भावना पर लागू किए जाते हैं और आरोप तुच्छ नहीं होते हैं और इसके विपरीत, प्रथम दृष्टया, अस्तित्व में दिखाए जाते हैं। एक और अपवाद तब हो सकता है जब वैकल्पिक उपचार समान रूप से प्रभावकारी न हो। फिर भी एक और अपवाद तब हो सकता है जब मामले का निर्णय सीमा पर नहीं किया जाता है और इसे सुनवाई के लिए कई 'मार्च' के बाद लिया जाता है और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है और इस बीच अपील दायर करने के लिए क़ानून के तहत निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त हो गई है। अपवादों को कई गुना बढ़ाया जा सकता

है लेकिन न्यायालय अपवादों का विस्तृत विवरण नहीं देना चाहता। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कुल मिलाकर, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

(27) वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह देखा जाएगा कि पहली याचिका डीआर में स्वीकार की गई थी और चूंकि बाद की दो याचिकाओं को उसके साथ निपटाया जाना था (199 का सीडब्ल्यूपी 1898?i, सभी याचिकाएं सुनवाई के लिए आ गई हैं) हमारे सामने। आम तौर पर, एक रिट याचिका, स्वीकार करने के बाद, एकल पीठ में सुनवाई की जाती है, लेकिन स्वीकार करने वाली पीठ ने मुख्य रूप से इसे या तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित *दुर्भावना* के कारण महत्वपूर्ण मामला माना या

मामले में शामिल कानून बिंदुओं के कारण या दोनों के कारण। मामलों को डीबी में स्वीकार करने का जो भी कारण रहा हो, सच्चाई यह है कि मामले इस न्यायालय के समक्ष तीन साल की अवधि से लंबित हैं और पक्षों द्वारा लगभग इस अवधि में विस्तृत मौखिक और लिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं। छह महीने की, वास्तविक सुनवाई लगभग 15 दिनों की होती है। मामले की लगातार सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि पक्षों के विद्वान वकील मामले पर एक बार में बहस करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, शाखा हस्तांतरण को कंसाइनमेंट बिक्री के रूप में अंतर-राज्यीय बिक्री के रूप में रोककर याचिकाकर्ता कंपनी पर भारी कर लगाया गया है। हमें बताया गया है कि लगातार तीन वर्षों की अवधि के लिए लगाया गया कर लगभग बीस करोड़ होगा। निस्संदेह, अधिनियम के प्रावधानों के तहत गुण-दोष के आधार पर अपील की सुनवाई के लिए कर जमा करना एक शर्त है, चाहे वह राज्य अधिनियम हो या केंद्रीय अधिनियम। हम इस तथ्य के प्रति काफी सचेत हैं कि अपीलीय प्राधिकारी के लिए स्थगन के लिए एक आवेदन पर विचार करना और अपील के लंबित रहने के दौरान उसे मंजूर करना स्वीकार्य है, लेकिन हम इस तथ्य के प्रति भी उतने ही सचेत हैं कि अधिकांश मामलों में ऐसा स्थगन नहीं है। दी गई है और यदि दी गई है तो वह सशर्त है।

(28) उनके मुख्य प्रश्नों में से एक यह है कि क्या लेन-देन शाखा हस्तांतरण या खेप बिक्री या अंतर-राज्यीय बिक्री का था, हम यहां बाद में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, सिद्धांतों सहित विभिन्न आधारों पर मामले को आकलन प्राधिकारी को भेजने जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं को सबूत पेश करने की अनुमति देने के लिए संबंधित अधिकारियों को आगे दिए गए निर्देश के साथ प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं किया गया। ऐसा पाठ्यक्रम केवल मूल्यांकन प्राधिकारी के लिए ही सुविधाजनक है और इस कारण से भी हम इस स्तर पर याचिकाकर्ता को अपील के वैकल्पिक उपाय के लिए बाध्य नहीं करना चाहते हैं। श्री सिब्ल द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति। उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का कहना था कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ताओं के लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, जिसे खारिज कर दिया गया।

(29) सबसे पहले शाखा हस्तांतरण से निपटते समय, उन बुनियादी कारणों को एक बार फिर से देखना उचित होगा जिनके आधार पर कंपनी द्वारा दावा किए गए उक्त हस्तांतरण को अंतर-राज्यीय बिक्री माना गया था। बिक्री कर प्राधिकरण का मानना है कि यह जिंदल स्टील्स लिमिटेड द्वारा एसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र का दुरुपयोग था, जहां तक कि उन्होंने फॉर्म 'सी*' में दी गई घोषणा पर स्टोर का सामान खरीदा था कि उन सामानों का उपयोग उनके द्वारा किया जाएगा। बिक्री के लिए माल के निर्माण या प्रसंस्करण में। जिनका उपयोग करने के बजाय मेसर्स

जिंदल स्टील्स लि

हरियाणा में अपने कारखाने में माल को दूसरे राज्यों में अपने कारखानों में ले जाया गया ताकि उन राज्यों में माल के निर्माण में उपयोग किया जा सके। इस प्रकार, मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार, माल का उपयोग केवल हिसार में किया जाना आवश्यक था। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का मूल तर्क यह है कि न तो धारा 8 (3) (बी) और न ही नियम 12 (1) और न ही फॉर्म 'सी' में घोषणा के निर्धारित प्रारूप में केवल राज्य में माल के उपयोग पर कोई प्रतिबंध है और . इसलिए, पंजीकरण प्रमाणपत्र का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि भले ही फॉर्म 'सी' में घोषणा का दुरुपयोग हुआ हो, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा सामान खरीदा गया था, वह उन सामानों की खेप को अपनी शाखाओं में परिवर्तित नहीं करेगी। अन्य राज्यों को बिक्री में शामिल करना ताकि बिक्री कर प्राधिकरण को केंद्रीय अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत उन वस्तुओं के मूल्य पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया जा सके। विद्वान वकील का तर्क है कि घोषणा के दुरुपयोग के मामले में प्राधिकरण के लिए एकमात्र विकल्प या तो धारा 10 (डी) के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी या केंद्रीय अधिनियम की धारा 10-ए के तहत अभियोजन के बदले जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय अधिनियम की धारा 8, जहां तक प्रासंगिक है, इस प्रकार है: -

"8(1).-प्रत्येक डीलर, जो अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान:-

(a) -----

(b) उपधारा (3) में उल्लिखित विवरण के सरकारी सामान के अलावा किसी पंजीकृत डीलर को बेचना है। इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो उसके टर्नओवर का (चार प्रतिशत) होगा।

8(3)(बी).- पंजीकृत डीलर के पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के सामान हैं जो सामान खरीदते हैं, जैसा कि उनके द्वारा पुनर्विक्रय के लिए इरादा है या इसमें केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन है। बिक्री के लिए माल के निर्माण या प्रसंस्करण में उसके द्वारा उपयोग के लिए

8(4) उपधारा (1) के प्रावधान नहीं होंगे। अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी भी बिक्री पर तब तक लागू करें जब तक कि सामान बेचने वाला डीलर निर्धारित तरीके से निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत न कर दे: -

(ए) उस पंजीकृत डीलर द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र, जिसे सामान बेचा जाता है, जिसमें निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में निर्धारित विवरण शामिल हैं; या

धारा 8(4) के तहत निर्धारित फॉर्म केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और टर्नओवर) नियमों के नियम 12(1) के संदर्भ में फॉर्म 'सी' है।

नियम 12(1) इस प्रकार है:-

"धारा 8 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट घोषणा और प्रमाणपत्र क्रमशः 'ओ' और 'डी' फॉर्म में होंगे।"

धारा 8 और नियम 12 (1) के प्रावधानों के आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि जब भी ये सामान याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान खरीदा जाता था, तो उसे एक देना पड़ता था। नियम 12(1) के तहत निर्धारित फॉर्म 'सी' में घोषणा जिसमें यह प्रमाणित करना था कि खरीदा गया सामान बिक्री के लिए सामान के निर्माण/प्रसंस्करण में पुनः बिक्री/उपयोग के लिए था। इस प्रकार, यह ध्यान दिया जाएगा कि न तो धारा 8 के प्रावधान, न ही नियम 12 के प्रावधान, न ही फॉर्म 'बी' में पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रावधान, न ही फॉर्म 'सी' में दी गई घोषणा के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रश्न में सामान का उपयोग किया जाना चाहिए। केवल किसी विशेष राज्य में बिक्री के लिए माल की निर्माण प्रक्रिया में और जहां तक मूल्यांकन प्राधिकारी अन्य राज्य में कंपनी की विनिर्माण इकाई में इन सभी सामानों के उपयोग को पंजीकरण प्रमाणपत्र या फॉर्म में घोषणा के दुरुपयोग के रूप में दर्ज करता है विद्वान वकील का तर्क है कि 'सी', प्राधिकरण ने जानबूझकर इस विषय पर स्पष्ट रूप से स्थापित कानून की अनदेखी की है। विद्वान वकील यह तर्क देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हैं कि यह एक निर्धारिती के लिए स्वीकार्य है जिसने फॉर्म 'सी' में घोषणा की है कि वह या तो एक राज्य में अपने कारखाने में माल का उपयोग कर सकता है या माल का उपयोग कर सकता है। किसी अन्य राज्य में निर्माण या प्रसंस्करण। विद्वान वकील की मूल निर्भरता *पोलस्टार इलेक्ट्रॉनिक (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम अतिरिक्त आयुक्त, बिक्री कर और अन्य* (26) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। उपरोक्त मामले के तथ्यों से पता चलता है कि करदाता बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 के तहत पंजीकृत डीलर थे, जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू होता है। 1971-72 और 1972-73 की मूल्यांकन अवधि के दौरान उनके पास पंजीकरण के प्रमाण पत्र थे जो उनके द्वारा पुनर्विक्रय के लिए या बिक्री के लिए माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले माल के वर्ग या वर्गों को निर्दिष्ट करते थे। पंजीकरण प्रमाणपत्र 29 मार्च, 1973 को इसके संशोधन से पहले के स्वरूप में थे, और उन्होंने यह निर्दिष्ट नहीं किया था कि

खरीदे गए माल की पुनर्विक्रय या विनिर्माण ओई माल में कच्चे माल के रूप में उनका उपयोग या निर्मित माल की बिक्री - दिल्ली के अंदर होनी चाहिए। कुछ मामलों में करदाता ने पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट श्रेणी का सामान खरीदा, जैसा कि पुनर्विक्रय के लिए है और सामान बेचने वाले डीलरों को निर्धारित फॉर्म में घोषणाएं प्रस्तुत कीं, जैसा कि यह 29 मार्च, 1973 से पहले था, जिसमें कहा गया था कि माल पुनर्विक्रय के लिए था और उसके बाद माल को फिर से बेच दिया गया, हालांकि दिल्ली के क्षेत्र के भीतर नहीं, जबकि कुछ अन्य मामलों में निर्धारिती ने पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट वर्ग के सामान खरीदे, जो उनके द्वारा निर्माण में कच्चे माल के

रूप में उपयोग के लिए थे। बिक्री के लिए माल की बिक्री करने वाले डीलरों को 29 मार्च, 1973 से पहले निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कहा गया था कि माल उनके द्वारा बिक्री के लिए माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिए खरीदा गया था और उसके बाद उपयोग किया गया था। माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में खरीदा गया माल, कुछ मामलों में दिल्ली के बाहर और कुछ अन्य मामलों में, लेकिन बाद में, इस प्रकार निर्मित माल को दिल्ली के बाहर बेचा जाता था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले यानी *फिटवेल इंजीनियर्स बनाम दिल्ली के वित्तीय आयुक्त* (27) में कहा कि धारा 5(2) (ए) (ii) और उसके दूसरे प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, खरीदे गए सामान की पुनर्विक्रय नहीं की जा सकती। दिल्ली के अंदर पुनर्विक्रय तक ही सीमित है और इसलिए, विनिर्मित वस्तुओं के निर्माण और बिक्री में कच्चे माल के रूप में खरीदे गए माल का उपयोग दिल्ली के अंदर होना आवश्यक था और इसलिए, यदि निर्धारित दिल्ली के बाहर माल को फिर से बेचता है या उन्हें कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है दिल्ली के बाहर निर्माण, या भले ही निर्माण दिल्ली के अंदर था, दिल्ली के बाहर निर्मित माल बेचा, करदाता द्वारा माल का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए उन्हें खरीदा गया था और इसलिए धारा 5(2) का दूसरा प्रावधान) (ए) (ii) आकर्षित किया गया था और खरीदे गए सामान की कीमत निर्धारित के कर योग्य कारोबार में शामिल होने के लिए उत्तरदायी थी। सवाल यह था कि क्या कर अधिकारियों के दृष्टिकोण को मंजूरी देने वाला उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण सही था। तर्क की प्रक्रिया से, सुप्रीम कोर्ट ने फिटवेल इंजीनियर्स मामले (सुप्रा) में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया और कहा कि: -

“जैसा कि निर्धारितियों द्वारा दी गई घोषणाओं में कहा गया है कि माल की खरीद का उद्देश्य बिक्री के लिए माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग करना था और यह निर्दिष्ट नहीं किया था कि निर्माण और बिक्री दिल्ली के क्षेत्र के अंदर होगी, यह नहीं कहा जा सकता है यदि निर्धारितियों ने माल का उपयोग 'किसी अन्य उद्देश्य' के लिए किया है तो दिल्ली के बाहर विनिर्माण में कच्चा माल या दिल्ली के बाहर निर्मित माल बेचा जाता है। भले ही उन्होंने दिल्ली के बाहर माल का निर्माण किया और दिल्ली के बाहर निर्मित माल को बेचा, उनके द्वारा खरीदे गए माल का उपयोग घोषणा में बताए गए उद्देश्य के लिए होगा और यह कहना सही नहीं होगा कि उन्होंने माल का उपयोग किसी अन्य के लिए किया। उद्देश्य। इस अवधि के दौरान भी करदाता पर दूसरे परंतुक के तहत कर का दायित्व नहीं डाला जा सकता क्योंकि उन्होंने बेचने वाले डीलरों को दी गई घोषणाओं में व्यक्त इरादे के बयान का अक्षरशः अनुपालन किया था।

(ii)

एक वैधानिक अधिनियम को आम तौर पर उसकी भाषा के स्पष्ट प्राकृतिक अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए और कोई भी शब्द तब तक नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बदला या संशोधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि किसी प्रावधान को अबोधगम्य, बेतुका, अनुचित, अव्यवहारिक या होने से रोकने के लिए ऐसा

करना स्पष्ट रूप से आवश्यक न हो। बाकी क़ानून के साथ पूरी तरह असंगत। यह नियम ओ 1 एफ शाब्दिक निर्माण दृढ़ता से स्थापित है और इसे कई मामलों में न्यायिक मान्यता प्राप्त हुई है।

किसी कर संबंधी क़ानून की व्याख्या करते समय "किसी को क़ानून के सख्त अक्षरों का ध्यान रखना चाहिए, न कि केवल क़ानून की भावना या क़ानून के सार का"। यदि विधायिका उचित भाषा का उपयोग करके इसका अर्थ स्पष्ट करने में विफल रही है, तो लाभ करदाता को मिलना चाहिए। यदि व्याख्या के संबंध में कोई संदेह है, तो भी इसका समाधान विषय के पक्ष में किया जाना चाहिए।

जब करदाता की शाखाएं दिल्ली के बाहर सामान बेचती थीं, तो वास्तव में करदाता ही सामान बेचता था, क्योंकि शाखाएं करदाता से अलग और स्वतंत्र नहीं थीं, बल्कि करदाता की संस्थाएं मात्र थीं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि जब माल शाखाओं द्वारा पुनर्विक्रय किया गया था, तो पुनर्विक्रय निर्धारिती द्वारा नहीं किया गया था ताकि दूसरे प्रावधान की प्रयोज्यता को आकर्षित किया जा सके। धारा 4 और धारा 5(2) (ए) (ii) के दूसरे प्रावधान के बीच कोई असंगतता नहीं है।

(30) थिया काउंसिली ने *असेसिंगिथ अथॉरिटी. एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, गुड़गांव और अन्य* बनाम *ईस्ट इंडिया कॉटन एमएफजी कंपनी लिमिटेड* (28) पर भरोसा किया। पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित *उक्त मामले* में निर्धारिती का व्यवसाय "कपड़ा - विनिर्माण, बिक्री, खरीद, थोक वितरण" था; रतालू और अपशिष्ट और कपड़ा मशीनरी की बिक्री और खरीद" और पंजीकरण प्रमाण पत्र में अन्य बातों के साथ- *साथ* धारा 8 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए माल की निम्नलिखित श्रेणियों को भी निर्दिष्ट किया गया है, अर्थात्, 'रंग रंगना, और उपयोग के लिए अन्य रसायन निर्माण में।' निर्धारिती ने इन सामानों को अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान खरीदा और बिक्री करने वाले व्यापारियों को फॉर्म 'सी' में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि ये सामान निर्धारिती द्वारा विनिर्माण में उपयोग के लिए खरीदे गए थे। बिक्री के लिए माल. इन घोषणाओं के आधार पर, बेचने वाले डीलरों पर केंद्रीय अधिनियम की धारा 8 (एल) (बी) के तहत 3 प्रतिशत की दर से निर्धारिती को की गई बिक्री के संबंध में कर लगाया गया था। निर्धारिती द्वारा खरीदे गए सामान का उपयोग आंशिक रूप से निर्धारिती के वस्त्रों के आकार, ब्लीचिंग और डेवेंग के लिए किया गया था और आंशिक रूप से निर्धारिती के तीसरे आकार के वस्त्रों के आकार, ब्लीचिंग और रंगाई के लिए और आंशिक रूप से नौकरी के आधार पर पार्टियों के लिए किया गया था। . निर्धारिती को इस आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि वह नौकरी के आधार पर तीसरे पक्ष के लिए साइजिंग, ब्लीचिंग और रंगाई करने के पंजीकरण प्रमाणपत्र का दुरुपयोग कर रहा था। करदाता. जिसने भी शो में कुछ जानकारी दोबारा प्रसारित की, लेकिन उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी ने निर्धारिती के खिलाफ निम्नलिखित तरीके से मामला तैयार किया: -

“कंपनी ने बिक्री के लिए माल के निर्माण में उपयोग के उद्देश्य से सी फॉर्म जमा करने पर पंजाब राज्य (अब हरियाणा) के बाहर से माल खरीदा। लेकिन ऐसा करने के बजाय, कंपनी ने उस खरीद का उपयोग आंशिक रूप से बिक्री के लिए अपने स्वयं के सामान के निर्माण में और आंशिक रूप से अन्य पार्टियों के लिए आईओबी-कार्य करने के लिए किया। कंपनी रियायती दर पर खरीदी गई सामग्री का उपयोग आईओबी-कार्य के लिए नहीं कर सकती क्योंकि वह 'बिक्री' नहीं है।”

जब निर्धारिती की दलील संबंधित अधिकारियों के साथ नहीं मानी गई कि न तो भर्ती प्रमाण पत्र के नियम और शर्तें और न ही केंद्र की धारा एसएफएसएम'बी'एल के प्रावधान। अधिनियम ने फिर से कहा कि उसके द्वारा खरीदे गए माल का उपयोग उसके द्वारा बिक्री के लिए अपने स्वयं के माल के निर्माण या प्रसंस्करण में किया जाना चाहिए और यह धारा 8(3),(बी) की आवश्यकता के साथ पर्याप्त अनुपालन होगा। माल भले ही पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ पढ़ें

(28) (1981) 48 एसटीसी, 239।

खरीदे गए सामान का उपयोग निर्धारिती द्वारा नौकरी-अनुबंध के तहत किसी तीसरे पक्ष के लिए माल के निर्माण या प्रसंस्करण में किया गया था, जब तक कि निर्मित या संसाधित सामान ऐसे तीसरे पक्ष द्वारा बिक्री के लिए थे, मामला एक रिट में दायर किया गया था उच्च न्यायालय ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि धारा 8(3)(बी) की सही व्याख्या के आधार पर, करदाता द्वारा उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध खरीदा गया सामान केवल वस्तुओं के निर्माण में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वयं बिक्री के लिए और यदि खरीदे गए सामान का उपयोग नौकरी-अनुबंध के आधार पर किसी तीसरे पक्ष के लिए वस्तुओं के निर्माण में किया गया था, तो यह धारा 8(3) में निर्दिष्ट से भिन्न उद्देश्य के लिए खरीदे गए सामान के उपयोगकर्ता के बराबर होगा। (बी) और निर्धारिती धारा 10 और 10-ए के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा। हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डिवीजन बेंच ने कानून के सवाल पर मामले का फैसला निर्धारिती के पक्ष में किया। इन परिस्थितियों में मूल्यांकन प्राधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। ऊपर उल्लिखित विवाद पर, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया: -

वस्तुओं के निर्माणमें उपयोग के लिए” अभिव्यक्ति का दायरा और अर्थ क्या है

बिक्री' धारा 8(3)(बी) और फॉर्म "सी" और नियम 13 में घोषणा में होती है। क्या इसका मतलब यह है कि माल एक पंजीकृत डीलर द्वारा उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर खरीदे गए माल का उपयोग करके निर्मित किया गया है और फॉर्म सी में घोषित राशन उसके द्वारा बिक्री के लिए अभिप्रेत होना चाहिए या क्या इसमें ऐसा मामला भी शामिल है जहां किसी पंजीकृत डीलर द्वारा नौकरी-अनुबंध के तहत किसी तीसरे पक्ष के लिए सामान का निर्माण किया जाता है और निर्मित सामान ऐसे तीसरे पक्ष द्वारा बिक्री के लिए अभिप्रेत है?

यह माना गया कि "उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच यह मानने में सही थी कि भले ही निर्धारिती ने नौकरी-अनुबंध के आधार पर किसी तीसरे पक्ष के लिए कपड़ों के आकार, ब्लीचिंग या रंगाई का काम किया हो, उसका मामला इसके दायरे में आएगा /" धारा 8(3)(बी) के दूसरे उप-खंड

की शर्तें, बशर्तें कि निर्धारिती द्वारा जब्त, प्रक्षालित और रंगे गए वस्त्र ऐसे तीसरे पक्ष द्वारा बिक्री के लिए थे। यदि धारा 10 (डी) या धारा 10-ए के तहत शुरू की गई किसी भी कार्यवाही में यह साबित हो जाता है कि आईओबी-अनुबंध के आधार पर किसी तीसरे पक्ष के लिए निर्धारिती द्वारा निर्धारिती के आकार, ब्लीच और रंगे गए कपड़े ऐसे तीसरे पक्ष द्वारा बिक्री के लिए अभिप्रेत नहीं थे, जैसा कि स्पष्ट होगा यदि ऐसे वस्त्र वास्तव में तीसरे एनएआरटीवी द्वारा बेचे नहीं गए थे, बल्कि अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए थे, तो निर्धारिती को उन धाराओं में निर्धारित दंड भुगताना होगा।

(31) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्रीमान एस भूषण द्वारा दी गई सबसे अगली न्यायिक याचिका *इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम वाणिज्यिक कर और अन्य के सहायक आयुक्त* (29) है। उक्त मामले के तथ्यों से, जहां तक ये प्रासंगिक हैं, पता चलता है कि उत्पादों की पैकिंग के उद्देश्य से याचिकाकर्ता कंपनी ने राज्य के अंदर और साथ ही बिहार राज्य के बाहर से बड़ी मात्रा में कागज और बोर्ड खरीदे। निर्धारित प्रपत्र में केंद्रीय अधिनियम के तहत कंपनी को दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र में कंपनी द्वारा अपनी सामग्रियों की पैकिंग में उपयोग के लिए कागजात और बोर्ड का भी उल्लेख किया गया है। संबंधित वर्ष के दौरान कंपनी ने निर्धारित सी फॉर्म में जारी घोषणा के तहत बिहार राज्य के बाहर से कागजात और बोर्ड खरीदे। इस हिसाब से, कंपनी को केंद्रीय अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रावधानित केवल 10 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना था। कंपनी ने कुछ सामग्रियों को बिहार राज्य के बाहर अपने अन्य कारखानों और शाखाओं में 'अंतर-शाखा हस्तांतरण के रूप में' उपभोग/उपयोग के लिए भेजा और यह विवादित नहीं था कि उन स्थानों पर भी उक्त सामग्रियों का उपयोग वास्तविक पैकिंग के लिए किया गया था। कंपनी की उन इकाइयों द्वारा निर्मित माल। निर्धारण के लिए जो अतिरिक्त प्रश्न आया वह यह था कि क्या उन सामानों का हस्तांतरण जो कंपनी द्वारा मोंगर में खरीदा गया था, उसकी घोषणा का उल्लंघन है? यह माना गया कि कंपनी की मुंगेर शाखा, हालांकि एक अलग पंजीकरण प्रमाण पत्र है, को इसकी प्रमुख कंपनी या अन्य राज्यों में विभिन्न स्थानों पर अन्य कार्यालयों और शाखाओं से स्वतंत्र एक अलग व्यक्तित्व नहीं माना जा सकता है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भी *इंडियन एल्युमिनिम कंपनी लिमिटेड बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर वार्ड ए संबलापुर* (30) मामले में यही विचार व्यक्त किया है, जिसमें यह माना गया था कि "डॉ. पाल के पहले तर्क पर आते हैं। यह केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(3)(बी) और याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र पर निर्भर करता है। डॉ. पाल के अनुसार, अभिव्यक्ति 'माल के निर्माण में उपयोग के लिए

.....' अधिनियम की धारा 8(3)(बी) में होती है। डीलर पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि डीलर को राज्य के भीतर ही तैयार माल का उत्पादन करना चाहिए और इसलिए, राजस्व के रुख में कोई औचित्य नहीं था कि चूंकि तैयार माल का उत्पादन उड़ीसा राज्य के बाहर किया गया था। अधिनियम की धारा 10(डी) का उल्लंघन है। इस तर्क के समर्थन में, जे.के. *कॉटन* के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है

(29) 58 एसटीसी 193.

(30) 90 एसटीसी 410.

स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर (31), साथ ही *असेसिंग अथॉरिटी-कम-एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी-टन एमएफजी कंपनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लिमिटेड* (32).

(32) वैकल्पिक याचिका यह दिखाने के प्रयास के साथ उठाई गई कि शाखा हस्तांतरण अंतर-राज्यीय बिक्री नहीं थी, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि किसी भी स्थिति में शाखा हस्तांतरण में कोई बिक्री शामिल नहीं थी। यह तर्क दिया गया है कि भले ही फॉर्म 'सी' में घोषणा का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था, लेकिन इसे मानते हुए, प्राधिकरण के पास उपलब्ध एकमात्र शक्ति या तो केंद्रीय अधिनियम की धारा 10 (डी) के तहत अभियोजन शुरू करना था। या केंद्रीय अधिनियम की धारा 10ए के तहत अभियोजन के बदले जुर्माना लगाने की कार्यवाही शुरू करना। यह तर्क दिया जाता है कि बिक्री केवल दो अलग-अलग व्यक्तियों या न्यायिक संस्थाओं के बीच ही हो सकती है। कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी केवल एक एकल न्यायिक इकाई है और कंपनी द्वारा स्वयं को बिक्री नहीं की जा सकती है। कंपनी की शाखाएं अलग-अलग न्यायिक इकाई नहीं हैं जिनके पक्ष में संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 2(जी) में निहित 'बिक्री' की परिभाषा और *केसीपी लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* (33), *द गवर्नमेंट वुड वर्क्स बनाम केरल राज्य* (34) में निहित न्यायिक उदाहरण भी शामिल हैं। *बिक्री कर अधिकारी, नवगांव और अन्य बनाम टाइमर एंड फ्यूल कॉर्पोरेशन* (35*) पर उनके उपरोक्त तर्क के लिए भरोसा किया गया है।

(33) अब दूसरे राज्यों में एजेंटों को माल के खेप हस्तांतरण के दूसरे बिंदु पर आते हुए, मूल रूप से, यह याचिकाकर्ता कंपनी का मामला है कि निर्धारिती अपना माल भेज रहा था और लिखित अनुबंध के तहत उन्हें दूसरे राज्यों में एजेंटों को भेज रहा था। एजेंटों ने उन राज्यों में स्थानीय बिक्री के माध्यम से उन सामानों को अन्य पार्टियों को बेच दिया, जिन पर उन्होंने स्थानीय बिक्री कर का भुगतान किया था। जिस दर पर उन बिक्री पर कर लगाया जाता है वह दर भी 4 प्रतिशत है, जैसा कि निर्धारिती द्वारा दूसरे राज्य में किसी अन्य पंजीकृत डीलर को अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर है। यह इस तथ्य के कारण है कि प्रश्नगत माल,

- | | |
|------|-----------------------|
| (31) | (1965) 16 एसटीसी 563। |
| (32) | (1981) 48 एसटीसी 239। |
| (33) | 88 एसटीसी 374 (एपी)। |
| (34) | 69 एसटीसी 62. |
| (35) | 31 एसटीसी 585. |

अर्थात् "लोहा और इस्पात" केंद्रीय अधिनियम की धारा 14(iv) के तहत 'घोषित माल' हैं। प्रविष्टि 92-बी को 2 फरवरी, 1983 से संविधान के 46वें संशोधन अधिनियम, 1982 द्वारा संविधान के एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसके आधार पर अब संसद को केवल अंतर-राज्यीय खेप पर कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है। माल भले ही ऐसी खेप में बिक्री शामिल नहीं थी, संसद ने अब तक अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है और कोई खेप कर नहीं लगाया है। अनुच्छेद 269(3) के तहत संसद को यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत बनाना है कि कानून द्वारा अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान (माल की बिक्री या खरीद, या खेप) कब होती

है। ऐसा कानून संसद द्वारा केंद्रीय अधिनियम की धारा 3 के तहत बनाया गया है जो इस प्रकार है: -

"धारा 3: जब यह अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली वस्तुओं की बिक्री या खरीद है - तो माल की बिक्री या खरीद को अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुआ माना जाएगा, यदि बिक्री या खरीद-

- (a) एक राज्य से दूसरे राज्य तक माल की आवाजाही के अवसर, या
- (b) एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन के दौरान माल के स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होता है।

यह धारा 3 का केवल खंड (ए) है जो वर्तमान मामले में प्रासंगिक होगा। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि याचिकाकर्ताओं का मूल तर्क यह है कि उनके एजेंटों को माल की बिक्री से एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही नहीं हुई। धारा 3 का खंड (ए) सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का विषय रहा है, प्रमुख निर्णय *टिस्को बनाम एस. एफ. सरकार* (36) में है, जिसमें यह माना गया था कि "बिक्री का लेनदेन कर के अधीन है" केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, बिक्री के पूरा होने पर, और बिक्री का मात्र अनुबंध धारा 2(जी) में परिभाषा के भीतर बिक्री नहीं है। परिभाषा के अनुसार बिक्री, संपत्ति का हस्तांतरण, धारा 3 (ए) के तहत कर योग्य हो जाती है यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही एक अनुबंध या बिक्री के अनुबंध की घटना के तहत होती है, और माल में संपत्ति राज्य के पास चली जाती है। जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा हो तो मालिकाना हक के दस्तावेजों के हस्तांतरण के अलावा क्रेता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता। अंतरराज्यीय बिक्री के संबंध में, कर केवल एक बार और धारा 3 के दो खंडों पर लगाया जाता है

परस्पर अनन्य हैं। इसलिए धारा 3 के खंड (ए) के अंतर्गत आने वाली कर योग्य बिक्री को धारा 3 के दायरे या खंड (बी) से बाहर रखा जाएगा। धारा 3 के खंड (बी) द्वारा विचार की गई बिक्री वह है जो शीर्षक के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के दौरान माल को बांधना। जहां माल में संपत्ति संचलन शुरू होने से पहले पारित हो गई है, बिक्री खंड (बी) के अंतर्गत नहीं आएगी; न ही वह बिक्री, जिसमें माल में संपत्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही बंद होने के बाद गुजरती है, इस खंड के अंतर्गत कवर की जाएगी। तदनुसार, आंदोलन की शुरुआत के बाद और इसके समापन से पहले दो टर्मिनी द्वारा अस्वीकार किए गए शीर्षक के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा की गई बिक्री! स्पष्टीकरण (1) में निर्धारित है और धारा 3(बी) के तहत किसी भी अन्य बिक्री को अंतर-राज्यीय बिक्री नहीं माना जाएगा। हालाँकि, "बिक्री" के विखंडन में किराया-खरीद या किस्तों द्वारा भुगतान की अन्य प्रणालियों पर माल का हस्तांतरण शामिल है, बिक्री का एक मात्र अनुबंध जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता है, जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही होती है। धारा 3(ए) की शर्तें, केवल वह लेन-देन जिसमें किराये की खरीद या किस्तों द्वारा भुगतान की अन्य प्रणालियों पर माल का हस्तांतरण होता है, "बिक्री" की परिभाषा में शामिल है। उपरोक्त मामले के तथ्यों से पता चलता है कि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बॉम्बे में, बीड बिक्री कार्यालय पश्चिम बंगाल राज्य के कलकत्ता में और इसके कारखाने बिहार राज्य के जमशेदपुर में थे। 1 जुलाई, 1957 से 31 मार्च, 1958 की मूल्यांकन अवधि के लिए कंपनी ने कर योग्य बिक्री का अपना रिटर्न वाणिज्यिक कर अधिकारी, कलकत्ता को प्रस्तुत किया, जिसमें रुपये के सकल कर योग्य कारोबार का खुलासा किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य में केंद्रीय बिक्री कर के लिए उत्तरदायी बिक्री के संबंध में 9561.71। हालाँकि, वाणिज्यिक कर अधिकारी ने कंपनी को मूल्यांकन अवधि के लिए जमशेदपुर से बिक्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, "जिससे संबंधित दस्तावेज पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित किए गए थे या किसी अन्य बिक्री से संबंधित जो पश्चिम बंगाल में हुई हो सकती है" केंद्रीय अधिनियम की धारा 3(बी). हालाँकि, कंपनी ने 30 सितंबर, 1959 को अपने पत्र द्वारा कर अधिकारी को सूचित किया कि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान जमशेदपुर से की गई बिक्री का विवरण प्रस्तुत करने की मांग अधिकार क्षेत्र के बिना थी। हालाँकि, 21 अक्टूबर, 1959 के आदेश द्वारा, कर: अधिकारी ने अंतर-राज्य बिक्री के सकल कारोबार पर सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन किया और कंपनी को केंद्रीय अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए कहा। उपरोक्त आदेशों को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता को कर का भुगतान करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के कर अधिकारी द्वारा दिए गए विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया। अन्य सहायक निर्णय.

श्री शांति भूषण पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील *TECCO* बनाम *सिस्सू* हैं। *कमिश्नर ओजे टैक्स और अन्य* (37), *बयाउहागास नुलास चंद और अन्य* बनाम *राज्य ओजी उड़ीसा* (38), राज्य ओज *लाम आई आईटी आईवी एसीएलयू बनाम द सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लिमिटेड और अन्य* (39), *साउथ पंजाब इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन/ लिमिटेड* बनाम *हरियाणा राज्य* (40)। और *यूनियन ओजे इंडिया और अन्य* बनाम *केजी खोसला एंड कंपनी और अन्य* (एच), और *आइसलवमेटर ओजे इंडिया लिमिटेड* बनाम *राज्य ओजे हरियाणा* (42)।

(34) जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुकदमे को मजबूत करने के लिए, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील भी केंद्रीय अधिनियम की धारा 6-ए पर भरोसा करते हैं। जो इस प्रकार पढ़ता है:-

"6-ए:- हस्तांतरण और बिक्री के माध्यम से अन्यथा दावा किए गए माल के मामले में सबूत आदि का बोझ:-

(1) जहां कोई भी डीलर दावा करता है कि वह इस अधिनियम के तहत किसी भी सामान के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, इस आधार पर कि ऐसे सामान की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही उसके द्वारा ऐसे सामान को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने के कारण हुई थी। उसके व्यवसाय के अन्य स्थान पर या उसके एजेंट या प्रिंसिपल को, जैसा भी मामला हो और बिक्री के कारण नहीं, यह साबित करने का भार डीलर पर होगा कि उन सामानों की आवाजाही इस तरह से हुई थी और इस उद्देश्य के लिए वह प्रस्तुत कर सकता है मूल्यांकन प्राधिकारी, निर्धारित समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो प्राधिकारी, पर्याप्त कारण, परमिट, एक घोषणा के लिए, व्यवसाय के अन्य स्थान के प्रमुख अधिकारी या उसके एजेंट द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित हो सकता है। या जैसा भी मामला हो, निर्धारित प्रिंसिपल से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में, निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में निर्धारित विवरण सहित, ऐसे सामान के विवरण के साक्ष्य के साथ।

(37) 1970 (3) एससीआर 862।

(38) 33 एसटीसी 207.

(39) 36 एसटीसी 389.

(40) 37 एसटीसी 35.

(41) 43 एसटीसी 457.

(42) 32 एसटीसी 629.

(2) यदि मूल्यांकन प्राधिकारी ऐसी जांच करने के बाद संतुष्ट है जिसे वह आवश्यक समझ सकता है कि उपधारा (1) के तहत एक डीलर द्वारा प्रस्तुत घोषणा में शामिल विवरण सत्य हैं, तो वह, अपने समय पर या उससे पहले किसी भी

समय, कर सकता है। इस अधिनियम के तहत डीलर द्वारा देय कर का मूल्यांकन, उस आशय का एक आदेश बनाएं और उसके बाद माल की आवाजाही, जिससे संबंधित घोषणा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अन्यथा उत्पन्न हुई मानी जाएगी। बिक्री करना।"

यह तर्क दिया जाता है कि सबूत के बोझ को व्यापार के अन्य स्थान के प्रमुख अधिकारी द्वारा विधिवत भरे और हस्ताक्षरित एक घोषणा प्रस्तुत करने से समाप्त किया जाता है, जहां माल भेजा गया है, प्रेषण के साक्ष्य के साथ निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में। ऐसे सामान का, उस स्थिति में मूल्यांकन प्राधिकारी को केवल यह जांच करनी है कि डीलर द्वारा प्रस्तुत घोषणा में शामिल विवरण सत्य हैं या नहीं। यदि उसे पता चलता है कि वे विवरण सत्य हैं, तो उसे उस आशय का आदेश देना आवश्यक था और फिर एक वैधानिक निष्कर्ष होता है कि माल की आवाजाही, जिससे घोषणा संबंधित है, बिक्री के कारण नहीं हुई है। इस प्रकार, दो तरीके हैं जिनसे एक राज्य में एक डीलर द्वारा दूसरे राज्य में दूसरे डीलर को सामान बेचा जा सकता है। या तो पहले बिक्री का अनुबंध किया जाता है और बिक्री के उस अनुबंध के अनुसरण में, सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है, जिसमें दूसरे राज्य के डीलर को ऐसी बिक्री पर केंद्रीय अधिनियम के तहत कर लगेगा। दूसरी ओर, पहले राज्य का डीलर माल को दूसरे राज्य की अपनी शाखा में भेज सकता है

राज्य या दूसरे राज्य में उसके एजेंट को इस निर्देश के साथ कि वह सामान प्राप्त होने पर वह दूसरे राज्य के डीलरों के साथ अनुबंध कर सकता है और उन्हें वह सामान बेच सकता है। यदि संचालन की इस पद्धति को अपनाया जाता है, तो बिक्री कर का दायित्व केंद्रीय अधिनियम के तहत उत्पन्न होने के बजाय, दूसरे राज्य के स्थानीय बिक्री कर अधिनियम के तहत उत्पन्न होगा, जहां माल या तो शाखा द्वारा या विक्रय एजेंट द्वारा बेचा गया है, उचित स्थानीय बिक्री कर लगाने के लिए केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और कारोबार) नियम, 1957 का नियम 12(51) नीचे दिया गया है: -

“धारा 6ए की उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा प्रपत्र 'एफ' में होगी।

बशर्ते कि एक एकल घोषणा में एक डीलर द्वारा, उसके व्यवसाय के किसी अन्य स्थान पर या उसके एजेंट या प्रिंसिपल को, जैसा भी मामला हो, एक कैलेंडर माह की अवधि के दौरान किए गए माल के हस्तांतरण को कवर किया जा सकता है;

बशर्ते कि यदि फॉर्म 'एफ' में प्रदान किया गया स्थान प्रविष्टियां करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो फॉर्म 'एफ' में निर्दिष्ट विवरण उस फॉर्म से जुड़े अलग-अलग अनुलग्नकों में दिए जा सकते हैं, जब तक कि फॉर्म में यह दर्शाया गया है कि अनुलग्नक उसका भाग बनता है और ऐसे प्रत्येक अनुलग्नक पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर भी किया जाता है

प्रपत्र 'एफ' के अवलोकन से पता चलता है कि दूसरे राज्य में माल प्राप्त करने वाले को एक प्रमाण पत्र देना होगा कि विवरण के अनुसार माल उसे प्राप्त हो गया है और उसका विधिवत हिसाब किया गया है। विवरण माल के 'विवरण' से संबंधित हैं, उनकी मात्रा, मूल्य, संख्या और चालान और चालान की तारीख या कोई अन्य दस्तावेज जिसके तहत माल भेजा गया था, रेलवे या सड़क परिवहन कंपनी के कार्यालय का नाम जहां से माल भेजा गया था डेस पैच किए गए थे. आरआर या जीआर की संख्या और तारीख, लॉरी की ट्रिप शीट के साथ और वह तारीख जिस पर ट्रांसफरी द्वारा डिलीवरी ली गई थी, साथ ही यह प्रमाणित करने के लिए कि फॉर्म में

दिए गए विवरण उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं। यह तर्क दिया जा रहा है कि एक बार वैधानिक प्रपत्र 'एफ' माल के हस्तांतरणकर्ता से प्राप्त कर लिया गया था, और उसे ऐसे माल के प्रेषण के साक्ष्य, अर्थात् जीआर और प्रेषण सलाह के साथ मूल्यांकन प्राधिकारी के पास दायर किया गया था, वहां अधिनियम की धारा 6-ए के तहत एक निर्णायक वैधानिक धारणा थी कि 'एफ' फॉर्म में कवर किया गया सामान बिक्री के अलावा किसी अन्य तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया गया था। उस स्थिति में, ऐसे सामानों पर कोई सीएसटी लगाने का सवाल ही नहीं उठता। आगे यह तर्क दिया जा रहा है कि निर्धारित द्वारा अन्य राज्यों में अपने बिक्री एजेंटों को भेजे गए सभी सामान उन एजेंटों और जीआर द्वारा आपूर्ति किए गए फॉर्म 'एफ' घोषणा के अंतर्गत कवर किए गए थे और साथ ही उनके संबंध में डीएसपीएच सलाह भी उपलब्ध थी। प्रपत्र 'एफ' प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में, संबंधित अधिकारियों को धारा 6 ए की उप-धारा (2) के तहत एक सीमित जांच करने की अनुमति दी गई थी ताकि यह देखा जा सके कि प्रपत्र 'एफ' में घोषणा में निहित विवरण सही थे। सही। यदि तथ्य सही थे, तो उप-धारा (2) में उल्लिखित वैधानिक चिंताएँ प्रवाहित होती हैं, अर्थात्, अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की कोई बिक्री नहीं हुई थी। इसके लिए सीपी के. *ट्रेडिंग कंपनी बनाम एडिशनल सेल्स टैक्स ऑफिसर* (43) पर भरोसा जताया गया है। *ए. पी. बनाम ए. पी. डेयरी विकास निगम राज्य/एल. टी.डी. (एपी)* (44), *बिक्री कर आयुक्त बनाम आगरा फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड* (45), और, *चूनी लै परशोडी लाई*

(43) 76 एसटीसी 211.

(44) 95 एसटीसी 478.

(45) (1984) 10 एसटीसी इलाहाबाद 49,

वी. *बिक्री कर आयुक्त* (46)। फिर यह तर्क दिया गया कि नियमित रूप से रखी गई खाता पुस्तकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उसे मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था क्योंकि उसने स्वयं देखा था कि 'खाता पुस्तकों का अवलोकन किया गया और पाया गया कि उन्हें व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में बनाए रखा गया था।' यह तर्क दिया जाता है कि नियमित रूप से रखे गए खातों को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इसके विपरीत साबित न किया जाए। यह कहा गया है कि खाता पुस्तकों में सभी प्रासंगिक दस्तावेज शामिल थे जो स्पष्ट रूप से स्थापित करते थे कि माल बिक्री के किसी भी पूर्व अनुबंध के बिना एजेंटों को भेजा गया था। इस तर्क के समर्थन में कि ऐसी खाता पुस्तकों पर विवाद नहीं किया जा सकता है, *सेंट टेरेसा ऑयल मिल्स बनाम केरल राज्य* (47) और *आयकर आयुक्त बनाम पदमचंद रामगोपाल* (48) पर भरोसा किया गया है।

(35) श्रीमान श्री बाल सिब्बल, एडवोकेट जनरल, हरियाणा, ने कानून के प्रस्ताव पर बहुत विवाद किया है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रचारित किया है, उन्होंने इसे उचित ठहराने की दृष्टि से हमें विभिन्न विवादित आदेशों के माध्यम से ले लिया है। प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील द्वारा विवादित किए जाने वाले कानून का एकमात्र प्रस्ताव केंद्रीय अधिनियम की धारा 6-ए के अनुसार सबूत के बोझ और उसके निर्वहन के संबंध में है। उनका तर्क है कि धारा 6-ए की उप-धारा (2) के तहत परिकल्पित जांच करते समय, मूल्यांकन प्राधिकारी यह पता लगाने के अपने अधिकारों के भीतर होगा कि घोषणाओं में दिए गए विवरण सही हैं। यदि वह जांच स्वीकार्य है, तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा यह पता लगाने के लिए सभी

संभव कदम उठाए जा सकते हैं कि क्या यह एक अंतर-राज्यीय बिक्री थी या किसी एजेंट को केवल खेप हस्तांतरण था। इस प्रकार, यह प्रतिवादी-विभाग का मामला है कि संबंधित अधिकारियों ने केंद्रीय अधिनियम की धारा 6-ए की उप-धारा (2) के तहत परिकल्पित जांच की और तर्क की प्रक्रिया पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे कि लेनदेन में प्रश्न अंतरराज्यीय बिक्री का था। उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कारणों को विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उचित ठहराने की मांग की गई है। प्रतिवादी विभाग का यह भी मामला है कि जहां तक शाखा हस्तांतरण का संबंध है, कुछ वस्तुएं ऐसी थीं जिनका उपभोग संभवतः किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता था और उक्त लेनदेन को अंतर-राज्यीय बिक्री माना गया था। इसके अलावा, मुख्य

- (46) 62 एसटीसी 112.
- (47) 76 आईटीआर 365.
- (48) 76 आईटीआर 719.

वैकल्पिक समाधान की क्षमता पर है और साथ ही इस बात पर भी है कि मुख्यमंत्री श्री भजन लार्ड के खिलाफ *दुर्भावना के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं।*

(36) हमने पक्षों के लिए एक-एक करके विस्तृत दलीलें और उन्नत वकील सुने हैं। जहां तक शाखा हस्तांतरण और एजेंटों को माल भेजने से संबंधित कानून पर याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील की दो बुनियादी दलीलों का सवाल है, हम उनसे काफी सहमत हैं। मूल्यांकन प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि शाखा हस्तांतरण की अनुमति नहीं थी और देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित याचिकाकर्ताओं की विभिन्न शाखाओं में भेजे गए माल का उपयोग केवल हिंसा कार्यालय में किया जा सकता था, ऐसा न होने पर इसे मान लिया जाएगा। अंतरराज्यीय बिक्री के रूप में, कानून की जांच में टिक नहीं सकता। केंद्रीय अधिनियम की धारा 8(3)(बी) और नियम 12(1) को फैसले के पहले भाग में पुनः प्रस्तुत किया गया है। न तो धारा 8 के प्रावधान, न ही नियम 12 के प्रावधान, न ही फॉर्म 'बी' में पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रावधान, न ही फॉर्म 'सी' में दी गई घोषणा के लिए यह आवश्यक है कि प्रश्न में आने वाले सामान का उपयोग माल के निर्माण या प्रक्रिया में किया जाना चाहिए। केवल किसी विशेष राज्य में बिक्री। यदि यह कानून की भाषा है, तो किसी भी हद तक यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता कंपनी ने पंजीकरण प्रमाणपत्र का दुरुपयोग किया है। *पोलस्टार इलेक्ट्रॉनिक्स* में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत प्रमुख मामला। (*प्राइवेट लिमिटेड* (सुप्रा) प्रश्नगत मुद्दे को अत्यधिक प्रदर्शित करता है। उक्त मामले में निर्धारित बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 के तहत पंजीकृत डीलर थे और उनके पास उनके द्वारा पुनर्विक्रय के लिए या कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए इच्छित वस्तुओं के वर्ग-या-वर्गों को निर्दिष्ट करने वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र थे। बिक्री के लिए माल का निर्माण। पंजीकरण प्रमाणपत्र उसी रूप में थे जैसा कि इसके संशोधन से पहले था और उन्होंने यह निर्दिष्ट नहीं किया था कि खरीदे गए माल की पुनर्विक्रय या माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उनका उपयोग या निर्मित माल की बिक्री दिल्ली के अंदर होनी चाहिए। कुछ मामलों में करदाता ने पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट श्रेणी का सामान खरीदा, जैसा कि उनके द्वारा पुनर्विक्रय के लिए किया गया था और सामान बेचने

वाले डीलरों को निर्धारित फॉर्म में घोषणाएं दीं, जिसमें कहा गया था कि सामान पुनर्विक्रय के लिए था और उसके बाद उसे फिर से बेच दिया। माल, हालांकि दिल्ली के क्षेत्र के भीतर नहीं है, जबकि कुछ अन्य मामलों में निर्धारितियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्रों में निर्दिष्ट वर्ग के सामान खरीदे, जो बिक्री के लिए माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले थे और डीलरों को उपलब्ध कराए गए थे। निर्धारित फॉर्म में सामान बेचने की घोषणा, जिसमें कहा गया है कि सामान उनके द्वारा सामान के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए खरीदा गया था।

बिक्री और विक्रेता ने खरीदे गए माल को माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया, कुछ मामलों में दिल्ली के बाहर और कुछ अन्य मामलों में दिल्ली के अंदर, लेकिन बाद में, इस प्रकार निर्मित माल को दिल्ली के बाहर बेचा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि "जैसा कि निर्धारितियों द्वारा दी गई घोषणाओं में कहा गया है कि माल की खरीद का उद्देश्य माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग करना था और यह निर्दिष्ट नहीं किया था कि निर्माण और बिक्री के क्षेत्र के अंदर होगी।" दिल्ली, यह नहीं कहा जा सकता कि निर्धारितियों ने माल का उपयोग 'किसी अन्य उद्देश्य' के लिए किया, यदि उन्होंने माल का उपयोग दिल्ली के बाहर विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में किया या दिल्ली के बाहर निर्मित माल बेचा। आगे यह माना गया कि 'भले ही उन्होंने दिल्ली के बाहर माल का निर्माण किया हो और दिल्ली के बाहर निर्मित माल को बेचा हो, उनके द्वारा खरीदे गए माल का उपयोग घोषणाओं में बताए गए उद्देश्य के लिए होगा और यह कहना सही नहीं होगा कि वे किसी अन्य उद्देश्य के लिए माल का उपयोग किया। आगे यह माना गया कि "जब करदाता की शाखाएं दिल्ली के बाहर सामान बेचती हैं, तो वास्तव में करदाता ही सामान बेचता है, क्योंकि शाखाएं करदाता से अलग और स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि केवल करदाता की संस्थाएं होती हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि जब माल शाखाओं द्वारा पुनर्विक्रय किया गया था, तो पुनर्विक्रय निर्धारिती द्वारा नहीं किया गया था ताकि दूसरे प्रावधान की प्रयोज्यता को आकर्षित किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों का अपने निर्णयों में यह लगातार दृष्टिकोण रहा है, जिसका उल्लेख इस निर्णय के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में किया गया है और इसलिए, इस मुद्दे पर और अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब हम विद्वान वकील के पहले तर्क को स्वीकार कर रहे हैं, तो वैकल्पिक दलील यह है कि किसी भी स्थिति में शाखा हस्तांतरण में कोई बिक्री शामिल नहीं थी, किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

(37) *Insoffar?cassiconsignmentistransfer* £1 माल=तत्कालीन एजेंटों को अन्य राज्यों को, याचिकाकर्ताओं का सकारात्मक मामला यह है कि कंपनी अपने माल भेज रही थी और उन्हें लिखित अनुबंध के तहत अन्य राज्यों में एजेंटों को भेज रही थी, जिन्होंने उसके बाद उन सामानों को अन्य राज्यों को बेच दिया उन राज्यों में स्थानीय बिक्री के माध्यम से पार्टियों पर जहां उन्होंने स्थानीय बिक्री कर का भुगतान किया था, जिसके लिए उनका मूल्यांकन किया गया था + संबंधित राज्यों के बिक्री कर अधिनियमों के तहत स्थानीय बिक्री कर। वह दर, जिस पर उक्त बिक्री पर कर लगाया जाता है, वह भी 4 प्रतिशत है, जो करदाता द्वारा किसी अन्य पंजीकृत डीलर को अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विचाराधीन सामान, अर्थात् "आयरन और स्टील" केंद्रीय अधिनियम की धारा 14 (iv) के तहत 'घोषित सामान' हैं। अनुच्छेद 269(3) के तहत यह संसद है जिसे माल की बिक्री या खरीद, या खेप के निर्धारण के लिए सिद्धांत तैयार करना है।

कानून द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के पाठ्यक्रम में होता है। ऐसी स्थिति को केंद्रीय अधिनियम की धारा 3 के तहत कवर किया गया है, जो जहां तक प्रासंगिक है, इस प्रकार है: -

"3- माल की बिक्री या खरीद अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई मानी जाएगी, यदि बिक्री या खरीद-

- (a) एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के अवसर, या
 (b) XX XX"

माना जाता है कि, धारा 3 का खंड (बी) लागू नहीं है क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में उनके स्थानांतरण के दौरान स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से कोई बिक्री नहीं हुई थी। धारा 3 का खंड (ए) सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का विषय रहा है और सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख निर्णय *टिस्को बनाम एसआर सरकार* (49) में है, जिसमें यह माना गया है कि "माल की बिक्री को अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हो ताकि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत कर लगाया जा सके, जब करदाता द्वारा सामान भेजने से पहले खरीदार के साथ बिक्री का अनुबंध किया गया हो। दूसरे राज्य के लिए निर्धारिती और एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही या प्रेषण खरीदार के साथ बिक्री के अनुबंध या अनुबंध के तहत होता है। फैसले का उद्धरण इस फैसले के पिछले पैराग्राफ में पहले ही दोहराया जा चुका है। शीर्ष न्यायालय ने एक अन्य मामले *टीईआईसीओ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त* (50) में आगे कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के लिए बिक्री के अनुबंध के लिए क्या आवश्यक है ताकि बिक्री को एक राज्य में तब्दील किया जा सके। ब्याज वाले व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री ताकि केंद्रीय अधिनियम के तहत केंद्रीय बिक्री कर के अधीन किया जा सके। उस मामले में सवाल यह है कि क्या TEICO द्वारा अन्य राज्यों में अपने डीलरों को वाहनों की बिक्री केंद्रीय अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत अंतर-राज्यीय बिक्री थी, क्योंकि इसमें कंपनी के जमशेदपुर स्थित कार्यों से माल की आवाजाही हुई थी। बिहार राज्य से बिहार राज्य के बाहर अन्य राज्यों तक। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के पृष्ठ 867 पर, समझौते के मूल खंडों का उल्लेख किया गया है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है: -

नियंत्रण की घोषणा के बाद अपीलकर्ता द्वारा डीलरशिप समझौते का एक नया रूप (एक्स.एल.) पेश किया गया था

(49) 11 एसटीसी 665.

(50) (1970) 3 एससीआर 862।

आदेश देना। इस समझौते के खंड 1 (ए) में प्रावधान है कि "कंपनी बिहार राज्य के जमशेदपुर में अपने कार्यों से या बिहार राज्य के बाहर अपने डिपो और स्टॉकयार्ड से डीलर को बेचने और आपूर्ति करने के लिए सहमत है" जो वाहन आवंटित किए जाएंगे। कंपनी द्वारा डीलर को समझौते के प्रावधानों के अनुसार पुनर्विक्रय के लिए अपने विवेक पर। खंड 11(बी) को नीचे दोहराया गया है: -

"डीलर प्रत्येक महीने की 15 तारीख को कंपनी को मेल करेगा, या ताकि कंपनी को प्रत्येक महीने की 20 तारीख तक उसकी प्राप्ति हो, अगले अगले महीने के दौरान खरीद के लिए उसका फिल्म ऑर्डर और उसकी अनुमानित आवश्यकताएं उक्त वाहनों के लिए, अगले अगले महीने के बाद के दो महीनों के लिए।

ऊपर दिए गए खंड के आधार पर, विभाग द्वारा यह स्पष्ट करने की मांग की गई थी कि चूंकि डीलर को प्रत्येक महीने की 15 तारीख को कंपनी को मेल करना होता है, इसलिए अगले अगले महीने के दौरान खरीद के लिए उसकी कंपनी को आदेश देना होता है और अगले अगले महीने के बाद के महीनों के लिए उक्त वाहनों की उनकी अनुमानित आवश्यकता, डीलरशिप समझौते में निहित बिक्री के अनुबंध के परिणामस्वरूप प्रश्न में वाहनों को जमशेदपुर से डीलर के राज्य में स्थानांतरित किया गया माना जाना चाहिए। इस खंड से निपटने के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने विभाग के तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "जब तक कि उन वाहनों को जमशेदपुर से भेजे जाने से पहले किसी विशिष्ट वाहन को किसी विशेष डीलर के साथ अनुबंध के लिए विनियोजित नहीं किया गया था, तब तक धारा 3 (ए) की आवश्यकता होगी। " पूरा नहीं किया जाएगा।" सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि "अगर किसी मूल्यांकन प्राधिकारी को निर्धारित की जाने वाली जांच को खारिज करके निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना है, तो उसे प्रत्येक लेनदेन की अलग से जांच करके ऐसा करना होगा, न कि एक सारगर्भित दृष्टिकोण से। (जोर दिया गया)। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले को निम्नानुसार निपटाया गया: -

"सहायक आयुक्त के आदेश में एक और गंभीर कमजोरी यह थी (एक ऐसा मामला जिसे महाधिवक्ता को भी काफी हद तक स्वीकार करना पड़ा) यह पता लगाने के लिए कि क्या बिक्री का पूरा अनुबंध हुआ था, प्रत्येक लेनदेन पर गौर करने के बजाय कर के दायरे में केवल तभी लाया जाएगा जब जमशेदपुर से वाहनों की आवाजाही किसी संधि या उस घटना के तहत हुई हो

अनुबंध के अनुसार, सहायक आयुक्त ने अपना आदेश केवल सामान्यताओं पर आधारित किया। यह सुझाव दिया गया है कि सभी लेनदेन समान प्रकृति के थे और अपीलकर्ता के प्रतिनिधि ने स्वयं प्रस्तुत किया था कि केवल एक नमूना लेनदेन की जांच की जानी चाहिए। हमारे फैसले में यह पालन करने के लिए पूरी तरह से गलत प्रक्रिया थी और सहायक आयुक्त, जिस पर कानून के अनुसार कर का आकलन करने का कर्तव्य था, प्रत्येक व्यक्तिगत लेनदेन की जांच करने के लिए बाध्य था और फिर यह तय करता था कि क्या यह एक अंतरराज्यीय बिक्री योग्य है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर लगाना।"

केल्विनेटर ओजे इंडिया लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (51), और अन्य में रिपोर्ट किए गए निर्णय, जिसका उल्लेख निर्णय के पहले भाग में किया गया है, विद्वान वकील के तर्क का समर्थन करते हैं।

(38) प्रासंगिक धाराओं से, जैसा कि हमने नोटिस किया है और जिन निर्णयों पर याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने भरोसा किया है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में चला गया है, तो धारा 3 के तहत एक प्रश्न उठता है। (ए) केंद्रीय अधिनियम के अनुसार, क्या माल की ऐसी आवाजाही अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री के कारण हुई थी और यदि ऐसा हुआ है, तो केंद्रीय अधिनियम के तहत एक दायित्व उत्पन्न होगा। यदि नहीं, तो ऐसी कोई देनदारी संभवतः उत्पन्न नहीं हो सकती। हम विद्वान वकील के इस तर्क से भी सहमत हैं कि जहां बिक्री के अलावा किसी अन्य तरीके से माल के हस्तांतरण का दावा किया जाता है, तो सबूत का बोझ डीलर द्वारा वसूला जाएगा यदि उसने निर्धारित सीमा के भीतर मूल्यांकन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया है। समय या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जब वह प्राधिकारी, पर्याप्त कारण के लिए, व्यवसाय के अन्य स्थान के प्रमुख अधिकारी या उसके एजेंट या प्रिंसिपल, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित विवरण सहित विधिवत भरी और हस्ताक्षरित घोषणा की अनुमति दे सकता है। निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र, ऐसे माल के प्रेषण के साक्ष्य के साथ, लेकिन इस न्यायालय के विचार में, यदि मूल्यांकन प्राधिकारी, उप-धारा (2) के तहत परिकल्पित की गई जांच पर, इस तरह के बोझ से मुक्त हो जाता है। धारा 6-ए के तहत, संतुष्ट है कि उप-धारा (1) के तहत डीलर द्वारा प्रस्तुत विवरण सत्य हैं तो केंद्रीय अधिनियम के तहत कोई कर देयता उत्पन्न नहीं होगी। सीपी में के.

(51) 32 एसटीसी 629.

ट्रेडिंग कंपनी बनाम अतिरिक्त बिक्री कर अधिकारी (52), यह माना गया है कि "वर्तमान मामले में, यह सामान्य आधार है कि अपीलकर्ता/डीलर ने घोषणाओं (एफ फॉर्म) के बिक्री विवरण प्रस्तुत किए हैं। जैसा कि हमने *विजयमोहिनी मिल्स मामले* (1989) 75 'एसटीसी (केर)' में कहा था; (1989), 1 केएलटी, 515, एफ फॉर्म के उत्पादन के बाद भी, यह मूल्यांकन प्राधिकारी के लिए खुला है कि वह खुद को संतुष्ट करने के लिए आगे की जांच कर सके कि घोषणा (एफ फॉर्म) में निहित विवरण "सही" हैं। इसके बाद ही, मूल्यांकन प्राधिकारी को मामले में आदेश पारित करने का आदेश दिया जाता है। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6ए(2) का एक स्पष्ट पाठ बताता है कि ऐसे मामलों में जहां डीलर घोषणा (एफ फॉर्म) प्रस्तुत करने के विकल्प का उपयोग करता है, एकमात्र अतिरिक्त आवश्यकता यह है कि मूल्यांकन करने के बाद मूल्यांकन प्राधिकारी संतुष्ट होना चाहिए। ऐसी जांच जिसे वह आवश्यक समझे, कि डीलर द्वारा प्रस्तुत घोषणा में शामिल विवरण "सत्य" हैं। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6ए(2) के तहत मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा जांच की सीमा का दायरा इस सीमा तक सीमित है, अर्थात् यह सत्यापित करने के लिए कि डीलर द्वारा प्रस्तुत घोषणा (एफ फॉर्म) में निहित विवरण सही हैं या नहीं। "सत्य"। इसका मतलब है कि मूल्यांकन प्राधिकारी यह पता लगाने के लिए जांच कर सकता है कि प्रस्तुत घोषणा में दिए गए विवरण सही हैं, या भरोसेमंद हैं, या तथ्यों के अनुरूप हैं या सटीक या वास्तविक हैं। केवल यही अधिनियम की धारा 6ए(2) द्वारा अपेक्षित जांच का दायरा है। ऐसी जांच के निष्कर्ष पर, उसे एक या दूसरे तरीके से एक निश्चित निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए। महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून की स्थिति, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अब निर्धारण प्राधिकारी के आदेशों की जांच करने और यह देखने के लिए स्पष्ट है कि क्या इसे कानून के अनुसार पारित किया गया है या ऐसे आदेश दिए गए हैं उन विचारों पर आधारित जो कानून के तहत विचाराधीन जांच से संबंधित नहीं हैं। आक्षेपित आदेश में. अनुलग्नक पी-194, दिनांक दिसंबर। 18. 1991. (1992 के सीडब्ल्यूपी 1898 से संबंधित) शाखा हस्तांतरण से निपटने के दौरान, मूल्यांकन अधिकारी ने पाया कि "डीलर ने प्रस्तुत किया था कि स्टोर का सामान पीएस के लायक था। 1,24,073.78 राज्य के भीतर से खरीदे गए (टैक्स की समाप्ति के बाद) और शेष स्टोर का सामान रु। 16 06 282.49 राज्य के बाहर से खरीदे गए थे क्योंकि इन्हें अन्य राज्यों में उनकी शाखाओं में पुनः खरीदा गया था। डीलर का लिखित उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्टोर का सामान उपभोग्य वस्तु है और उसका उपभोग केवल हिसार में तैयार माल के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है।

(52) 76 एसटीसी 211.

तैयार माल को अन्य शाखाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है, न कि राज्य के भीतर और राज्य के बाहर पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर अपने स्वयं के उपयोग के लिए खरीदी गई उपभोग्य सामग्रियों को। इस प्रकार के लेनदेन डीलर द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग के समान हैं। " निर्णय के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारे द्वारा चर्चा किए गए मामले को ध्यान में रखते हुए , शाखा हस्तांतरण को अंतर-राज्य मानने के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा दिए गए कारण बिक्री, पूरी तरह से गलत है। ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्यांकन प्राधिकारी ने कानून के प्रासंगिक प्रावधानों को बिल्कुल भी नहीं देखा था या, शायद, उसे दिखाया भी नहीं गया था। हरियाणा के बाहर बिक्री (खेप बिक्री) के अलावा अन्य हस्तांतरण से निपटने के दौरान, मूल्यांकन प्राधिकारी ने पाया कि "18 दिसंबर, 1991 के लिखित उत्तर के पैरा 2 में, डीलर ने उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों के विवरण का उल्लेख किया था। मद्रास और बॉम्बे में उपरोक्त फर्मों के अस्तित्व के संबंध में साक्ष्य के रूप में विभिन्न प्राधिकरण। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पहले, मूल्यांकन प्राधिकारी ने पाया था कि "डीलर वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेनदेन के समर्थन में कोई भी ठोस सबूत या दस्तावेजी साक्ष्य देने में विफल रहा, जैसा कि इन फर्मों को बताया गया था अस्तित्व में नहीं :—

1. मैसर्स जिंदल स्टील एजेंसी, मद्रास
2. मैसर्स ऑर्बिट स्टील (इंडिया) लिमिटेड, बॉम्बे

Total Rs. 25,34,75,734

Sr. No. Name of the consignee	Amount
-------------------------------	--------

<p>यह उस संबंध में है कि याचिकाकर्ता कंपनी ने जवाब में बॉम्बे और मद्रास में फर्मों के अस्तित्व के संबंध में विभिन्न प्राधिकरणों से प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों के विवरण का उल्लेख किया था। मूल्यांकन प्राधिकारी ने माना कि "दस्तावेजों की प्रतियों की जांच की गई है और इन फर्मों के अस्तित्व के संबंध में डीलर द्वारा प्रस्तुत सहायक साक्ष्य पर जोर दिया गया है "। "हालांकि, यह भी देखा गया कि उपरोक्त फर्मों की वास्तविकता की जांच करते समय, उनके पास भंडारण सुविधा के पहलुओं की भी जांच की गई, जो कुछ लोगों की ओर से एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक थे और कंसाइनी फर्म इस संबंध में कोई सबूत देने में विफल रहे। मडियास में व्यवसाय के स्थानों पर उनके स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए गोदाम आदि</p> <p>बॉम्बे" आगे यह देखा गया कि "बॉम्बे फर्म के मामले में उक्त फर्म के प्रतिनिधि के हलफनामे से पता चलता है कि माल क्रमशः हिसार से प्राप्त किया गया था और हिसार से बॉम्बे भेजा गया था, लेकिन फर्म द्वारा प्रस्तुत फॉर्म एफ की सूची में दिखाया गया था नई दिल्ली से माल का प्रेषण और इस प्रकार, माल की आवाजाही के स्थान के संबंध में हलफनामे में की गई पुष्टि में विरोधाभास था। अंत में यह देखा गया कि "जब पूरे भारत के लिए स्थानांतरण सुविधाएं हिसार (फर्म के व्यवसाय का स्थान) पर उपलब्ध थीं, तो इस मामले में माल को उन परिवहन कंपनियों से बॉम्बे ले जाया गया था जो हिसार में मौजूद नहीं थीं।" हमें डर है कि मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा दिए गए कारणों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर सके कि इस तरह के हस्तांतरण केवल देश में स्थित विभिन्न राज्यों के एजेंटों के साथ-साथ मद्रास और बॉम्बे में इसके एजेंटों के लिए भी थे। मूल्यांकन प्राधिकारी को, विषय से संबंधित कानून को</p>	<p>Rs. 18,89,37 392</p>
--	-----------------------------

ध्यान में रखते हुए और जिसकी ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है, याचिकाकर्ता कंपनी या उसके एजेंटों द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्रों पर विचार करना आवश्यक था। यदि प्रपत्रों में दिए गए विवरण सही पाए गए, तो मूल्यांकन प्राधिकारी को मामले में आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि मूल्यांकन करने वाला प्राधिकारी जांच करने के लिए केंद्रीय अधिनियम की धारा 6-ए के प्रावधानों के तहत अपने अधिकारों के तहत अच्छी तरह से काम कर रहा होगा। यह फिर से उसके अधिकार में होता कि वह निर्धारिती से सभी घोषणा पत्र प्रस्तुत करने और उसमें की गई प्रविष्टियों की जांच करने के लिए कहता और यदि वह गलत या असंगत पाया जाता या कुछ ओवर-लैपिंग होती, तो निर्धारिती को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। यह साबित करने का एक और मौका कि घोषणा पत्र के माध्यम से भेजा गया सामान वास्तविक था! एजेंटों को भेजा गया माल, न कि अंतर-राज्यीय बिक्री। हालाँकि, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था और आदेश उन आधारों पर पारित किए गए थे जो केंद्रीय अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत जांच के लिए उपयुक्त नहीं थे। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि नेटीशनर कंपनी को अपने संस्करण को प्रमाणित करने के लिए दिसंबर आईक्यू 1991 को नोटिस जारी किया गया था कि लेनदेन टर्न-ओवर से कटौती के लिए डीलर को हकदार बनाता है। 17 दिसंबर 1991 को याचिकाकर्ता कोमोनी ने दावे को प्रमाणित करने में अपनी असमर्थता दिखाते हुए प्रतिकृति दायर की थी। इसके अनुसार . 10 दिसंबर 1991 के नोटिस में आपत्ति का विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया । इसके बाद यह हुआ कि 17 दिसंबर, 1991 को मामले की जांच की गई और याचिकाकर्ता कॉमननव द्वारा दायर किए गए आगे के जवाब पर विचार किया गया और 18 दिसंबर, 1991 को विवादित आदेश पारित किए गए, जिससे सीडब्ल्यूपी संख्या 1898 को जन्म दिया गया। जहां तक अन्य दो मूल्यांकन आदेशों का संबंध है, यह फिर से देखा जाएगा कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा कारण बताने के लिए निर्धारित तिथि 1 मई, 1992 थी और याचिकाकर्ता कंपनी ने निर्धारित तिथि पर भारी दस्तावेजों के साथ अपना जवाब दाखिल किया था। 1 मई 1992। इसी दिन 1992 के सीडब्ल्यूपी नंबर 5864 को जन्म देने वाले आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी-715 पारित किए गए थे। इसी तरह, निर्धारिती को 18 फरवरी, 1993 को नोटिस जारी किया गया था और वह तारीख, जब मामला मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष तय किया गया था, 18 फरवरी, 1993 थी। इसी तारीख को याचिकाकर्ता ने अपना जवाब दाखिल किया था और यह उसी तारीख को है। कि 1993 के सीडब्ल्यूपी संख्या 5404 को जन्म देने वाले आक्षेपित आदेश, अनुबंध पी-29, पारित किए गए थे।

(39) तत्कालीन तरीके से जो कि मूल्यांकनकर्ता प्राधिकरण (पहले से ही) - इस मामले में आगे बढ़ा, हमारे विचार को और मजबूत करता है कि शाखा हस्तांतरण या एजेंटों को खेप के रूप में विभिन्न लेनदेन का निर्धारण करने के उद्देश्य से इन मामलों में जो कारक प्रासंगिक थे या जो अंतरराज्यीय बिक्री थे, वे थे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। 1 मई 1992 के आक्षेपित आदेशों (1992 के सीडब्ल्यूपी 5864 को जन्म देते हुए) में मूल्यांकन प्राधिकारी थोड़ा अधिक उदार रहा है और 18 दिसंबर 1991 के आक्षेपित आदेशों में दिए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों का भी उल्लेख किया गया है। शाखा स्थानान्तरण पर विचार करते समय, यह देखा गया कि "यह लोगों को अच्छा नहीं लगता कि मेसर्स जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड, हिसार जैसी कंपनी, जिसका प्रबंधन अत्यधिक कुशल और योग्य कर्मियों द्वारा किया जाता है, परिवहन के लिए भारी-भरकम (आवश्यक) खर्च उठाएगी।" हरियाणा राज्य के बाहर से सीधे माल लाकर, फिर चुंगी, उतराई, भंडारण, रख-रखाव और फिर हरियाणा राज्य के बाहर अपनी शाखाओं में माल भेजने

के दौरान लोडिंग, परिवहन और चुंगी आदि पर खर्च करना। आगे देखा गया कि "यदि सामान वास्तव में उनकी शाखाओं के लिए था, तो इन सामानों को शाखाओं द्वारा सीधे खरीदा जा सकता था, इस प्रकार, हिसार कार्यालय द्वारा किए गए अनावश्यक खर्चों को बचाया जा सकता था।" यह भी देखा गया कि "वहां विसंगतियां थीं और दी गई जानकारी और उत्पादित खातों में हेरफेर जो सत्यापन और जांच के परीक्षण का सामना नहीं कर सके, इसलिए मूल्यांकन को नोट किए गए और सत्यापित तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, जो डीलर द्वारा उत्पादित खातों पर प्राप्त नहीं होता है। हमें डर है, ये फिर से वे आधार नहीं थे जिनके आधार पर मूल्यांकन प्राधिकारी को आगे बढ़ना चाहिए था। आकलन करने वाले लेखक! टीवी के सामने असली मुद्दा यह था कि क्या शाखाओं को भेजी गई वस्तुएँ ऐसी थीं जिनका उपभोग उक्त शाखाओं द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया में किया जा सकता था। विवादित आदेशों में कहा गया है कि लेनदेन यानी शाखा हस्तांतरण को अंतर-राज्यीय बिक्री नहीं माना जा सकता है। प्रत्येक संदिग्ध वस्तु पर महत्वपूर्ण उत्तर देने के लिए विचार किया जाना चाहिए

परीक्षण यानी कि क्या ऐसी वस्तु विनिर्माण प्रक्रिया में उपभोग योग्य थी। मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा बताया गए आधार पर हम बहुत आसानी से आदेशों को रद्द कर देते और सीधे इन रिट याचिकाओं को अनुमति दे देते, लेकिन बहस की प्रक्रिया में, हमें बड़े पैमाने पर दस्तावेज और आइटम, शाखा हस्तांतरण के विषय वस्तु, जिनमें एयर भी शामिल थे, दिखाए गए। कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और समान रूप से और हरियाणा के महाधिवक्ता द्वारा उत्तरदाताओं की ओर से रिट याचिकाओं का विरोध करते हुए दृढ़ता से तर्क दिया जा रहा है कि ऐसी वस्तुओं का संभवतः विनिर्माण प्रक्रिया में उपभोग नहीं किया जा सकता है। हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिखाए गए एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या अन्य वस्तुओं का विनिर्माण प्रक्रिया में उपभोग किया जा सकता है या नहीं, यह एक तथ्य का प्रश्न है और हम पहले ही राय दे चुके हैं कि मूल्यांकन प्राधिकारी, इससे बहुत दूर हैं इसके समक्ष वास्तविक मुद्दे की जांच करते हुए, शाखा हस्तांतरण को उन आधारों पर अंतर-राज्यीय बिक्री माना गया जो टिकाऊ नहीं हैं।

(40) जबकि कंसाइनमेंट्स की बिक्री के साथ डील करते समय, मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा यह कहा गया था कि "कंसाइनमेंट बिक्री के लिए कटौती की विस्तार से जांच की गई थी और रुपये की वास्तविक कंसाइनमेंट बिक्री के कारण कटौती की गई थी। 38,69,23,402 की अनुमति दी गई थी, जबकि शेष बिक्री इस आधार पर अंतर-राज्य बिक्री थी कि सत्यापन पर यह पाया गया कि हिसार से माल का पूरा टुक लोड पूर्व अनुबंध का परिणाम था और इसे अंतिम खरीदारों तक पहुंचाया गया था। वहीं वाहन. कंसाइनमेंट एजेंटों द्वारा दिए गए बिलों में आरआर/जीआर नंबर, वाहन नंबर, परिवहन कंपनी का नाम या परिवहन का तरीका नहीं था, जबकि उनके बिलों में आरआर और प्रेषण के तरीके आदि के बारे में कॉलम दिए गए थे। यह जानकारी बिलों पर जानबूझकर नहीं दिया गया था क्योंकि यह जानकारी देने से अंतर-राज्य बिक्री को कंसाइनमेंट बिक्री के रूप में छिपाने की *कार्यप्रणाली बिल्कुल स्पष्ट हो सकती थी।*" आगे यह भी देखा गया कि "साथ ही, कंसाइनमेंट एजेंट द्वारा उठाए गए बिलों पर लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडिंग, भंडारण, परिवहन डिलीवरी और अन्य खर्चों के शुल्क का कोई उल्लेख नहीं था, यह दर्शाता है कि ऐसे कोई खर्च नहीं थे क्योंकि माल सीधे वितरित किया गया था।" मेसर्स जिंदल स्टील्स लिमिटेड, हिसार से अंतिम खरीदारों के लिए। आगे यह देखा गया कि "अन्य कंसाइनमेंट एजेंटों द्वारा दिखाई गई बिक्री के मामले भी ऐसे ही थे। दरअसल, खरीदारों को सामान उसी वाहन से और उसी मात्रा में वितरित किया गया था, जिस वाहन ने जिंदल स्टील्स लिमिटेड, हिसार से माल की डिलीवरी ली थी, लेकिन अंतर-राज्य बिक्री को कंसाइनमेंट बिक्री के रूप में छिपाने के लिए हेरफेर किया गया था। केवल दो बिल उठाकर किया गया, जिसके उदाहरण मूल्यांकन आदेश में दिए गए थे। मेसर्स स्वास्टिक सेल्स कॉर्पोरेशन राशन, अहमदाबाद और अन्य कंसाइनमेंट एजेंटों के मामले में भी, कुछ ऐसे बिक्री के पूर्व-मौजूदा अनुबंध के अनुसरण में माल ले जाया गया था।" यहां आक्षेपित आदेश में कुछ अन्य कारण भी दिए गए हैं, जिन्हें हम विस्तार से नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे विचार में, जहां तक एजेंटों को खेप का संबंध है, निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या माल दूसरे देश में ले जाया गया था। पूर्व अनुबंध के अनुसरण में एजेंटों को राज्य। यह सच है कि आक्षेपित आदेश में दिए गए विभिन्न उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रेषण बिक्री के पूर्व-मौजूदा अनुबंध के परिणामस्वरूप और अनुसरण में किए गए थे और यह भी सच है कि कुछ घोषणा प्रपत्रों में या तो प्रस्तुत किया गया था याचिकाकर्ता कंपनी या उसके एजेंटों के लिए उल्लिखित आवश्यक विवरण सही नहीं पाए गए, लेकिन, इस मामले में भी निर्धारित को यह साबित करने का उचित अवसर नहीं दिया गया कि घोषणा प्रपत्रों में विसंगतियों के संबंध में यह एक यह साबित करने की स्थिति कि लेन-देन उसके एजेंटों के लिए महज खेप थी, न कि अंतर-

राज्यीय बिक्री और वास्तव में माल बिना किसी पूर्व-मौजूदा अनुबंध के हिसार से दूसरे राज्यों में चला गया। ऐसे हजारों मुद्दे हैं जिन पर तथ्यों पर विवाद है और यह न्यायालय इन मुद्दों पर विचार करने और उन पर स्वतंत्र रूप से फैसला देने के लिए तैयार नहीं है।

(41) 18 दिसंबर, 1991 (1992 के सीडब्ल्यूपी 1898 को जन्म देते हुए) के आक्षेपित आदेशों में ई-असेसिंग अथॉरिटी द्वारा विस्तृत कारण ऐसे हैं कि उनके आधार पर, एक या दूसरे तरीके से, कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा सकता है। 1 मई, 1992 के आक्षेपित आदेश (1992 के सीडब्ल्यूपी 5864 को जन्म देते हुए) के बारे में भी यही सच है। पार्टियों के बीच विवाद का निर्धारण करना प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नेटिशनकर्ता को अपना मामला साबित करने के लिए उचित अवसर नहीं दिया गया था। जहां तक 18 फरवरी 1993 के आक्षेपित आदेश (1993 के सीडब्ल्यूपी संख्या 5404 को जन्म देते हुए) का संबंध है, पार्टियों के विद्वान वकील ने किसी भी अतिरिक्त आधार पर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, हमारे पास शायद विवादित आदेशों, अनुबंध पी-194 (1992 के सीडब्ल्यूपी संख्या 1898 में), अनुबंध पी-715 (1992 के सीडब्ल्यूपी संख्या 5864 में) और अनुबंध पी29 को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। (1993 के सीडब्ल्यूपी नंबर 5404 में) और पूरे मुद्दे को फिर से खोलने और हमारे द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर शामिल विवाद का फैसला करने के लिए मामले को मूल्यांकन प्राधिकारी को भेज दें क्योंकि यह शाखा हस्तांतरण और एजेंटों को खेप से संबंधित है। हम निर्देश देते हैं कि मूल्यांकन प्राधिकारी ऊपर बताए गए कानून के प्रस्ताव को ध्यान में रखेगा और अंतर-राज्यीय बिक्री, शाखा हस्तांतरण या एजेंटों को खेप होने के संदेह वाले प्रत्येक आइटम और हमारे द्वारा निर्धारित कानून के मापदंडों पर निपटेगा।, इसे या तो होने के लिए पकड़ी

शाखा स्थानांतरण, एजेंटों को खेप या अंतरराज्यीय बिक्री, जैसा भी मामला हो। हम आगे निर्देश देते हैं कि इस मामले को हिसार जिले के अलावा अन्य जिले में उच्चतम कर प्राधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा। यह आदेश केवल उन संदेहों को दूर करने के उद्देश्य से दिया जा रहा है जो श्री जिंदल ने मूल्यांकन अधिकारियों और विशेष रूप से श्री आरएस शर्मा के संबंध में व्यक्त किए हैं, जिनके बारे में यह तर्क दिया जा रहा है कि कमल में एक आवासीय भूखंड दिया गया है। आक्षेपित आदेशों को पारित करने के लिए, इस अधिकतम सीमा पर कि न केवल न्याय किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है और इसके बिना भी, अदालत ने संबंधित अधिकारियों की ईमानदारी के खिलाफ संदेह पैदा किया है।

(42) जहां तक मुख्य मंत्री के खिलाफ दुर्भावना का आरोप है, श्री ओपी जिंदल की नाराजगी है। याचिकाकर्ता कंपनी के अध्यक्ष का कहना है कि जब से श्री भजन लाई ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद संभाला है, उन्होंने मुख्यमंत्री के एक समर्थक को हराने के कारण उन्हें आर्थिक और अन्यथा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्हें, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य सहयोगियों को विभिन्न आपराधिक मामलों में शामिल करके भी। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता कंपनी दो दशकों से अधिक समय से व्यवसाय में है और किसी भी समय इसकी साख पर कर चोरी का संदेह नहीं था और न ही ऐसा कोई आदेश पारित किया गया था और यह पहली बार है कि बीस करोड़ से अधिक की भारी देनदारी हुई है। श्री ओपी जिंदल के प्रति मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्त की गई नाराजगी के कारण इस पर रोक लगाई गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री शांति भूषण द्वारा यह भी दलील दी गई और तर्क दिया गया कि व्यावहारिक रूप से सभी मोर्चों पर कंपनी, उसके पदाधिकारियों और श्री ओपी जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि 26 जून 1991 को श्री भजन लाई ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। 30 जून 1991 को याचिकाकर्ता कंपनी से जुड़े ट्रकों की आवाजाही को सरकार समर्थित ट्रक यूनियन और स्थानीय प्रशासन द्वारा बाधित किया गया था। 2 जुलाई, 1991 को ट्रकों की आवाजाही के संबंध में सिविल मुकदमे दायर किए गए और हिसार में सिविल न्यायालयों द्वारा निषेधाज्ञा दी गई। 8 जुलाई, 1991 को हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने बिजली लाइन को काट दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ता कंपनी के डीसी सेटों द्वारा उत्पन्न बिजली का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई। इस प्रकार, कंपनी को सिविल मुकदमा दायर करना पड़ा और सिविल कोर्ट द्वारा निषेधाज्ञा दी गई। 16 जुलाई, 1991 को याचिकाकर्ता कंपनी की औद्योगिक इकाई, स्टाफ सदस्यों और मजदूरों की आवासीय कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति काट दी गई, जिसके बाद सिविल मुकदमा दायर किया गया, जिसमें सिविल कोर्ट, हिसार द्वारा निषेधाज्ञा भी दी गई। 18 जुलाई, 1991 को श्री ओपी जिंदल के राजनीतिक समर्थकों के ट्रकों की आवाजाही में बाधा डाली गई, जिसके बाद सिविल मुकदमा दायर किया गया और

सिविल कोर्ट द्वारा सरकार समर्थित ट्रक यूनियन और डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों सहित स्थानीय प्रशासन के खिलाफ निषेधाज्ञा दी गई। 28 जुलाई, 1991 को म्यूनिसिपल कमेटी, हिसार ने नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता कंपनी को 24 घंटे के भीतर चुंगी राशि जमा करने का निर्देश दिया, जो कि सिविल रिवीजन में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन है, जिसमें राशि जमा करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया था। 30 जुलाई 1991 को, एचएसईबी ने याचिकाकर्ता कंपनी को दो दिनों के भीतर बिजली के समानांतर संचालन प्रणाली के /नेटर उपकरण को बदलने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता को फिर से सिविल मुकदमा दायर करना पड़ा। 2 अगस्त 1991 को सरकार समर्थित ट्रक यूनियन और स्थानीय प्रशासन ने न्यायालय द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप अवमानना याचिका दायर की गई। 7 अगस्त 1991 को कोर्ट ने डीसी, एसपी

और अन्य पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उनका वेतन कुर्क कर लिया जाए. 7 अगस्त 1991 को तीन एफ.आई.आर. श्री ओपी जिंदल, उनके बेटों और कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और टाडा के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। 9 अगस्त 1991 को कंपनी के 29 कर्मचारियों को फैक्ट्री परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अगस्त, 1991 को जिला मजिस्ट्रेट, हिसार द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश पारित किए गए, जिसमें ट्रकों के जमावड़े और आवाजाही पर रोक लगा दी गई। 13 अगस्त 1991 को श्री ओपी जिंदल और उनके बेटों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई। 13 अगस्त, 1991 को उपरोक्त एफटीआर को रद्द करने के लिए एक आपराधिक रिट याचिका दायर की गई थी। 20 अगस्त 1991 को याचिकाकर्ता कंपनी के 29 कर्मचारियों को, जिन्हें 9 अगस्त 1991 को गिरफ्तार किया गया था, अदालत ने जमानत दे दी। 2 सितंबर 1991 को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने याचिकाकर्ता कंपनी को वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत इसे बंद करने का नोटिस जारी किया। एक सिविल मुकदमा दायर किया गया था. 16 सितंबर 1991 को प्रदूषण बोर्ड ने याचिकाकर्ता कंपनी को जल प्रदूषण अधिनियम के तहत औद्योगिक इकाई बंद करने का नोटिस जारी किया। फिर से एक सिविल मुकदमा दायर किया गया। 3 अक्टूबर, 1991 को बिक्री कर अधिकारियों द्वारा श्री ओपी जिंदल के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों पर छापा मारा गया। इसके बाद विवादित आदेशों को पारित करने के संबंध में इतिहास दिया गया है और बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सिविल रिट याचिकाओं के माध्यम से इसे इस न्यायालय में कैसे चुनौती दी गई थी। ट्रकों को रोकने के मामले में राज्य, पुलिस अधिकारियों और मुख्यमंत्री के खिलाफ 29 अगस्त, 1992 को एक रिट याचिका दायर की गई थी और इस न्यायालय द्वारा स्टे दे दिया गया था। कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर अवमानना याचिका भी दायर की गई. 20 फरवरी 1993 को जनता ट्रक यूनियन, हिसार के कार्यालय पर पुलिस बल के साथ-साथ असामाजिक तत्वों द्वारा गोलीबारी की गई। 26 फरवरी, 1993 को कंपनी के माल से लदे सात ट्रकों को पुलिस की मदद से असामाजिक तत्वों ने हिरासत में ले लिया। **जिक्र** भी है कुछ अन्य आपराधिक शिकायतों तथा 25 मार्च, 1993 को असामाजिक तत्वों द्वारा गोलीबारी की।

(43) पार्टियों की श्रृंखला से, यह देखा जा सकता है कि केवल आरएस शर्मा, उप उत्पाद एवं कराराधान आयुक्त, हिसार और भजन लाई, मुख्यमंत्री, हरियाणा को प्रतिवादी के रूप में रखा गया है। उत्तरदाताओं 1, 2 और 4 की ओर से दायर लिखित बयान में इन आरोपों से इनकार किया गया है कि मुख्यमंत्री के कहने पर विवादित आदेश पारित किए गए थे। प्रतिवादी नंबर 3- श्री भजन लाई द्वारा दायर लिखित बयान में यह दलील दी गई है कि झूठे और *दुर्भावनापूर्ण* आरोप लगाए गए हैं कि याचिकाकर्ता कंपनी को कर के दायरे में लाने के लिए प्रतिवादी द्वारा मूल्यांकन प्राधिकारी को कोई निर्देश नहीं दिया गया था। यह कहा गया है कि कानून के अनुसार मूल्यांकन करना मूल्यांकन प्राधिकारी का कर्तव्य है और याचिकाकर्ताओं के पास ट्रिब्यूनल तक अपील और उच्च न्यायालय के संदर्भ के माध्यम से आदेश के खिलाफ उपाय था। आगे कहा गया है कि चूंकि श्री जिंदल प्रतिवादी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, इसलिए वह कर की देनदारी से बचने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। यदि उसने किसी कानून के तहत कोई अपराध किया है या किसी कानून का उल्लंघन किया है, तो राज्य के अधिकारी इससे निपटने में सक्षम हैं और कानून के अनुसार संबंधित व्यक्ति के लिए उपचार समान रूप से उपलब्ध हैं। प्रशासन या ट्रक यूनियनों द्वारा याचिकाकर्ता कंपनी या उसके अध्यक्ष और उनके दोस्तों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए विभिन्न मामलों में मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोपों का खंडन किया गया है।

(44) किसी भी याचिका में, प्राधिकरण, चाहे वह बिजली बोर्ड, पुलिस विभाग या प्रदूषण बोर्ड और अन्य के अधीन हो, को पक्ष-प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह केवल श्री आरएस शर्मा, डीईटीसी, हिसार और श्री भजन लाई हैं, जिन्हें पार्टी-प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चीजों की प्रकृति से, यह विशेष रूप से यह कहकर *दुर्भावना का अनुमान लगाने का मामला* है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय संचालने के तुरंत बाद कार्रवाई की श्रृंखला महज एक संयोग नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में, *दुर्भावना* का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों से, यह तर्क दिया गया है कि *दुर्भावना* संदेह की छाया से परे साबित हुई है।

(45) हमें डर है कि *दुर्भावना के किसी भी निष्कर्ष को केवल संभावनाओं के आधार पर* वापस नहीं किया जा सकता है और न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण और मजबूत है कि *दुर्भावना के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष को दर्ज करने की* आवश्यकता नहीं है। एक खोज कि एक विशेष

कार्रवाई या आदेश बाहरी विचारों पर लिया या पारित किया जा सकता है, इस प्रकार, वह केवल तभी वापस लौटा जब अन्य सभी परिकल्पनाओं को बाहर रखा गया क्योंकि *दुर्भावना* को साबित करना एक *आपराधिक* आरोप की तरह है और इसे संदेह की छाया से परे साबित करना होगा। *ए. परियाकरुप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य (53)* में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि "केवल सकारात्मक बातें *दुर्भावना* की याचिका का आधार नहीं बन सकतीं।" उपरोक्त मामले में *दुर्भावना* के आरोपों को इस तथ्य से उजागर करने की कोशिश की गई थी कि कई छात्र, जिन्होंने लिखित परीक्षा में बहुत खराब प्रदर्शन किया था, ने साक्षात्कार में बहुत उच्च अंक हासिल किए थे। उक्त मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया गया था कि साक्षात्कार के अंक संपार्श्विक विचार-विमर्श पर आवंटित किए गए थे और चयन समितियां सरकार के हाथों में उपकरण थीं और सरकार ने अंकों में इस तरह से हेरफेर किया ताकि सुविधा प्रदान की जा सके। उन छात्रों का चयन जिनमें सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों की रुचि थी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आरोपों का उत्तरदाताओं ने खंडन किया है। *दुर्भावना* की दलील पर अपने तर्कों की विस्तृत रेटिंग करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान अंक सूचियों की ओर आकर्षित किया था, जो स्पष्ट रूप से दिखाती है कि साक्षात्कार में दिए गए अंक बड़े पैमाने पर विपरीत अनुपात में थे। विश्वविद्यालय परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक। आगे यह तर्क दिया गया कि उनके चेहरे पर अंक सूची से पता चलेगा कि साक्षात्कार के अंकों में हेरफेर किया गया था। याचिकाकर्ताओं की उपरोक्त दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“हालाँकि इन आलोचनाओं के लिए कुछ आधार हैं, लेकिन हमारे सामने कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकें कि ग्रेडेशन सूची तैयार करने में कोई हेरफेर हुआ था। यह सच है कि कई छात्र जिनका विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रदर्शन न तो बहुत संतोषजनक था और न ही उनके पिछले रिकॉर्ड विश्वसनीय थे, उन्होंने साक्षात्कार में बहुत उच्च अंक प्राप्त किए थे। यह भी सच है कि बड़ी संख्या में ऐसे छात्र जिन्होंने विश्वविद्यालय परीक्षा में बहुत अधिक अंक प्राप्त किए थे और जिनका पिछली कक्षाओं में प्रदर्शन बहुत अच्छा था, उन्हें साक्षात्कार में बहुत कम अंक मिले थे। ये परिस्थितियाँ निस्संदेह परेशान करने वाली हैं लेकिन अदालतें महज संभावनाओं के आधार पर *दुर्भावना की दलील को बरकरार नहीं रख*

सकतीं हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि कोई भी जिम्मेदार सरकार अंकों में हेरफेर करने पर उतारू हो जाएगी।”

(53) एआईआर 1971 एससी 2303,

(46) *ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (54)* मामले में, यह माना गया था कि " *दुर्भावना* स्थापित करने का बोझ उस व्यक्ति पर बहुत भारी है जो इसका आरोप लगाता है। *दुर्भावना* के आरोप अक्सर साबित होने की बजाय आसानी से लगाए जाते हैं, और ऐसे आरोपों की गंभीरता उच्च स्तर की विश्वसनीयता के प्रमाण की मांग करती है। उपरोक्त रिपोर्ट में लगाया गया आदेश याचिकाकर्ता का स्थानांतरण आदेश था, जो राज्य का मुख्य सचिव था और मुख्यमंत्री के खिलाफ *दुर्भावना* के आरोप लगाए गए थे। मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, यह आगे माना गया कि "ये और कुछ अन्य परिस्थितियाँ संदेह पैदा करती हैं, लेकिन संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता है और, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यहाँ आवश्यक सबूत उच्च स्तर का सबूत है। हम यह नहीं कह सकते कि वर्तमान मामले में *दुर्भावना की दलील को बरकरार रखने में न्यायिक विश्वसनीयता पैदा करने वाले साक्ष्य हमारे सामने रखे गए हैं।*" इसलिए, हमें याचिकाकर्ता के इस तर्क को भी खारिज करना चाहिए।"

(47) *एम. शंकरनारायणन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (55)* मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि "वास्तव में पूर्ण और विस्तृत विवरण के साथ द्वेष प्रदर्शित करना हमेशा संभव नहीं हो सकता है और उचित मामले में उचित निष्कर्ष निकालने की अनुमति दी जा सकती है।" प्रस्तुत तथ्यों से *दुर्भावना* का अनुमान लगाया गया और स्थापित किया गया। लेकिन ऐसा अनुमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर आधारित होना चाहिए और ऐसा तथ्यात्मक मैट्रिक्स संकेत, संदेह या अनुमान के दायरे में नहीं रह सकता है। ऐसी कोई पर्याप्त सामग्री नहीं थी जिससे स्थानांतरण के विवादित आदेश को पारित करने के लिए वास्तव में द्वेष का उचित अनुमान लगाया जा सके।" उपरोक्त मामले में, विवादित आदेश फिर से एक स्थानांतरण आदेश था और याचिकाकर्ता का आरोप था कि यह *दुर्भावना* के कारण किया गया था क्योंकि वरिष्ठ नौकरशाहों की पोस्टिंग के मामले में मुख्य सचिव के सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चूंकि याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री के सभी सुझावों को स्वीकार करने और उस पर नोट्स लगाने के लिए सहमत नहीं था, इसलिए उसे मुख्यमंत्री की नाराजगी का सामना करना पड़ा।

(48) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री शांति भूषण ने हालांकि दृढ़ता से तर्क दिया कि परिस्थितियों की श्रृंखला और याचिकाकर्ता कंपनी, श्री ओपी जिंदल और अन्य के खिलाफ शुरू की गई विभिन्न कार्यवाहियों से, मुख्यमंत्री के खिलाफ *दुर्भावना* का एक अनूठा निष्कर्ष निकलता है। अच्छी तरह से खींचा जा सकता है। वह

(54) एआईआर 1974 एससी 555।

(55) (1993) 1 एससीसी 54।

दलील दी गई है कि दुर्भावनापूर्ण आरोपों पर विचार करते समय, *प्रत्येक आरोप को अलग से नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि यह पता लगाने के लिए सभी आरोपों को एक साथ देखना होगा कि क्या ऐसे आरोप लगाए गए हैं और क्या ऐसे आरोप, यदि स्थापित हैं, तो सही हैं।* मुख्यमंत्री की ओर से द्वेष या दुर्भावना साबित करने के लिए पर्याप्त है। वह *हरियाणा राज्य और अन्य बनाम राजेंद्र सरिन (56)* मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत कानून के प्रस्ताव से कोई झगड़ा नहीं हो सकता। हालांकि, यह मामला ऐसा नहीं है जिसमें विभिन्न प्रकार के आरोप हो सकते हैं और जैसा कि ऊपर विस्तृत रूप से बताया गया है, एकमात्र आरोप यह है कि मुख्यमंत्री ने याचिकाकर्ता कंपनी, श्री ओपी जिंदल और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की है और उन्हें शामिल किया है। श्री ओपी जिंदल द्वारा विधानसभा चुनावों में श्री भजन लाई के शिष्य को हराने के कारण प्रतिशोध लेने की दृष्टि से सभी

संभावित मोर्चों पर विविध मुकदमेबाजी में। यह सच है कि कंपनी वास्तव में कई मोर्चों, नागरिक, आपराधिक राजस्व और अन्य पर मुकदमेबाजी में शामिल है, लेकिन क्या न्यायालय, उसके सामने उपलब्ध सामग्री के आधार पर, सकारात्मक निष्कर्ष निकाल सकता है कि कंपनी को इन सभी मामलों को शुरू करना या बचाव करना था, क्या इस कारण से कि विभिन्न मामलों से निपटने वाले अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया था? हमें डर है कि ऐसी खोज को रिकॉर्ड करना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया है कि विभिन्न अधिकारियों ने उनके द्वारा जारी आदेशों पर या उनके इशारे पर याचिकाकर्ता कंपनी और अन्य के खिलाफ पूर्वाग्रह से कार्रवाई की। विभिन्न मामलों से निपटने वाले किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को पक्ष-प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। विभिन्न कार्यवाहियों, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, अभी भी लंबित हैं। याचिकाकर्ता कंपनी ने अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया होगा, जैसा कि पेश करने की मांग की जा रही है, लेकिन यह स्वीकार किया गया है कि आज तक किसी भी मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है, जिससे यह पता चल सके कि कार्यवाही, अदालती मामलों की विषय वस्तु, अनुचित थे या अन-जू दबा दिए गए थे। इस प्रकार, ऐसे अधिकारियों/अधिकारियों के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि या खंडन करने का कोई अवसर नहीं उठता है। चीजों की प्रकृति को देखते हुए कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी निश्चित रूप से कई अधिकारियों की बात सुने बिना उनकी निंदा करने के समान होगी। इसके अलावा, इस न्यायालय को यह विश्वसनीय नहीं लगता कि सभी अधिकारी मुख्यमंत्री द्वारा जारी निर्देशों के प्रति लचीले और उत्तरदायी थे। इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों की निष्ठा पर संदेह नहीं किया जा सकता और उनकी निंदा करना उचित नहीं होगा और वह भी उनकी बात सुने बिना. श्री ओपी जिंदल आश्वस्त हो सकते हैं कि उनके और याचिकाकर्ता कंपनी के साथ क्या किया गया है

(56) एआईआर 1972 एससी 1004।

अर्न कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 391
(आरएस मोंगिया, जे.)

M/s Jindal Strips limit I ed through Shri Sham Lai Gupta and 67

मुख्यमंत्री का उदाहरण लेकिन उनके आंशिक संदेह पैदा करने से आगे नहीं बढ़ते और यह स्थापित कानून है कि संदेह, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता। इस प्रकार, *दुर्भावना* की याचिका खारिज करने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।

(49) ऊपर दर्ज की गई चीख-पुकार के लिए 300 सेट रिट याचिकाएँ आंशिक रूप से स्वीकृत हैं। विवादित आदेश, अनुबंध पी-194 (1992 के सीडब्ल्यूपी 1898 में), अनुबंध पी-715 (1992 के सीडब्ल्यूपी 5864 में) और अनुबंध पी-29 (1993 के सीडब्ल्यूपी 5404 में) को अलग रखा जाता है। इन सभी मामलों को पूरे मामले को फिर से खोलने और शाखा हस्तांतरण और एजेंटों को खेप दोनों के संबंध में हमारे द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर शामिल विवाद का फैसला करने के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी को भेजा जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सहायता प्राधिकारी कानून के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पार्टियों के बीच उपरोक्त विवादास्पद मुद्दों पर निर्णय करेगा और पैरा- पर अंतर-राज्यीय बिक्री, शाखा हस्तांतरण या एजेंटों को खेप होने के संदेह वाले प्रत्येक आइटम से निपटेगा। हमारे द्वारा निर्धारित कानून के मीटर। मामला, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हिसार जिले के अलावा अन्य जिले में सर्वोच्च कर प्राधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा। हालाँकि, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय केवल वादकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह इसे अपनी भाषा में समझ सके और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी न्यायिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हिमानी सागर

प्रशिक्षित न्याय अधिकारी, हरियाणा